खण्ड-07 सत्र-05 (भाग-02) / अंक-71

बृहस्पतिवार 26 सितम्बर, 2024 / 04 अश्विन, 1946 (शक)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्यमेव जयते

सातवीं विधान सभा

पाँचवां सत्र

अधिकृत विवरण

(खण्ड-07, सत्र-5 (भाग-02) में अंक 71 से 72 तक सम्मिलित हैं।)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सम्पादक वर्ग

EDITORIAL BOARD

रंजीत सिंह

सचिव

RANJEET SINGH

Secretary

महेन्द्र गुप्ता

उप-सचिव (सम्पादन)

MAHENDRA GUPTA

Deputy Secretary (Editing)

विषय सूची

सत्र-5 (भाग-02) बृहस्पतिवार, 26 सितंबर, 2024/04 अश्विन, 1946 (शक)   अंक-71

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1-2
2.	निधन संबंधी उल्लेख	3-6
3.	बधाई प्रस्ताव एवं सूचना	7
4.	सदन में अव्यवस्था	8-16
5.	अल्पकालिक चर्चा (नियम-55)	17-172
6.	विधेयक का पुरःस्थापन	173

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-5 (भाग-02) बृहस्पतिवार, 26 सितंबर, 2024/04 अश्विन, 1946 (शक) अंक-71

दिल्ली विधान सभा

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए:

1. श्री अजेश यादव
2. श्री अखिलेशपति त्रिपाठी
3. श्रीमती ए. धनवंती चंदीला ए.
4. श्री अब्दुल रहमान
5. श्रीमती बंदना कुमारी
6. सुश्री भावना गौड
7. श्री बी. एस. जून
8. श्री धर्मपाल लाकड़ा
9. श्री दिनेश मोहनिया
10. श्री दुर्गेश कुमार
11. श्री गिरीश सोनी
12. श्री गुलाब सिंह
13. श्री हाजी युनूस
14. श्री जय भगवान
15. श्री जरनैल सिंह
16. श्री कुलदीप कुमार
17. श्री नरेश यादव
18. श्री पवन शर्मा
19. श्री प्रीति जितेंद्र तोमर
20. श्री प्रलाद सिंह साहनी

21. श्री प्रवीण कुमार
22. श्री प्रकाश जारवाल
23. श्री राजेश गुप्ता
24. श्रीमती राजकुमारी ढिल्लों
25. श्री रोहित कुमार
26. श्री शरद कुमार चौहान
27. श्री संजीव झा
28. श्री सोमदत्त
29. श्री शिव चरण गोयल
30. श्री सोमनाथ भारती
31. श्री सही राम
32. श्री एस. के. बग्गा
33. श्री सुरेंद्र कुमार
34. श्री विनय मिश्रा
35. श्री वीरेंद्र सिंह कादियान
36. श्री अजय दत्त
37. श्री अभय वर्मा
38. श्री अनिल कुमार बाजपेयी
39. श्री अजय कुमार महावर
40. श्री जितेंद्र महाजन
41. श्री महेंद्र गोयल
42. श्री महेन्द्र यादव
43. श्री मदन लाल
44. श्री मोहन सिंह बिष्ट
45. श्री ओमप्रकाश शर्मा
46. श्री ऋतुराज गोविंद
47. श्री रघुविंदर शौकीन
48. श्री राजेश ऋषि
49. श्री विजेंद्र गुप्ता
50. श्री विशेष रवि

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-5 (भाग-02) बृहस्पतिवार, 26 सितंबर, 2024/04 अश्विन, 1946 (शक) अंक-71

सदन पूर्वाह्न 11.12 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

(राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम्)

निधन संबंधी उल्लेख

माननीय अध्यक्षः आतंकी हमलों में शहीद हुए जवानों के प्रति शोक संवेदना। माननीय सदस्यगण, विगत कुछ माह के दौरान आतंकी हमलों में कई जवान शहीद हुए हैं तथा आम नागरिक भी घायल हुए हैं। इनमें से अधिकांश घटनायें जम्मू-कश्मीर में हुई हैं। दिनांक 04 मई, 2024 को जम्मू-कश्मीर के पुंछ में वायु सेना के काफिले पर आतंकी हमले में एक जवान शहीद हो गया तथा 04 अन्य जवान घायल हो गये। दिनांक 09 जून, 2024 को जम्मू-कश्मीर के रियासी में तीर्थ यात्रियों की बस पर आतंकवादियों की गोलीबारी से 09 यात्रियों की मौत हो गई और 40 से ज्यादा लोग घायल हो गये। दिनांक 10 और 11 जून, 2024 को कठुआ में आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच हुई मुठभेड़ में सी.आर.पी.एफ का एक जवान शहीद हो गया। दिनांक 12

जून, 2024 को डोडा में आतंकियों ने सुरक्षा बलों की चौकियों पर दो हमले किये जिनमें 06 सुरक्षाकर्मी घायल हो गये। दिनांक 08 जुलाई, 2024 को कठुआ में गश्त पर निकले दो सैन्य वाहनों पर घात लगाकर हमला कर दिया गया जिसमें सेना के जे.सी.ओ सहित 05 सैन्यकर्मी शहीद हो गये तथा 05 अन्य घायल हो गये। दिनांक 16 जुलाई, 2024 को जम्मू संभाग के डोडा जिले के जंगलों में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना के कैप्टन समेत 04 सैनिक शहीद हो गये। दिनांक 18 जुलाई, 2024 को छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में नक्सलियों ने एक बारूदी सुरंग में विस्फोट कर दिया जिससे एस.टी.एफ के 02 जवान शहीद हो गये तथा 04 अन्य घायल हो गये।

दिनांक 13 सितम्बर, 2024 को जम्मू-कश्मीर के कठुआ में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षाबलों ने 02 आतंकवादियों को मार गिराया जब कि किश्तवाड़ में एक अन्य मुठभेड़ में 02 जवान शहीद हो गये जबकि 02 अन्य जवान घायल हो गये।

उधर मणिपुर में लगातार अशांति के कारण पिछले दिनों कई लोग मारे गये हैं तथा पुलिस और सुरक्षा बलों के जवान भी शहीद हुए। इन कायरतापूर्ण हमलों की जितनी निंदा की जाये उतनी कम है। देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाले इन जवानों की शहादत अनमोल है। मैं शहीद हुए जवानों को अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से श्रद्धांजलि देता हूं और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं तथा ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिजनों को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

माननीय सदस्यगण, जैसा कि आप सबको विदित है कि दिनांक 12 सितम्बर, 2024 को वरिष्ठ राजनेता और सी.पी.एम के महासचिव श्री सीताराम येचुरी जी का दिल्ली में निधन हो गया। वे 72 वर्श के थे और काफी दिनों से बीमार थे। राजनीतिक क्षेत्र में उनका प्रवेश वर्ष 1974 में छात्र जीवन में ही हो गया था। इमरजेंसी के दौरान वे गिरफ्तार हुए और रिहा होने के बाद जेएनयू के छात्रसंघ के अध्यक्ष चुने गये। वे भारतीय राजनीति के सर्वोच्च मंचों पर देश के कमजोर तबकों की आवाज मजबूती से उठाते थे। वह पांच भाषाओं के ज्ञाता, कई पुस्तकों के लेखक और टेनिस के अच्छे खिलाड़ी थे। येचुरी जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनके निधन से भारतीय राजनीति को अपूरणीय क्षति हुई है।

मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से श्री सीताराम येचुरी के निधन पर हार्दिक शोक संवेदना प्रकट करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिजनों को इस दु:ख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

पिछले कुछ माह के दौरान विभिन्न आकस्मिक दुर्घटनाओं के कारण कई व्यक्तियों को अपनी जान गंवानी पड़ी है।

दिनांक 12 जून, 2024 को कुवैत के दक्षिणी अहमदी प्रांत के मंगाफ क्षेत्र में श्रमिकों की छह मंजिला आवासीय इमारत में आग लगने से 45 भारतीयों समेत 49 लोगों की मौत हो गई तथा 30 भारतीय घायल हो गये। जिस समय यह हादसा हुआ उस समय ज्यादातर श्रमिक

सो रहे थे और सोते समय धुंए से दम घुटने के कारण उनकी मौत हो गई।

दिनांक 17 जून. 2024 को उत्तर बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से 30 किलोमीटर दूर रंगापानी स्टेशन के पास मालगाड़ी की टक्कर के बाद कंचनजंघा एक्सप्रेस के दो डिब्बे पटरी से उतर गये। भिडंत इतनी तेज थी कि कंचनजंघा के पीछे के तीन डिब्बे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गये। हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई तथा 41 लोग घायल हो गये।

दिनांक 02 जुलाई, 2024 को हाथरस में सत्संग में भगदड़ से 120 लोगों की मौत हो गई तथा 100 से ज्यादा लोग घायल हो गये।

दिनांक 18 जुलाई, 2024 को उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में चंडीगढ़-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के 8 डिब्बे पटरी से उतर गये। इस दुर्घटना में 02 लोगों की मौत हो गई तथा 34 लोग घायल हो गये।

केरल के वायनाड जिले में भी दिनांक 30 जुलाई, 2024 को भारी बारिश के कारण कई जगह लैंडस्लाइड होने से 400 लोगों की मौत होने का अनुमान है तथा उस समय 170 लोग लापता हो गये।

दिनांक 27 जुलाई, 2024 को दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में स्थित कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में अचानक पानी भरने से तीन छात्रों की मौत हो गई।

मैं इन सभी हादसों के मश्तकों को अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से श्रद्धांजलि देता हूं और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की

कामना करता हूं तथा ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिजनों को इस अपार दु:ख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। अब दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए सदन द्वारा दो मिनट का मौन धारण किया जायेगा।

(सदन द्वारा दो मिनट का मौन धारण किया गया।)

ओम शांति, शांति।

माननीय सदस्यगण, मैं आप सभी का सातवीं विधानसभा के पांचवें सत्र के दूसरे भाग में हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि श्रीमती आतिशी जी के नेतृत्व में नई मंत्रिपरिषद ने कार्यभार संभाल लिया है। मैं माननीया मुख्यमंत्री श्रीमती आतिशी जी और उनके मंत्रिमंडल को बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि वे दिल्ली की जनता को बहुत अच्छा शासन देंगे और आम जनता की भलाई के लिए कार्य करने में सफल होंगे।

साथ ही मैं, श्री विजेंद्र गुप्ता जी को प्रतिपक्ष का नेता नियुक्त किए जाने पर बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि वे और उनकी पार्टी के सदस्य रचनात्मक विपक्ष के रूप में कार्य करेंगे और दिल्ली की जनता के हित में सदन को सुचारू रूप से चलने देंगे।

इसी के साथ नये सेक्रेट्री रंजीत सिंह जी ने पदभार संभाला है, मैं उनको भी बधाई देता हूँ।

गत आम चुनाव में लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के फलस्वरूप, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी ने दिनांक 18 जून 2024 से इस सदन से अपना त्यागपत्र दे दिया है। इसके अलावा श्री राजेंद्र पाल गौतम ने भी इस सदन से अपना त्यागपत्र दे दिया है, जिसे मैंने दिनांक 22 सितम्बर 2024 से स्वीकार कर लिया है। मैं आपको यह भी सूचित करना चाहता हूँ कि श्री राज कुमार आनंद और श्री करतार सिंह तंवर को संविधान की दसवीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत क्रमशः दिनांक 06 मई 2024 और 10 जुलाई 2024 से इस सदन के सदस्य के रूप में अयोग्य घोशित कर दिया गया है। इन सभी खाली सीटों का नोटिफिकेशन कर दिया गया है और चुनाव आयोग को सूचित कर दिया गया है।

माननीय सदस्यगण, मुझे श्री विजेन्द्र गुप्ता माननीय नेता, प्रतिपक्ष तथा विपक्ष के अन्य सदस्यों से नियम 55 के अंतर्गत अल्पकालिक चर्चा व नियम 54 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण की सूचना प्राप्त हुई है। श्री विजेन्द्र गुप्ता ने नियम 59 के अंतर्गत कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना भी दी है। मैं पिछले सत्र के दौरान व्यवस्था दे चुका हूँ कि कार्यसूची में सूचीबद्ध विषयों के अलावा किसी अन्य विषय को चर्चा के लिए नहीं लिया जायेगा। इस संबंध में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। अतः माननीय सदस्य सूचीबद्ध विषयों पर ही अपने विचार व्यक्त करें तथा सदन को सुचारू रूप से चलाने में मुझे सहयोग दें।

माननीय सदस्यगण, 280 में मुझे जितने भी माननीय सदस्यों के नोटिस प्राप्त हुए थे समय के अभाव में उन सबको पढ़ा हुआ माना जाए। मैं उनके नाम बोल रहा हूँ जिनके 10 सदस्यों के लॉटरी में आये।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः कोई बात नहीं ये व्यवस्था में दे रहा हूँ।

श्री विजेन्द्र गुप्ता (माननीय नेता, प्रतिपक्ष): ध्यानाकर्षण में हमारा सीएजी का ये मामला जो है।

माननीय अध्यक्षः और भी आये हुए हैं और भी आये हैं। मैं 280 में।

श्री विजेन्द्र गुप्ता (माननीय नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, सीएजी की रिपोर्ट आज सदन में पेश नहीं होगी।

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी ये तो कोई तरीका नहीं हुआ।

श्री विजेन्द्र गुप्ता (माननीय नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी आपको 280 ले लेने चाहिएं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, संवैधानिक इश्यू है।

माननीय अध्यक्षः ये तो सरकार को पेश करनी है, सरकार करे।

श्री विजेंद्र गुप्ता (माननीय नेता, प्रतिपक्ष): हम तो सरकार से जवाब चाहते हैं ना।

माननीय अध्यक्षः श्री विजेन्द्र गुप्ता जी, श्री अभय वर्मा जी, श्री संजीव झा जी, श्री गुलाब सिंह जी, श्री मोहन सिंह बिष्ट जी, श्री भूपेन्द्र सिंह जून जी, श्री अजय महावर जी, श्री विशेष रवि जी, श्रीमती प्रोमिला धीरज टोकस, श्रीमती बंदना कुमारी।

श्री अभय वर्माः आपकी ही व्यवस्था है, 11 से 12 में 280 लेंगे।

श्री मोहन सिंह बिष्टः सर 280 तो ले लीजिए ना, 280 में क्या प्रॉब्लम है। हम भी कम से कम एरिया के बारे में बतायें..

...व्यवधान...

श्री मोहन सिंह बिष्टः उसके बाद जो है हमको बोलने तक समय नहीं दिया जा रहा है। आखिर बोले तो बोले किस platform में जाके, बताइये? अध्यक्ष जी ये 280 ।

माननीय अध्यक्षः अल्पकालिक चर्चा (नियम-55) श्री कुलदीप कुमार जी दिल्ली परिवहन निगम के बस मार्शल्स को नियमित करने के संबंध में चर्चा प्रारम्भ करेंगे।

...व्यवधान...

श्री कुलदीप कुमारः अरे गुप्ता जी बैठ जाओ मेरा नंबर है, ऐसे मत करो, चर्चा होने दो। धन्यवाद अध्यक्ष जी और आज इस सदन में बड़े महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा शुरू की गई है और मैं जैसे ही दिल्ली सिविल डिफेंस बस के मार्शल की चर्चा की आपने बात शुरू करी तुरन्त मेरे विपक्ष के साथी बीजेपी के लोग।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः आप बोलते रहिये, आप बोलो आपकी बात रिकॉर्ड होगी, उनकी कोई रिकॉर्ड नहीं होगी।

श्री कुलदीप कुमारः अध्यक्ष जी तुरन्त मेरे बीजेपी के साथी विरोध करने के लिए खड़े हो गए क्योंकि इनको पता है कि जो ये चर्चा शुरू हो रही है इनके काले कारनामों की पोल आज इस सदन में खुलेगी और जैसे इन्होंने दिल्ली के सिविल डिफेंस के बस मार्शलों को जिस प्रकार से इन्होंने हटाने का काम किया है वो बात जनता के सामने जायेगी, उन बस मार्शलों के सामने जायेगी इसलिए ये बस मार्शलों का विरोध करने के लिए यहां खड़े हुए हैं।

...व्यवधान...

(पक्ष तथा विपक्ष के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गए)

माननीय अध्यक्षः मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ कृपया बैठे। माननीय सदस्यों से प्रार्थना है कि कृपया अपने स्थान पर बैठे। सभी माननीय सदस्य.....

...व्यवधान...

(पक्ष तथा विपक्ष के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गए)

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्यगण अपने स्थान पर बैठे। सभी से प्रार्थना है। सभी माननीय सदस्यों से प्रार्थना है कृपया अपने स्थान पर

बैठे।

(पक्ष तथा विपक्ष के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गए)

माननीय अध्यक्षः सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित की जाती है।

सदन 11.45 बजे पुनः संवेत हुआ

माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री रामनिवास गोयल) पीठासीन हुए।

माननीय अध्यक्षः कुलदीप जी।

श्री कुलदीप कुमारः धन्यवाद अध्यक्ष जी, और।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः कुलदीप जी एक सेकेंड, एक सेकेंड।

...व्यवधान...

(विपक्ष के सदस्यों द्वारा द्वारा नारेबाजी की गई।)

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी, देखिये मैं,

...व्यवधान...

(विपक्ष के सदस्यों द्वारा द्वारा नारेबाजी की गई।)

माननीय अध्यक्षः मैं माननीय विपक्ष के सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं सदन की कार्यवाही चलने दें, सदन की कार्यवाही चलने दें बहुत महत्वपूर्ण विषय है। 10 हजार मार्शलों की नौकरियां चली गई हैं, 10 हजार मार्शलों की नौकरियां चली गई हैं। दिल्ली के 10 हजार मार्शल घर पर बैठा दिये गये हैं।

श्री कुलदीप कुमारः अरे आप लोग क्यों डर रहे हो मार्शल पर चर्चा करने से, बताईये? मार्शल पर चर्चा करने से उनके रोजगार पर चर्चा करने से आप लोग क्यों डर रहे हो, क्यों घबरा रहे हो आप लोग?

माननीय अध्यक्षः मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं.

...व्यवधान...

श्री कुलदीप कुमारः क्यों नौटंकी कर रहे हैं यहां पर? अगर आज यहां बस मार्शल के रोजगार पर चर्चा हो रही है तो आपको क्या दिक्कत है?

माननीय अध्यक्षः कुलदीप जी आप बोलना शुरु करिये, जरा उंचाई से बोलिये।

श्री कुलदीप कुमारः अध्यक्ष जी, आज इतने महत्वपूर्ण विषय पर यह चर्चा हो रही है 10 हजार से ज्यादा लोगों के घरों और परिवार का विषय है, उनकी रोजी-रोटी का विषय है, आज उनकी रोजी-रोटी छीन ली गई है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उप-राज्यपाल महोदय के द्वारा

उनकी रोजी–रोटी को छीना गया और उनको घर से बेघर करने का काम किया गया, उनकी नौकरी छीनने का काम किया गया। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में अध्यक्ष जी, दिल्ली की सरकार ने 10 हजार से ज्यादा बस मार्शलों को नौकरी देने का काम किया उनको रोजगार देने का काम किया।

...व्यवधान...

(विपक्ष के सदस्यों द्वारा द्वारा नारेबाजी जारी रखी गई।)

माननीय अध्यक्षः मैं दोबारा प्रार्थना कर रहा हूं। विजेन्द्र जी, करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूं सदन की कार्यवाही चलने दीजिए।

...व्यवधान...

श्री कुलदीप कुमारः उन बस मार्शलों को रोजगार देने का काम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने करने का काम किया और आज जब उनको नौकरी से निकाल दिया गया.

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः मुझे मजबूर मत करिए।

श्री कुलदीप कुमारः और दिल्ली की सरकार चाहती है कि उनको रोजगार मिले...

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः मैं प्रार्थना कर रहा हूं।

श्री कुलदीप कुमारः उन पर चर्चा हो तो भारतीय जनता पार्टी के लोग नौटंकी कर रहे हैं,

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः मैं बार बार प्रार्थना कर रहा हूं, बैठ जाएं।

श्री कुलदीप कुमारः ड्रामा कर रहे हैं यहां खड़े होकर ये बीजेपी के लोग। ये गरीब लोगों के विरोधी लोग हैं, ये बस मार्शलों के विरोध करने वाले लोग हैं।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः बोलिये, आप बोलिये।

...व्यवधान...

श्री कुलदीप कुमारः अध्यक्ष जी ये आज इन बस मार्शलों का मुद्दा है लगातार 2015 के बाद से।

माननीय अध्यक्षः महेन्द्र जी, बैठिये-बैठिये-बैठिये।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्यों से प्रार्थना है बैठें। माननीय विपक्ष से मैं बार-बार बोल रहा हूं बहुत महत्वपर्ण मुद्दा है। 10 हजार

लोग घर बिठा दिये गये हैं, 10 हजार मार्शल्स, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा है, दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा है।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः मार्शल्स, मार्शल्स वाजपेयी जी को बाहर करें, बाहर करिये, अभय वर्मा जी को बाहर करें।

श्री कुलदीप कुमारः ये चाहते हैं सदन से बाहर जाना, ये भागना चाहते हैं।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः जितेन्द्र महाजन जी को बाहर करिये।

श्री कुलदीप कुमारः ये अब मार्शल्स के मुद्दे पर चर्चा होने नहीं देना चाहेंगे यहां पर।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र गुप्ता जी को, ओमप्रकाश जी को, अजय महावर जी को बाहर करें। सदन से बाहर करें, जल्दी करिये बाहर, बाहर करिये जल्दी, मार्शल जल्दी करिये बाहर, बाहर करिये, मोहन सिंह बिष्ट जी को बाहर करिये, अभय वर्मा जी को करिये बाहर। भई बाहर क्यों नहीं कर रहे हैं, जल्दी करिये बाहर। बिल्कुल कोई रियायत नहीं। 10 हजार मार्शल हटा दिये गये, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा है उस पर चर्चा ही नहीं चाहते, शुरु करो।

अल्पकालिक चर्चा (नियम-55)

श्री कुलदीप कुमारः धन्यवाद अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी देखिये जैसे ही बस मार्शल पर चर्चा शुरु हुई, पिछली बार भी सदन में चर्चा शुरु हुई थी तब भी नेता, प्रतिपक्ष उस समय पर बिधूड़ी जी थे और उन्होंने यही नौटंकी करके वो सदन से भाग गये थे। आज फिर इस सदन के अंदर वही हुआ कि जब बस मार्शलों की बात शुरु हुई तो वो नौटंकी करके इस सदन को परेशान करने का काम किया और यहां से चले गये। अध्यक्ष जी, दिल्ली के बस मार्शल आज बड़े दुख के साथ मुझे इस सदन के अंदर ये बात रखनी पड़ रही है दूसरी बार की दिल्ली के वो बस मार्शल जिन्हें दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 2015 के अंदर दिल्ली की बसों के अंदर तैनात किया ताकी वो हमारी माताओं और बहनों की, हमारे बच्चों की डीटीसी बस के अंदर सुरक्षा कर सकें और मुझे ये बात बड़ी जिम्मेदारी से कहते हुए खुशी भी हो रही है कि उन बस मार्शलों ने अपनी उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और दिल्ली की बसों के अंदर हमारी माताओं और बहनों की सुरक्षा की और लगातार अरविंद केजरीवाल जी ने जब उन 10 हजार मार्शलों को नियुक्त किया था उसके बाद से लेकर 2023 तक मतलब लगभग 8 साल तक वो दिल्ली की बसों के अंदर अपनी सर्विसेज दे रहे थे। वो दिल्ली में जब कोरोना काल आया देशभर के अंदर तो दिल्ली के लोगों की सेवा कर रहे थे, दिल्ली के लोगों की मदद कर रहे थे, वो दिल्ली के लोगों को बढ़-चढ़कर उनका साथ देने का काम कर रहे थे। जब बाप बेटे को नहीं देख रहा था, बेटा बाप को नहीं

देख रहा था उस समय पर उन्होंने दिल्ली के लोगों की मदद की और अपनी जान को हथेली पर रखकर कोविड काल के अंदर उन बस के मार्शलों ने दिल्ली के लोगों की सेवा करने का काम किया। लेकिन अध्यक्ष जी दिल्ली के उप-राज्यपाल महोदय ने 2023 में उनकी सेलरी रोकने का काम शुरु किया। जब सैलरी रोकने का काम शुरु किया अध्यक्ष जी तो उसके बाद 6 महीने तक उन लोगों को सैलरी नहीं मिली और उसके बाद एक आर्डर निकाल दिया गया आनन-फानन में कि उन सब लोगों को नौकरी से हटाया जा रहा है और उसका रीजन क्या दिया गया? एलजी साहब ने कहा कि डीटीसी की बसें के अंदर पैनिक बटन और सीसीटीवी कैमरे लग चुके हैं इसलिए बस मार्शल की आवश्यकता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के उप-राज्यपाल महोदय के द्वारा इस प्रकार का उदाहरण पेश करना, इस प्रकार का एग्जाम्पल देना कि डीटीसी की बस के अंदर अगर पैनिक बटन और कैमरे लग चुके हैं तो वहां पर सुरक्षाकर्मी की जरूरत नहीं है, बस मार्शल की जरूरत नहीं है। एलजी साहब के घर के अंदर तो, अभी हम शपथ ग्रहण समारोह में गये थे, हजारों कैमरे लगे हुए हैं और सिक्योरिटी गार्ड भी उतने हैं। एलजी साहब अपनी सिक्योरिटी को हटा दें दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस जो सुरक्षा कर रही है। तो दिल्ली के अंदर जो जगह-जगह हमने कैमरे लगाये हुए हैं तो आप क्या दिल्ली पुलिस को कल हटा दोगे? अध्यक्ष महोदय, एक पूरी प्लानिंग के तहत उन 10 हजार बस मार्शलों को हटाने का काम किया गया है और उसके साथ-साथ जो उनको झूठ परोसने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और

एलजी महोदय ने करने का काम किया अध्यक्ष महोदय इसी सदन के अंदर मुझे याद है कि इस सदन के अंदर अध्यक्ष जी हम लोगों ने 29 फरवरी को एक संकल्प पास किया और उस संकल्प के अंदर हमने पूरी डिटेल से ये बताया कि ये बस मार्शल 2015 से दिल्ली की जनता की सेवा कर रहे हैं, दिल्ली की बसों में सुरक्षा कर्मी का काम कर रहे हैं लेकिन अध्यक्ष जी हमने जो प्रस्ताव पास किया, वो प्रस्ताव पास होने के बाद पहले तो बीजेपी के लोग उन मार्शलों को गुमराह करते रहे, वो कहते रहे जी दिल्ली की सरकार नहीं चाहती है, उन्होंने आपको हटाया है, वो आपको नौकरी देना नहीं चाहते और हमने सदन में आकर वो प्रस्ताव लाकर ये स्पष्ट किया कि दिल्ली की सरकार को उन बस के मार्शलों की आवश्यकता है, हमारी डीटीसी बस के अंदर उन बहन-बेटियों की सुरक्षा के लिए उनकी आवश्यकता है और दिल्ली की सरकार उनको नौकरी पर रखना चाहती है। लेकिन अध्यक्ष जी उसके बाद जब ये प्रस्ताव पास हुआ, ये सदन जो दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को रिप्रजेंट करने का काम करता है, उनका प्रतिनिधित्व करने का काम करता है, इस सदन से पास किया गया प्रस्ताव जब दिल्ली के उप-राज्यपाल महोदय के पास पहुंचा तो भाजपा के नेताओं ने झूठ बोलने का काम शुरु किया कि इस सदन में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं पास हुआ। हमारे पास सिविल डिफेंस वालंटियर जो लोग हैं वो सारे लोग आए, उन्होंने हमसे आकर कहा कि आपने जो प्रस्ताव पास किया है सदन में वो उप-राज्यपाल महोदय के पास नहीं पहुंचा। हमने कहा ये तो सदन की व्यवस्था है जो भी सदन में प्रस्ताव पास होगा वो उप-राज्यपाल

महोदय के पास जाएगा। आप देखिये किस तरह की छोटी–छोटी बातें उप–राज्यपाल कार्यालय से और भाजपा के लोगों ने करने का काम किया है। उन्होंने कहा हमें प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ उसकी कापी लाकर दो। हमने सिविल डिफेंस वालंटियर और मार्शलों को उस प्रस्ताव की कापी मुहैया कराने का काम किया। अध्यक्ष जी, वो जाकर फिर उनसे मिले उन्होंने कहा जी अब तो कापी आपके पास गई अब क्या करोगे, उन्होंने कहा जी कापी तो आ गई लेकिन वो लोग चाहते नहीं हैं आप नौकरी पर लगो, उनके मिनिस्टर से किसी से कहलवाओ, वो प्रस्ताव तो हमें आ गया लेकिन उनसे पीसी करके कहलवाओ। हम लोगों ने मैं और संजीव भाई यहां बैठे हैं हम लोगों ने विधानसभा की तरफ से इस प्रस्ताव की तरफ से, एक प्रेस कांफ्रेंस करी और उसके अंदर हमने कहा कि हमने दिल्ली विधानसभा से प्रस्ताव पास किया है और हमारे सिविल डिफेंस के वालंटियरों को, बस के मार्शलों को उनका रोजगार वापस होना चाहिये, आज उनके घर चलने के भी लाले पड़े हुए हैं, वो अपने बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे हैं और मुझे ये भी जानकारी मिली कि कुछ लोगों ने तो आत्महत्या तक कर ली अध्यक्ष जी। और हमने उसके बाद वो पीसी के माध्यम से बात रखी, हमने वो पीसी की और उसके 2 दिन बाद अध्यक्ष जी फिर दोबारा वो बीजेपी के लोगों के पास गये। अब उन्होंने फिर क्या कहा अध्यक्ष जी, कहते हैं डायरी नंबर लाकर दो डायरी नंबर। अध्यक्ष जी इतना झूठ, इतना बेवकूफ हमारे बस के मार्शलों को इन लोगों ने बनाने का काम किया। एलजी साहब पूरी दिल्ली में जगह–जगह घूमते हैं रोज की रोज, रोज ट्वीट करते रहते

हैं। मैं तो एलजी साहब से कहना चाहता हूं अभी भी बीच में एक हुआ था फिर बस मार्शल गये उन्होंने कहाजी कि बीजेपी की तरफ से और आम आदमी पार्टी की तरफ से और दिल्ली विधानसभा की तरफ आमने-सामने लोग आएं और चलकर एलजी साहब के पास चलें। अध्यक्ष जी, मैं इस सदन में बताना चाहता हूं उस दिन एलजी हाउस के बाहर 45 डिग्री टेंपरेचर के अंदर हमारी वो माताएं-बहनें और बस मार्शल बैठे हुए थे और उनके साथ हमारे 10 से ज्यादा विधायक वहां मौजूद थे, इस कारण से कि हमें उम्मीद थी कि बीजेपी के सांसद, बीजेपी के लोग वहां पर आएंगे और आने के बाद वो एलजी हाउस में हमारे साथ चलेंगे और हमारे बस मार्शल भाई-बहनों को रोजगार मिलने का काम होगा। उधर से टेलीफोन आता है कि विधायक तो आ गये मंत्री जी नहीं आए जब मंत्री जी आएंगे तब बीजेपी के लोग आएंगे, तब बिधूड़ी जी आएंगे, तब गुप्ता जी आएंगे ये सूचना उनको मिली। उन्होंने हम से कहा कुलदीप जी आप लोग तो आ गये, वो लोग कह रहे हैं हम तब आएंगे जब मंत्री जी आ जाएंगे। अध्यक्ष जी, मैं सदन को बताना चाहता हूं उसी रोड पर 45 डिग्री टेंपरेचर में एलजी हाउस के बाहर सौरभ भारद्वाज जी, मंत्री जी वहां पर पहुंच जाते हैं और एक घंटा वहां रुकते हैं लेकिन एक घंटे तक भाजपा का कोई नेता वहां पर नहीं आता है क्योंकि अध्यक्ष जी उनकी नीयत साफ दिखती है, वो इन लोगों को रोजगार देना नहीं चाहते हैं। वो चाहते नहीं है कि इन लोगों को रोजगार मिले इनकी नौकरी वापस हो केवल झूठा प्रोपेगेंडा झूठ-झूठ बोलते जा रहे हैं। माननीया मुख्यमंत्री जी ने भी यहां पर उनकी व्यथा

को रखने का काम किया था अरविंद केजरीवाल जी ने भी यहां उनकी व्यथा को रखने का काम किया था इस सदन के अंदर मुझे याद है। अध्यक्ष जी उसके बाद जब वहां पर मंत्री जी आए तो उन्होंने कहा जी मंत्री जी तो आ गये लेकिन हमें आप एक पत्र डिपार्टमेंट की तरफ से दिलवाओ, मंत्रियों की तरफ से। तो अध्यक्ष जी मैं बताना चाहता हूं सदन को कि हमारी जो रेवेन्यू मिनिस्टर हैं आतिशी जी उन्होंने अपना एक लैटर दिल्ली के उप-राज्यपाल महोदय को उसी दिन भेजने का काम किया और उस लैटर के अंदर उन्होंने बताया कि हम इन बस मार्शलों को दोबारा से रोजगार देना चाहते हैं और अध्यक्ष जी उन्होंने बड़े उससे बताया कि as the elected Government in the Delhi, we are ready to extend the all possible help and support required to restore bus marshal their jobs. We hope that the matter will be considered positive discussion by your good self. ये एलजी साहब को लिखा हुआ है और एलजी साहब से कहा कि हम चाहते हैं कि इनको रोजगार वापस हो लेकिन अध्यक्ष महोदय मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि दिल्ली की मंत्री के लिखने के बाद दिल्ली की विधानसभा के पास करने के बाद भी उन लोगों को आज तक रोजगार नहीं मिला उनको नौकरी नहीं मिली। मैं तो कहना चाहता हूं भाजपा के लोगों से भी और एलजी साहब से भी कहना चाहता हूं एलजी साहब अगर आपकी मंशा उनको रोजगार देने की है तो आप एक मीटिंग तो उन लोगों से कर लो, एक बातचीत तो उनसे कर लो, उनको बिठा तो लो कम से कम, हमें भी बुला लो और मैं तो कह रहा हूं इस सदन के

अंदर आपको बताओ क्या चाहिए, इस सरकार से क्या चाहिए आपको इस सरकार से। आप जहां कहेंगे, जैसे कहेंगे हमने कहा, बार-बार मंत्री जी ने भी कहा कि हम वहां साइन करने के लिए तैयार हैं, आप बताईये। लेकिन जब भी चर्चा की बात होती है भाग जाते हैं अध्यक्ष जी, खड़े हो जाते हैं यहां से और मैं तो कहता हूं आज एलजी साहब अगर आपकी नीयत है, छोड़ो आप मीटिंग नहीं कर सकते आप रोज कहीं कूड़े का ट्वीट करते हो, कहीं नाले का ट्वीट करते हो, कही किसी चीज का ट्वीट करते हो, दिल्ली की कानून व्यवस्था पर आपका ध्यान नहीं है, बस मार्शल की नौकरी चली गई ध्यान नहीं है, कहीं 2 लोगों को नौकरी दोगे आप डालोगे ट्वीट मैंनें 2 लोगों को नौकरी दी, अरे अगर नौकरी 2 को दी तो 10 हजार लोगों की नौकरी छीनने वाले भी आप हैं, उनका पाप आपको लगेगा और भाजपा के लोगों को लगेगा उनका पाप। उनका घर चलना मुश्किल हो गया है लेकिन आज ये लोग बैठे हुए हैं लट्टन साहब कुर्सी पर, उनको लग रहा है कि मुझसे बड़ा कोई है नहीं। अध्यक्ष जी, समय सबका आता है, मैं बता देता हूं। दिल्ली की जनता के अधिकारों को छीनने का काम, दिल्ली की सरकार के अधिकारों को छीनने का काम, हमें नहीं पता था इस मंशा से किया जा रहा है। इसी मंशा से सुप्रीम कोर्ट के 5 जज के फैसले को पलटने का काम आधी रात को केन्द्र की सरकार ने किया। उनको लगता था कि कहीं ये लोगों को रोजगार न दे दें, उनको हटाने के लिए इन लोगों ने किया। पूरी मंशा के साथ पूरी प्लानिंग के साथ अध्यक्ष जी ये करने का काम किया गया और मैं कहता हूं एलजी साहब आज आप ट्वीट

करें, आज ये ट्वीट करके कहें कि मैं इनको रोजगार देना चाहता हूं और आप बताएं कि आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं, किसका अप्रूवल आपको चाहिए ये बताएं और बीजेपी के लोग भाग गये यहां से अभी अध्यक्ष जी ड्रामा करके नौटंकी करके। मैं तो कहता हूं अगर बीजेपी के लोग, तुम्हारे अंदर हिम्मत है और तुम्हारे अंदर शर्म है, जरा सी भी दया की भावना है तो उन 10 हजार लोगों के परिवार की तरफ देखो, उनके घर की तरफ देखो, उनके बच्चों की तरफ देखो। अध्यक्ष जी, उनके बच्चों की तरफ उनकी स्कूल की फीस नहीं जा रही है, घर में खाना नहीं है उन लोगों के लेकिन इनको इससे फर्क नहीं पड़ता ये बड़े लोग हैं। सांसद का चुनाव था, बिधूड़ी जी आज सदन में नहीं हैं, उन्होंने कहा कि मैं सांसद बन जाउंगा तुम्हें रोजगार वापस कराउंगा तुम्हारा। अरे अब तो 7 के 7 तुम्हारे सांसद बन गये अब क्या दिक्कत आ रही है। तो मैं तो कहता हूं अध्यक्ष जी कि आज बीजेपी के लोग यहां पर आएं और यहां आकर वादा करें कि वो रोजगार देना चाहते हैं और अभी के अभी चलें एलजी साहब के पास यहां से, कहां दिक्कत आ रही है, कहां अड़चन आ रही है, कौन सा ऐसा अधिकारी है जो फाइल को रोककर बैठा हुआ है। कौन नहीं चाहता रोजगार दिलाना उनको ये बात इस सदन में अध्यक्ष जी स्पष्ट होनी चाहिए और मैं यह कहना चाहता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है और इस मुद्दे को, मुझे लगता है ये 10 हजार लोगों के घर-परिवार से जुड़ा हुआ मुद्दा है और हम कहते हैं कि हम इस पर कोई राजनीति नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि सारा क्रेडिट बीजेपी के लोग ले लें

लेकिन उसका रोजगार वापस कर दें। सारा क्रेडिट इन लोगों का, सारा क्रेडिट ये लोग ले लें 10 हजार लोगों को रोजगार अरविंद केजरीवाल जी ने दिया, इन्होंने एक झटके में छीनने का काम किया। उनका रोजगार वापस होना चाहिए इसी के साथ मैं फिर कहता हूं कि बीजेपी के लोग अगर इनका रोजगार चाहते हैं तो इस सदन में आएं अपनी बात कहें और चलें हमारे साथ एलजी साहब के पास आज हम सब लोग चलने को तैयार हैं एलजी साहब के पास उनके रोजगार के लिए, हम सब लोग जाएंगे और चलकर उनको वापस कराएं आज के आज कराएं। अभी की अभी कराने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद, श्री अब्दुल रहमान जी।

श्री अब्दुल रहमानः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, बड़ी अजीब सी बात है कि दस हजार मार्शल और सिविल डिफेंस के लोगों को एलजी साहब ने एक मनमाने तरीके से बिल्कुल दूध में से मक्खी की तरह उठाकर फेंक दिया और बेरोजगार कर दिया और ये कह दिया कि सीसीटीवी कैमरे लगे हैं बसों के अंदर, पैनिक बटन लगे हैं बसों के अंदर तो कोई जरूरत नहीं है। मैं एक छोटी सी एक मिनट की एक कहानी आपको सुनाना चाहता हूं। एक गांव में एक गरीब व्यक्ति का परिवार रहता था जंगल के नजदीक और उस जंगल में था क्या कि उनके पास एक गधा था और बरसात का मौसम था, बरसात हो रही थी और इतेफाक से क्या हुआ कि वहां एक शेर आ गया और

शेर आकर के उसके कमरे में जहां गधा बंधा होता था वहां शेर जाके खड़ा हो गया। उस गरीब व्यक्ति की बीवी ने कहा कि जाओ गधे को बांध आओ। तो शेर सुन रहा था ये बात, उसने कहा यार मुझे इतना डर उसका नहीं है शेर का भी नहीं है, जितना डर टपके का हो रहा है। तो टपका पड़ रहा होगा अंदर तो गधा भीग जायेगा। शेर ने सुना यार ये तो कोई मुझ से भी बड़ी चीज है टपका, ये क्या बला है। तो खैर वो बेचारा किसान आया अंदर, उसने देखा तो वहां शेर खड़ा हुआ था, अंधेरा था उसने सोचा गधा है उसका कान पकड़ा, शेर ने सोचा यही टपका है, ये मुझसे भी बड़ी कोई आईटम है, टपका यही है, शेर भी डर गया। उसने ले जाके शेर को बांध दिया। तो मार्शल जो थे वो एक टपके का काम कर रहे थे इतनी दहशत, इतनी दहशत बदमाशों में थी कि आये दिन जो मनचले बसों में सफर किया करते थे, जिन मनचलों की वजह से, जिन गुंडे आवाराओं की वजह से हमारी बहन, बेटी, माएं बसों में सफर नहीं करती थीं, बसों में जिस दिन से मार्शल लगे अध्यक्ष महोदय, उस दिन से बसों में महिलाओं की संख्या मेरे ख्याल से छह सात गुना ज्यादा बढ़ गयी, आज बेखौफ होकर के महिलायें बसों में सफर करने लगी, बेखौफ होकर के मां, बहन बेटियों ने बसों में सफर करना शुरू कर दिया क्योंकि उनकी हिफाजत के लिये वहां सीसीटीवी तो लगा ही था, वहां पैनिक बटन तो था ही, एक मार्शल भी वहां बैठा हुआ था और जिसका डर इतना था बदमाशों में और कई हादसे ऐसे हुए दिल्ली के अंदर जहां हमारे मार्शल ने उन गुंडों को तुरंत पकड़कर के पुलिस के हवाले किया ले जाकर के और उस

बदमाशी पर रोक लगाई। तो महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हमारी मंत्री महोदया के लिखने के बावजूद, आदेश देने के बावजूद कि एक हफ्ते के अंदर अंदर इन मार्शलों का वेतन भुगतान किया जाये, उसके बाद उनका वेतन नहीं मिला, दस हजार मार्शलों को बेघर कर दिया गया। उनके घर में क्या व्यवस्था है रोटी की, रोजी की या जो है मतलब दवाई की, दारू की, किसी को परवाह नहीं। एलजी साहब एक लाट साहब की तरह बैठकर के काम कर रहे हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं कि किसी गरीब का क्या होगा, उन्हें बस अपनी कुर्सी से मतलब है। अभी कुलदीप भाई ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि एलजी साहब अगर आप ये सच में ये सुरक्षा समझते हो कि वहां पैनिक बटन और वहां जो है सीसीटीवी कैमरे बसों में लग गये तो सुरक्षित हैं तो सबसे पहला काम आप ये कीजिये कि आपके घर पर बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं आपके पास जितने भी सिक्योरिटी के लोग हैं उन सब को हटाईये। सीसीटीवी में अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जायेगी तो पुलिस तो पकड़ ही लेगी सीसीटीवी देख के, फिर जरूरत क्या है इस सब सिक्योरिटी की। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है दिल्ली की इस तरह की व्यवस्था जो एलजी साहब चलाना चाहते हैं, गरीब आदमियों को बेघर करना चाहते हैं, बेरोजगार करना चाहते हैं ये शर्मनाक है और अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि इसी विधान सभा में 29.02.2024 को रेज्योल्यूशन पास हुआ था उसके बावजूद भी अभी तक न उनको बहाल किया गया, न उनका वेतन दिया गया है। तो ये बड़े शर्म की बात है कि

दिल्ली की विधान सभा जिस रेज्योल्यूशन को पास कर दे और उसके बाद भी उस पर अमल न हो, दिल्ली के राजस्व मंत्री आदेश करें और उनके आदेश पर अमल न हो। तो एलजी साहब क्या करना चाहते हैं इस दिल्ली का और कहां ले जाना चाहते हैं इस व्यवस्था को, बड़ा गंभीर होकर के इस विषय पर सोचना होगा और उन बेरोजगारों के लिये जिन बेचारों को आज दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं, सड़कों पर भटकना पड़ रहा है उन्हें तुरंत लगाने की व्यवस्था की जाये, उनका वेतन दिया जाये, उन्हें बहाल किया जाये। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद, श्री रोहित कुमार जी।

श्री रोहित कुमारः धन्यवाद अध्यक्ष जी, जो आपने मुझे इतने गंभीर मुद्दे पर अपनी बात कहने का मौका दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, दिल्ली के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 2015 के अंदर माता, बहनों की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए जो बसों में यात्रा करती थीं और जो बसों में यात्रा करते हैं गरीब परिवारों से ही जो माता बहनें आती हैं वही ज्यादा उसमें सफर करते हैं, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए, आए दिन ये घटनायें सामने आती थी जैसे तमाम हमारे साथियों ने बताया कहीं छीना झपटी की घटनायें, कहीं चोरी चकारी की घटनायें, उन सबको ध्यान में रखते हुए दिल्ली की सरकार ने 2015 के अंदर दस हजार सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स, बस मार्शल की नियुक्ति की और उसके बाद हमने लगातार देखा कि किस

प्रकार से जांबाजी दिखाते हुए, दिलेरी दिखाते हुए हमारे बस मार्शलों ने दिल्ली की माता बहनों को सुरक्षा प्रदान करी, कई प्रकार के बड़े अपराधों को होने से रोका। मैं उसका एग्जाम्पल भी यहां पे रखना चाहूंगा। एक बस मार्शल अरूण कुमार नाम का एक चार साल की बच्ची को अगवा करते हुए कुछ अपहरणकर्ता यहां पर बस में ले कर जा रहे थे अरूण कुमार की सूझबूझ की वजह से, दिलेरी की वजह से उस चार साल की बच्ची को अपहरण होने से बचाया गया। जो लोग उसको अपहरण करके लेके जा रहे थे उनको पुलिस के हवाले भी किया गया। उसके अलावा दिल्ली दंगों के दौरान रूट नंबर 253 बस में जब खजूरी चौक के पास ये बस पहुंची तो लगभग दो ढाई सौ दंगाई वहां पर सड़क पर खड़े थे। एक गुलशन नाम के जो हमारा बस मार्शल था उस भाई ने इतनी दिलेरी दिखाई कि खुद अकेले बस में से उतर के पूरे दरवाजे बंद करा दिये और खुद अकेले उतर कर बस को तुरंत बैक करवाया, सबका हौंसला बंधाया, सबको हिम्मत बंधाई कि आप चिंता न करें और ऐसी मुश्किल घड़ी के अंदर उसने सूझबूझ दिखाते हुए लगभग बीस पच्चीस लोगों की जान बचाई। उन लोगों के साथ कुछ भी हादसा हो सकता था। और जहां तक बात है कि कई सारे जो जेब कतरे या चोर उचक्के वो तो आये दिन उनको पकड़ते थे। कोरोना की मुश्किल घड़ी के अंदर भी हमने देखा कि किस प्रकार से सिविल डिफेंस के हमारे साथियों ने, भाईयों ने, बहनों ने अपनी जान को जोखिम में डाल कर, अपनी जान को खतरे में डालकर जब कोई परिवार का सदस्य एक दूसरे को हाथ नहीं लगाता था, एक दूसरे को

अस्पताल तक नहीं लेकर जाता था उनके कोरोना के जब टैस्ट होते तो डिस्पेंसरी के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर वो सारी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, उनकी दवाईयों के, इलाज के लिये हर तरह से उनकी मदद करी। तो कहीं न कहीं ये दस हजार से ज्यादा जो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स थे, बस मार्शल्स थे इन्होंने देवदूत की तरह काम करा और आज बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी ने दस हजार से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया और ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की आंखों में खटका, एलजी साहब ने एक तुगलकी फरमान निकाल कर, तरह तरह के बहाने बनाकर इनको तुरंत नौकरी से निकाल दिया और ये नहीं सोचा कि ये दस हजार लोग हैं और अगर हर आदमी के साथ 5-5, 6-6 लोगों का परिवार जोड़ें तो लगभग 60-70 हजार लोगों के पेट पे लात मारने का काम इन्होंने किया है। बहुत सारे हमारे सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स हमारे पास आते हैं, बस मार्शल हमारे कार्यालय में आते हैं, वो हमें अपनी आपबीती बताते हैं किस प्रकार से बच्चों की फीस वो नहीं भर पा रहे हैं। किस प्रकार से उनको खर्चे के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं, किस प्रकार से राशन तक उनके घर में नहीं आ पाता है। कई सारे हमारे सिविल डिफेंस के साथियों ने, बस मार्शलों ने आत्महत्या तक की कोशिश की है, उसके बाद भी इनका मन नहीं पसीजा है। और जब इनको हटा दिया गया, हम लगातार इस सदन के माध्यम से उनका समर्थन कर रहे हैं कि फिर से दस हजार लोगों को बहाल किया जाना चाहिये। जैसा अभी हमारे साथी बता रहे थे कि हमने इसी

विधान सभा के अंदर एक विधेयक पास किया, रेज्योल्यूशन पास किया कि दस हजार लोगों को तुरंत इनकी नौकरी पर बहाल किया जाना चाहिये, उसके बाद इसकी कापी भी भेजी गयी, एलजी साहब को भी कापी भेजी गयी उसके बाद भी इन्होंने कभी इसकी ओर संज्ञान नहीं लिया और ये दर्शाता है कि ये दस हजार लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय हमारे मंत्री जी यहां पर बैठे हैं सौरभ भारद्वाज जी, अभी 11 तारीख की बात है इसी महीने जब अपनी जायज मांगों को लेकर हमारे सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स हमारे साथी, बस मार्शल्स एलजी हाउस अपनी याचिका लेकर पहुंचे तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी आमंत्रित किया गया था कि आईये, क्या कमी रह गयी है क्या कुछ है हम मिलकर इसको सुलटाते हैं, हम भी बड़ी खुशी के साथ में वहां पर पहुंचे, हमारा विधायकों का प्रतिनिधि मंडल जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का वहां पर पहुंचना था, हम तमाम आम आदमी पार्टी के विधायक दस से ज्यादा विधायक वहां पर पहुंचे, वहां पर हम इंतजार करते रहे, उमस भरी गर्मी के अंदर 45 डिग्री टेम्परेचर में हम वहां बैठे रहे। कुछ देर बाद बारिश भी शुरू हो गयी, बारिश में भीगते हुए हम अपने सिविल डिफेंस के साथियों के साथ, बस मार्शलों के साथ सड़क पर बैठे रहे, चार घंटे माननीय अध्यक्ष जी हमने इंतजार करा उसके बाद बहाने लगाने लगे कि जब मंत्री जी आयेंगे तभी हमारे बड़े नेता यहां पर पहुंचेंगे, तभी बिधूड़ी जी पहुंचेंगे, तभी हमारे सांसद जी पहुंचेंगे, तभी हमारे गुप्ता जी पहुंचेंगे। माननीय मंत्री जी भी वहां पर पहुंच गये कुछ देर बाद, एक डेढ घंटा

तक इंतजार करते रहे मंत्री जी, मंत्री जी ने अपनी बात वहां पर कही, तमाम हमारे जितने वहां पर हजारों की तादात में सड़क के उपर जो हमारे सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स बैठे हुए थे, बस मार्शल बैठे हुए थे उन लोगों से ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मैं कहता हूं हम बड़े जिम्मेदारी के साथ में कहते हैं कि आप बताईये हमें क्या लिख कर देना है, हम कोरे कागज पे लिख के देने के लिये तैयार हैं, वो तरह तरह के बहाने बनाते हैं कि जी आपने जो इनकी नियुक्ति की थी ये आपने नियम के विरूद्ध जाके की थी। नियम ये कहता है, नियम वो कहता है। तो आईये नियमों को सुधार लेते हैं, नियम भी तो सरकार ने बनाये हैं, हमारी सरकार उस नियम को भी देखने के लिये तैयार है आईये हमें क्या लिख के देना है, क्या सुधार करना है, क्या लाईन लिखनी है, आप लिख लीजियेगा हम कोरे कागज पे लिखने के लिये तैयार हैं लेकिन दस हजार लोगों को आप फिर से नौकरी पे बहाल कीजिये आपको बड़ी दुआएं मिलेंगी। अरविंद केजरीवाल जी ने दुआएं कमाने का काम किया था जो दस हजार लोगों को नौकरी दी थी और ये बद्दुआएं कमाने का काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये एलजी साहब बद्दुआएं कमाने का काम करते हैं। आज सोचिये उनके परिवारों से कितनी, उनके दिलों से कितनी हाय निकलती होंगी, कितनी उनके दिलों से बद्दुआएं निकलती होंगी जब उनके घरों में पैसे की तंगी होती है, जब उनके बच्चों की फीस नहीं जाती है, जब उनके घर का किराया नहीं जा पाता है। तो माननीय अध्यक्ष जी 11 तारीख को ही हमारी माननीय आतिशी जी ने ये लैटर भी लिखा जो हमारे

साथी कुलदीप जी ने भी पढ़ के सुनाया था, इसके अंदर साफ कह दिया गया कि हमारी सरकार इन दस हजार वॉलंटियर्स को फिर से बहाल करने के लिये तैयार है, हमारी सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है उनकी सैलरी देने के लिये, पहली सरकार है जो फायदे में चल रही है, हमारी सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है आपको क्या दिक्कत है, पैसा हमारी सरकार देना चाहती है आप क्यों उनको बहाल नहीं करना चाहते। तो आज मैं सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स से भी कहना चाहता हूं कि ये लगातार ड्रामे करते हैं, आज भी इन्होंने बहाना बना के सदन से वाकआउट कर दिया है, इनको पता था भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि आज चर्चा होने वाली है सिविल डिफेंस के उपर, तो हम चर्चा में भाग लेंगे तो हम क्या मुंह दिखायेंगे, क्या बोलेंगे, इसलिये बहाना बनाकर भाग गये। पिछली बार जब रेजोल्यूशन पास किया गया था इसी विधान सभा के अंदर तब भी ये भाग गये थे।

(समय की घंटी)

श्री रोहित कुमारः हमारे साथियों ने बताया रहमान जी ने किस प्रकार से जो हमने एक विधेयक यहां पर पास किया उसके बाद भी इन्होंने उसका बहाना बनाकर भागे हैं। तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस सदन से यही पुरजोर अपील करता हूं और हाथ जोड़ कर दिल्ली के उपराज्यपाल जी से भी ये विनती करता हूं कि दस हजार लोगों के परिवारों को देखिये, ये दस हजार लोग आपको बड़ी दुआएं देंगे, आज भी वक्त है आप सुधर जाईये। आज भी वक्त है कि आप इनको

नौकरी पे बहाल कर दीजिये, पिछले 10 महीने से, एक साल से ये सड़कों पर बैठे हैं, इधर से उधर दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। तो प्लीज हाथ जोड़कर मेरी रिक्वेस्ट है और भारतीय जनता पार्टी के साथियों से कहता हूं कि इलैक्शन नजदीक आ रहा है, अगर आप राजनीतिक नजरिये से भी देखें तो आपको इसका लाभ मिल सकता है, अगर आप सोचेंगे तो हम भी कह रहे हैं, हमारे साथी कुलदीप जी ने बोला सारा श्रेय आप ले लीजिये, सारा श्रेय आपको जाता है, आप इनको बहाल करा दीजिये, आप इनको बहाल कराईये ताकि इनके परिवारों को फिर से राहत मिल सके और ये दस हजार साथी दर बदर जो भटक रहे हैं इनको रोजगार मिल सके क्योंकि आज के जमाने में जो भी व्यक्ति बेरोजगार घर पे बैठा है उससे बड़ा अभिशाप कुछ भी नहीं है माननीय अध्यक्ष जी। तो मेरी पुनः इस सदन से, आपसे, एलजी साहब से और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार से भी मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि साढे दस हजार लोगों को फिर से नौकरी पे बहाल किया जाना चाहिये। बहुत बहुत धन्यवाद आपने इतनी महत्वपूर्ण चर्चा में मुझे अपनी बात कहने के लिये मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद रोहित जी। श्री ऋतुराज गोविंद जी।

श्री ऋतुराज गोविंदः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बोलने का मौका दिया। पूरी दुनिया में हमें लगभग, हमारे देश को आजाद हुए 75 साल से भी ज्यादा हो गया है

अध्यक्ष जी और हजारों लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी, तो देश को आजादी मिली। पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं डेवलप कंट्री हों, डेवलपिंग कंट्रिज हों, आप किसी की भी राजधानी के बारे में पढ़ेंगे तो किसी के भी बारे में ये नहीं कहा जाता है कि 'Rape Capital of this country' एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि 'Rape Capital of India is Delhi' कितनी शर्म की बात है और ये एक साल नहीं, लगातार कई सालों से कह रही है। और पूरी दुनिया में इस चीज को लेकर के हम लोगों को चिंता करना चाहिये। इसी को देखते हुए जब 2013 में हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही थी तो अरविंद केजरीवाल जी ने हम सब लोगों ने मिलकर जो स्टडी किया था उसके बिहाफ पर दिल्ली की महिलाओं को ये प्रॉमिस किया गया था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो महिला सुरक्षा हमारी प्राथमिकता होगी। दिल्ली के अंदर में सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी जिस दिल्ली पुलिस की है अध्यक्ष महोदय, वो दिल्ली पुलिस केंद्र की है, सैंटर की है। अगर आज दिल्ली के अंदर में ला एंड आर्डर की स्थिति बेहतर होती, दिल्ली के अंदर में सुरक्षा की भावना बेहतर होती, ये Rape Capital of India का टैग नहीं लगा होता। तो शायद हो सकता है कि हमें बस मार्शल्स की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन 2013 में जब चुनाव लड़ा था उसी वक्त अरविंद केजरीवाल जी ने ये प्रामिस किया था कि महिला सुरक्षा हमारी प्राथमिकता होगी, वर्क फोर्स पे जब हमारी महिलायें जायें तो सुरक्षित महसूस करें, world class transportation system भी हो, सुरक्षित महसूस भी करें, दूर दूर तक जा सकें, अपना काम कर सकें, सुरक्षित लौट सकें, ये

सुनिश्चित करना एक अच्छी सरकार की जिम्मेदारी होती है। इसी के लिए थ्री टीयर, थ्री लेयर सिक्योरिटी सिस्टम बसिसज के अंदर बनाया गया था। पहला पैनिक बटन, दूसरा सीसीटीवी कैमरा, तीसरा सुरक्षा गार्ड। हर काम पैनिक बटन और सीसीटीवी नहीं कर सकता है। लेकिन ये थ्री लेयर सिक्योरिटी सिस्टम इसलिए बनाया गया था ताकि महिलाओं के अंदर में सैंस ऑफ सिक्योरिटी जो है एक पोजिटिविटी आएगी और महिलाएं सुरक्षित महसूस करेगी, किसी भी परिस्थिति के अंदर में वो ट्रैवल करने से नहीं घबराएगी। एक तरफ आपने देखा कि जहां वर्ल्ड क्लास ट्रॉस्पोर्टेशन सिस्टम बनाया गया, जहां पर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया, यूरोपियन स्टैंडर्ड की सड़कें बनाई गई, वहीं दूसरी तरफ जो है महिलाओं को एक सैंस ऑफ सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए थ्री टीयर सिक्योरिटी सिस्टम बनाया गया। ऐसा क्या हुआ, 2015 में 10 हजार बस मार्शलस को डीटीसी की बससिज में और क्लस्टर बससिज में डिप्लोए किया गया महिलाओं की सुरक्षा के लिए। 8 साल तक उन लोगों ने शानदार काम किया, इसी दौरान कोरोना काल भी आया, इसी दौरान बहुत तरह के obstacles आए। कोरोना में बहुत सारे सिविल डिफेंस वॉलिटियर्स ने अपनी जान पर खेलकर के उन्होंने नागरिकों की सुरक्षा की, कई लोग तो अपनी जान दे भी दिये और जिसके बाद माननीया मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने तय किया कि जिस प्रकार से जो शहीद, जो सैनिक अपना शहादत देता है देश की रक्षा करने के लिए, अगर कोई सिविल डिफेंस वॉलियटियर दिल्ली वालों की रक्षा करने के लिए अपनी जान दिया है तो उसको भी एक करोड़ रुपया

उनको घर देकर के आए। माननीया मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सम्मान दिया है। 8 साल बाद आखिर ऐसा क्या हो गया कि उन 10 हजार गरीब, आज सिविल डिफेंस में कौन लोग थे, गरीब लोग थे, गरीब लड़के-लड़कियाँ थी, जेजे क्लस्टर में रहने वाले, रिसैटलमेंट कॉलोनी में रहने वाले, कच्ची कॉलोनी में रहने वाले प्रवासी लोगों के बच्चे थे, उनको रोजगार भी दिया गया था 10 हजार लोगों को नौकरी देकर के। वो अपने परिवार का भी सुरक्षा कर रहे थे, परिवार का भरण-पालन भी कर रहे थे और साथ में हमारे दिल्ली की बहन-बेटियों की, माताओं की, बहनों की, बुजुर्गों की, बच्चों की सुरक्षा भी सुनिश्चित कर रहे थे। आखिर क्या हो गया, 8 साल से ठीक चल रहा था, उसके बाद ऐसा क्या हो गया जो ट्रॉस्पोर्ट कमिश्नर तीन-चार साल से लगातार उसी काम को कर रहा था, वही ट्रॉस्पोर्ट कमिश्नर कुछ उल्टा-सीधी फाइल पर लिखने लग गया और वही ट्रॉसपोर्ट कमिश्नर आशीष कुंद्रा बाद में जाकर के वही लेफ्टिनेंट गवर्नर का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन गया। ये खेल क्या हम लोग को समझ में नहीं आता? खूब समझ में आता है अध्यक्ष महोदय और जिस तरीके से महिला सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया। इनका रिकॉर्ड है हमारे यहां बिहार में कहते हैं लंगड़ी मार पॉलिटिक्स । जिस चीज का मुकाबला नहीं कर सकते हो उसको लंगड़ी मार के गिरा दो और फिर बोलो ये तो दौड़ ही नहीं पाया। लेकिन एक चीज हमें समझना चाहिए अध्यक्ष जी, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे वो पंजाब की सरकार हो, हमारी सरकार नौकरी देना जानती है और आप नौकरी छीनना जानते हो। ये केवल और केवल सिविल

डिफेंस में नहीं हुआ, यही जो है सो महिला आयोग में भी हुआ। यही एमएलएज को फैलोज दिए गए थे उनसे भी इनको प्रोब्लम हो गई क्योंकि उनके माध्यम से हमारा काम तेजी से हो रहा था, उनको भी निकाला गया। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे कि दो करोड़ रोजगार देंगे हर साल और दूसरी तरफ जो अरविंद केजरी जी जो दिल्ली के बच्चों को जो नौकरी दे रहे थे महिला सुरक्षा के लिए अत्यंत जरूरी था उसको भी नौकरी लेने का काम किया और इतना ही नहीं किया, 6-6, 8-8 महीने की उनकी सैलरी रोक ली गई, उन बच्चों की जो कि गरीब थे, वो अपना परिवार मुश्किल से चला रहे थे, बच्चों की फीस मुश्किल से भर पा रहे थे, बूढे मॉं-बाप का मुश्किल से ईलाज करा पा रहे थे। आपने उनके उपर अत्याचार करने का काम किया। गरीब की हाय कभी नहीं लेना चाहिए हम लोग कहते हैं, गरीब की हाय सबसे बुरी होती है और वो हाय का असर होने लगा है, 400 पार का नारा दे रहे थे, 240 पर अटक गया उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा गरीब की हाय का क्या असर होता है। तो आने वाले समय में सुपड़ा-साफ हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि ये मंत्री तैयार हों, सदन रैजूलुशन पास कर दिया हो, क्या बोलते हैं फरवरी, 2024 के अंदर में, जनतंत्र में जनता इंपोर्टेंट होता है, डैमोक्रेसी की जो नींव होती है वो डैमोक्रेसी में फॉर दा पीपल ऑफ दा पीपल बाए दा पीपल का ही मतलब डैमोक्रेसी होता है। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हम हैं, जनता का सदन ये है, अगर ये सदन रैजूलुशन पास कर देती है उसके बाद भी ऐसा कौन

आदमी है जिनको जो सो इन 10 हजार लोगों को नौकरी पर बहाल करने में प्रोब्लम है। मंत्री लिखकर के दे रहा है कि इनको वापस जो है सो इनकी जुवाइनिंग करवाई जाए। सदन रैजूलुशन पास करता है इसी साल के फरवरी के महीने में कि इन 10 हजार लोगों को वापस नौकरी पर रखा जाए, उसके बाद ये लैफटीनेंट गवर्नर कौन होता है इनकी नौकरी लेने वाला। ये कौन लोग हैं जो इनके जो है चूल्हे बुझाना चाहते हैं। तो हम सब लोगों को मिलकर के इस लैफटीनेंट गवर्नर का और लैफटीनेंट गवर्नर की क्या औकात है, नरेंद्र मोदी के रिप्रेजेंटेटिव हैं ये और आज इन 10 हजार लोगों की नौकरी किसी ने ली है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ली है, उनको जवाब देना चाहिए। इन 10 हजार लोगों की नौकरी का सवाल है, दो करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं दिल्ली के अंदर में जहां पर महिलाओं की आबादी एक करोड़ से ज्यादा है। एक करोड़ महिला की जो असुरक्षा है उसकी जिम्मेदारी नरेद्र मोदी जी को लेना चाहिए और 10 हजार लोगों की जो नौकरी छिनी है उसकी जिम्मेदारी मोदी जी को लेना चाहिए और जल्दी से जल्दी वो 10 हजार लोगों को नौकरी वापस मिले ऐसी कोशिश होनी चाहिए और मैं तो सिविल डिफेंस वालंटियर से भी कहना चाहता हूं, आप लोग भी इधर-उधर जो प्रदर्शन करते रहते हो, 10 हजार आदमी अपने परिवार को लेकर के सीधा लेफ्टीनेंट गवर्नर के घर पर बैठो, लगातार बैठो, हम लोग भी आपका साथ देंगे और देखों कैसे तुम्हें नौकरी नहीं मिलती है। आप लोगों को भी सीखना पड़ेगा कि अपने हक और अधिकार की लड़ाई कैसे लड़नी है और ये देश बाबा साहब

अंबेडकर के संविधान से चलता है। हक और अधिकार की लड़ाई अगर लड़नी है तो संविधानिक दायरे में रहकर के अपनी आवाज को मजबूत करो, मजबूती से लड़ो फिर देखो कैसे अधिकार और हक नहीं मिलती है। ये भाजपाई जैसे सिविल डिफेंस की बात आती है भाग जाते हैं, उसका सामना नहीं कर सकते, इनको जवाब देना चाहिए, इनके लैफटीनेंट गवर्नर को जवाब देना चाहिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जवाब देना चाहिए। अध्यक्ष जी मैं यही कहना चाहता हूं अंतोदय, अंतोदय का खाली नारा लगाने से अंतोदय नहीं होगा, पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति का भला केवल नारा लगाने से नहीं होगा, पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति का भला काम करने से होगा। इसी बात पर हमारे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था स्वानों को मिलता दूध यहां, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, मां के छाती से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। गरीबी क्या होती है, भूखमरी क्या होती है, रोजगार क्या होता है, इन भाजपाईयों से, इन पूंजीपतियों के दलाल से कभी आप उम्मीद मत करना। कभी रोजगार की बात हो, गरीब की बात हो, मजदूर की बात हो, किसान की बात हो, आज मुझे बड़ी खुशी हुई मंत्री जी बने और यहां पर न्यूनतम मजदूरी बढ़ा दी। ये होती है गरीब की मदद करनी, मजदूर की मदद करनी। यहां पर न्यूनतम मजदूरी बीस हजार और नोएडा में है 10 हजार, आपकी सरकार है। हरियाणा में है 8 हजार, पड़ोसी राज्य लगा लो जहां पर भाजपा की सरकार है। सबसे ज्यादा दिल्ली में है। जब बात मजदूर की होगी, जब बात किसान की होगी, जब पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति की होगी, जब महिलाओं की

होगी, तो हमेशा आपको आम आदमी पार्टी, केजरीवाल सरकार का मॉडल पूरा देश देखता है।

माननीय अध्यक्षः चलिए, चलिए।

श्री ॠतुराज गोविंदः बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय मैं इस प्रस्ताव का फिर से क्योंकि ये दूसरी बार आया है, मैं फिर से यही कहना चाहता हूं कि इनकी appointment जल्द से जल्द हो, क्योंकि महिला सुरक्षा के लिए, इनके रोजगार के लिए ये बेचारे जो डेढ़ साल से जो दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, लड़के-लड़कियां इधर-उधर ठोकरें खा रहे हैं, उनसे भी मैं कहूंगा, अपनी लड़ाई को मजबूती से लड़ो हम सब लोग साथ में है, ये सदन आपके साथ है, सारे के सारे विधायक आपके साथ है, पूरी सरकार आपके साथ है क्योंकि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, इनको भी पता लगना चाहिए कि किस तरीके से ये लोग महिला विरोधी हैं, किस तरह से ये लोग बृजभूषण शरण जैसे लोगों को पनाह देने वाले लोग हैं, रेपिस्ट को माला पहनाने वाले लोग है। महिला सुरक्षा पर कभी कोई बात नहीं करते हैं, दिल्ली के अंदर में इनकी सरकार 10 साल से है आज भी एनसीआरबी भी कहता है रेप कैपिटल ऑफ इंडिया, रेप कैपिटल ऑफ इंडिया ये तमगा लेकर घूमते हैं, फिर बोलते हैं हम तो विश्वगुरू बनेंगे, विश्वगुरू बनेंगे, देश की राजधानी से रेप कैपिटल ऑफ इंडिया का तमगा तो हटा नहीं पाए, बड़े आए विश्वगुरू बनने वाले। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद गोविंद जी। अखिलेश पति त्रिपाठी जी। संक्षेप में रखिये जरा, अखिलेश जी।

श्री अखिलेशपति त्रिपाठीः धन्यवाद अध्यक्ष जी, आज हमारे पूर्व के वक्ताओं ने साथियों ने रखा की किस तरीके की पीड़ा दिल्ली के 10 हजार गरीब, मध्यम वर्ग के परिवार के बच्चों की जिसको हमारी सरकार ने एक पुनीत, एक पुनीत कर्तव्य के तहत, एक ऐसा काम जो हमारी महिलाओं को मजबूत करती थी, उनकी सुरक्षा को उनके सम्मान को सुनिश्चित करती थी, उसको लागू करने के लिए बसों में सिविल डिफेंस मार्शल्स की नियुक्ति की गई। अध्यक्ष महोदय आज मैं सदन के माध्यम से एलजी साहब को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आखिर आपको दिल्ली वालों से क्या दुश्मनी है, क्यों दिल्ली वालों को इस तरीके से सजा दे रहे हो? आज मैं सिविल डिफेंस वॉलियंटर से भी कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल का एक-एक सिपाही आपके साथ खड़ा है। इसी अरविंद केजरीवाल ने और इसी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, युवाओं के रोजगार को प्रमोट करने के लिए बस मार्शल की सुविधा दी थी। आप सबको नौकरी मिली, लेकिन आपको गुमराह करने का काम किया गया, पता नहीं किस बहकावे में आप आकर के इधर-उधर घुमते रहे। जिस अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के एक-एक लोगों के हक और हकुक की लड़ाई को लड़ा, एक-एक महिलाओं के सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए, महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए बस मार्शल को लगाने का काम किया, सीसीटीवी

कैमरा लगाने का काम किया दिल्ली भर में चार लाख से ज्यादा लाइटें लगाने का काम किया, महिलाओं के सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए उस अरविंद केजरीवाल जी ने सभी बसों में फ्री बस यात्रा देने का काम किया और अब जबसे एक हजार रुपये देने का काम किया है तब से भारतीय जनता पार्टी ज्यादा ही परेशान थी, वो भी योजना महिलाओं के सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए जो अरविंद केजरीवाल जी ने लाया वो भी अधिकारियों के माध्यम से रोके पड़े हैं अभी तक हुआ नहीं। तो इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी और इनके एलजी साहब जो बैठे हुए हैं और सही कहा ऋतुराज जी ने, ये एलजी की नियुक्ति किसने की, केंद्रीय मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री की सलाह पर इनकी नियुक्ति की गई है, पर भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। तो पूरी भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता महिला विरोधी आज यहां सदन के सामने साबित हो गया, पूरी दिल्ली के सामने साबित हो गया है। ये नहीं चाहते महिलायें सुरक्षित हो, उनका सम्मान बढ़े इसलिए महिलाओं के लिए जो-जो काम हमारी सरकार कर रही है, उसको रोकने का काम ये करते हैं, उसको काम होने नहीं देना चाहते हैं। एक बात ये आई कि महिला विरोधी मानसिकता के साथ ग्रसित होकर के एलजी साहब ने और भारतीय जनता पार्टी ने जो मार्शलस की नियुक्ति थी उसको रोकने का काम किया और यही नहीं रूका, इनकी महिला विरोधी मानसिकता ही नहीं है,ये युवा और रोजगार विरोधी मानसिकता के लोग भी यहां बैठे हुए हैं। हमारी सरकार ने 10 हजार लोगों को रोजगार देने

का काम किया, आप रोजगार छीनने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी एलजी के माध्यम से। मैं पूछना चाहता हूं सिविल डिफेंस वालंटियर से, आखिर सर्विसिज डिपार्टमेंट किसके पास है? बार-बार यही सदन प्रस्ताव पारित करके भेज रहा है, आखिर वो प्रस्ताव कौन नहीं मान रहा है? आज ये गौर करें हमारे सिविल डिफेंस के वालंटियर और आज आह्वान करना चाहते हैं कि आपके हक और हकुक की लड़ाई में हम लोग शामिल हैं। आप लोग अपने परिवार के साथ आइये, जिनके पास जिम्मेदारी है दिल्ली के लैफ्टिनेंट गवर्नर, जिन्होंने इस फाइल को रोका और जिन अधिकारियों ने फाइलों पर कुतर्क लिखकर के आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है उनके यहां चलकर के, उनके यहां बैठने के लिए हम लोग तैयार हैं। ये सदन कृतसंकल्प है कि जब तक एक-एक सिविल डिफेंस के वालियंटर्स को फिर से बहाल नहीं किया जाता, हम सब एक संकल्प पारित करते रहेंगे, इस संकल्प के साथ जरूरी है, आइये सिविल डिफेंस के साथियों आपके हक की लड़ाई ये सदन लड़ रहा है। बाहर आपके साथ लड़ेंगे, आप चलिए हम बैठकर के आपको न्याय दिलाने का काम करेंगे। जो रोक रहे हैं उनके घरों को घेरने का काम करिये, सातों सांसद बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक बैठे हैं, ना आपके साथ कभी खड़े हुए, ना इन्होंने सदन में कभी बोला और अभी जब सदन में चर्चा हो रही थी तो यही साथी यहां से भाग गए और बहाना बनाकर के कि उनके पक्ष में इनको बोलना ना पड़ जाए, कहीं उनको ये बोलना ना पड़ जाए कि हमारे गवर्नर ने, हमारे लैफ्टिनेंट गवर्नर ने इसको रोकने का काम किया है। तो शर्म करिये।

...व्यवधान...

श्री अखिलेशपति त्रिपाठी: वो आपके अधिकारी हैं। लैफि्टनेंट गवर्नर के अधिकारी हैं।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: महाजन जी मुझसे बात करिये। बैठिये, बैठिये।

...व्यवधान...

श्री अखिलेशपति त्रिपाठी: मैं आज सदन के साथ शेयर करना चाहता हूं, आज ये कह रहा हूं अरे दिल्ली के सीवरों की हालत तुम्हारे एलजी ने बुरा कर दिया है। मैं सदन में लेकर आया हूं इस पीड़ा को, आज सिविल डिफेंस के वालंटियर पर चर्चा हो रही है, भाग क्यों रहे हो?

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: जितेंद्र महाजन जी को बाहर करिये, बाहर करिये इनको। पूरे ही दिन के लिए बाहर, जितेंद्र महाजन जी को पूरे दिन के लिए बाहर। चलिए।

...व्यवधान...

श्री अखिलेशपति त्रिपाठी: तुम्हारे अंदर दम है तो सिविल डिफेंस वालंटियर्स के पक्ष में बोलो, बताओ उनको मिलना चाहिये कि नहीं

मिलना चाहिए, उनको बहाली होनी चाहिए की नहीं होनी चाहिए, सिविल डिफेंस के वालंटियर की बहाली होनी चाहिए की नहीं होनी चाहिए, आज भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं? पूरे दिल्ली के सिविल डिफेंस के वांलियंटर जानना चाहते हैं, बताइये आप सिविल डिफेंस के वालियटर्स को बहाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइये आप?

माननीय अध्यक्षः कन्कलूड करिये।

श्री अखिलेशपति त्रिपाठीः भाग क्यों रहे हैं चर्चा से?

माननीय अध्यक्षः अखिलेश जी कन्कलूड करिये।

श्री अखिलेशपति त्रिपाठीः मैं कन्कलूड कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय बार-बार हमारे मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया कि सिविल डिफेंस के वॉलियटर्स बहाल होने चाहिए। उसको ऑर्डर के रूप में हमारे ट्रॉस्पोर्ट मिनिस्टर ने कहा कि उनको जो है होमगार्डस के रूप में उनको बहाल कर दीजिए, उनको किसी भी तरीके से उनके रोजगार को बचा लीजिए। हमारी सरकार मिन्नत करती रही, आतिशी जी लगातार उसपर लिखती रहीं, मिन्नतें करती रही गवर्नर जनरल से, ये गवर्नर बैठे हुए हैं हमारे.. लेकिन सुना नहीं गया।

माननीय अध्यक्षः भई अब हो गया अखिलेश जी कन्कलूड करिये प्लीज।

श्री अखिलेशपति त्रिपाठीः अध्यक्ष महोदय, अब आपके सदन के माध्यम से मुझे आपकी कुर्सी से उम्मीद है कि इन सिविल डिफेंस के वॉलियटर्स को न्याय दिलाने का काम करिये और जिन लोगों ने बार-बार प्रस्ताव पारित होने के बावजूद इस प्रस्ताव की अवहेलना की है, ये मामला पूरा ब्रीच ऑफ प्रिविलेज समझकर के उन अधिकारियों के खिलाफ सदन में ये ब्रीच अफ़ प्रिविलेज विशेषाधिकार समिति को ये मामला दिया जाना चाहिए कि ये मामला केवल और केवल सिविल डिफेंस वॉलियटर्स तक सीमित नहीं रह गया है। अब सदन की गरिमा का भी सवाल है, सदन की गरीमा की भी धज्जियॉं उड़ाई जा रही हैं, इसलिए आप संज्ञान लें और ये मामला विशेषाधिकार समिति को भेजकर के न्याय दिलाए, जो अधिकारी नहीं काम कर रहे उनपर कार्रवाई होनी चाहिए, जयहिंद, जयभारत।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद। श्री भूपेंद्र सिंह जून जी।

श्री बी.एस. जूनः धन्यवाद अध्यक्ष जी, सर 2012 में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे देश को हिला दिया। वो घटना थी निर्भया रेप और मर्डर केस। उस इन्सीडेंट के बाद पूरे देश में एक बहस शुरू हुई की महिला सुरक्षा को मजबूत किया जाये। कानून में बदलाव किया गया कमेटियां बनीं, कमीशन बने कुछ recommendations हुईं और उनके बेस पर कुछ ना कुछ improvement भी की गई। 2015 में दिल्ली सरकार ने भी एक स्कीम लेकर आये मार्शल की क्योंकि buses में बहुत घटनायें होती थीं eve-teasing की pick- pocketing की और ये दूसरा

chain snatching वगैरह की। सर human tendency है कि अगर यूनिफार्म में एक कांस्टेबल किसी traffic intersection पर खड़ा हुआ है तो लोगों की हिम्मत नहीं होती कि वो उसको जंप कर जायें रेड लाइट को, इसी प्रकार जब ये मार्शल्स की डिप्लोएमेंट हुई तो उसका बहुत अच्छा इफैक्ट हुआ बसों में, ये जो घटनायें थीं उनको curb किया गया, ये घटनाओं में कमी आई क्योंकि जब यूनिफार्म में कोई आदमी किसी बस में ट्रैवल कर रहा है चाहें वह पुलिस का था हर लोग यही सोचते थे ये पुलिस का आदमी है, सिविल डिफेंस का नहीं है। तो जो क्रिमिनल्स थे या anti-social elements, miscreants थे उनके दिल में एक डर बैठा और महिलाओं में सुरक्षा की भावना मज़बूत हुई। तो ये माननीया मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का ये बहुत अच्छा स्टैप था जिससे ये स्कीम बहुत पोपुलर हुई लेकिन on the contrary दूसरी साइड में एल.जी. साहब हों या बीजेपी के लोग हों उनको ये रास नहीं आया कि इतनी पोपुलर स्कीम दिल्ली में चल रही थी और ये स्कीम हर जगह appreciate की गई कि महिला सुरक्षा के लिये बहुत अच्छा कदम उठाया धीरे-धीरे करके जो marshal deployment हुआ था उनको harass करना शुरू कर दिया, सैलरी टाइम पर नहीं मिलती थी, कभी-कभार ड्यूटियां मिलती नहीं थीं या मैक्सिमम मिलती तो 28 दिन की ड्यूटी मिलती थी क्योंकि इनको मालूम था अगर regularly without break 180 दिन की सर्विस ये लोग कर जायेंगे फिर इनको बाहर निकालना मुश्किल हो जायेगा। तो harassment day one से ही इनकी स्टार्ट हो गई थी लेकिन ऑलओवर स्कीम चलती रही 2015 में deployment हुई और 2023 में एक

टैक्निकल ग्राउंड पर आगे इनकी services terminate कर दीं। वो क्या था की सिविल डिफेंस एक्ट में प्रोविजन है कि इनकी deployment सिर्फ natural calamities या natural disaster के टाइम ही की जा सकती है अदरवाइज़ इनसे दूसरी ड्यूटिज़ नहीं ली जा सकती। ये टैक्निकल ग्राउंड था सर जिसको कभी भी rectify किया जा सकता था। ये लोग गरीब परिवार से आते थे एक झटके में आठ से दस हज़ार Civil Defence Volunteers की, मार्शल्स की सर्विस खत्म कर दी गई। उधर women safety का मुद्दा दोबारा से जागृत हो गया और इधर इनकी फैमिली का सवाल था। तो humanitarian ground पर इसको नहीं सोचा गया, अदरवाइज़ क्या होता कि इनको एबजॉर्व कर सकते थे होमगार्ड्स में या किसी में भी। कुछ दिनों बाद माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने एल.जी. साहब से मुलाकात की उनको कहा की भई आप जो है इनको रेगुलराइज़ कर दो और इन लोगों की सर्विस मेंटेन रहने दो। उन्होंने कहा नहीं हम होमगार्ड्स में recruitment करेंगे और इनको कन्सीडर करेंगे। फिर advertisement आती है सर advertisement उनको preference देने की बात कहीं भी नहीं थी, उन लोगों को preference नहीं दिया गया और शायद आजकल recruitment चल रही है most of the जो employees थे उनको disqualify किया जा रहा है। ये बहुत बुरी मतलब दुर्भाग्य की बात है कि उन इम्लोइज़ को जानबुझकर आज disqualify किया जा रहा है ताकि वो दोबारा से सर्विस में ना आ सकें। तो माननीय अरविंद केजरीवाल की रिक्वेस्ट पर भी एल.जी. साहब ने ये ना तो इनको प्रिफरेंस देने की बात की और ना उनको रेगुलराइज़ किया, ना

उनको छः महीने की सर्विस के बाद absorb करने की बात उनमें कही गई। तो सर ये बहुत ऐसा गंभीर मुद्दा था दस हज़ार परिवारों पर रोजी-रोटी का तो सवाल था ही, सबसे बड़ा मुद्दा था कि महिला सुरक्षा का क्या होगा। निर्भया कांड के बाद हम बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे अगर कोई government sincerely कोई स्टैप लेती है उस पर obstacles आती है, hurdles आती है और जानबूझकर ऐसी स्कीम्स को फेल किया जाता है। ये लोग पिछले एक-डेढ़ साल से सड़कों पर भटक रहे हैं, अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास जा रहे हैं रेगुलराइजेशन के लिये या reinstatement के लिये कि भई इनको दोबारा से वापस लिया जाये लेकिन भारतीय जनता पार्टी या एल.जी. साहब के कान पर कोई जूं नहीं रेंग रही और मुझे नहीं लगता कि जब तक ये सिस्टम ऐसा ही चलता रहेगा ये इनको reinstate कर पायेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी डे वन से इनके लिये reinstatement के लिये संघर्ष करती रही है और करती रहेगी आगे और हम चाहते हैं इस सदन के माध्यम के थ्रू कि एल.जी. साहब इसको reconsider करें, इन लोगों को reinstate करें और इनको जो होमगार्ड की भर्तियां चल रही हैं उनको प्रिफरेंस दी जाये ताकि दस हज़ार परिवारों का भला हो सके, बहुत-बहुत धन्यवाद सर।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद जून साहब, श्री मोहन सिंह बिष्ट जी।

श्री मोहन सिंह बिष्टः आदरणीय अध्यक्ष जी वास्तव में बेरोजगारी और जिस प्रकार के पढ़े-लिखे बच्चे बेरोजगार हो जायें ये हम सब लोगों

को उसकी चिंता होनी चाहिये ये एक ऐसा अच्छा कार्य है कि इसमें हमको चर्चा करनी चाहिये कि चर्चा हो कि किसी का घर बरबाद ना हो, उसकी हम सब लोगों को चिंता करनी चाहिये। अध्यक्ष जी मेरा आपसे करबद्ध प्रार्थना है और मेरे को लगता है कि शायद आपने चिंता जाहिर की होगी कि जिन बच्चों को मार्शल के रूप में एपोइंटमेंट दी गई थी आखिर उन बच्चों को वहां तक उनकी रोजी-रोटी की व्यवस्था किसने करनी थी, वो सरकार ने करनी थी। सरकार ने उसमें कोई भी ऐसा पहलु नहीं देखा जिसकी वजह से उनकी रोज़ी और रोटी बनी रहे, ये मैं कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय हम ही ने सुना है इसी सदन के अंदर, दिल्ली के अंदर अखबारों में छाया है। मैं ये नहीं कह सकता कि सारे मार्शल एक जैसे हो सकते हैं लेकिन कई मार्शलों की ये हालत को देखकर के बस के अंदर सरेआम रेप किया गया, क्या हमने उनका करैक्टर देखा, क्या हमने उसके बारे में पुलिस की identification दी और कोई identification नहीं हुई।

...व्यवधान...

श्री मोहन सिंह बिष्टः ऐसे लोगों को भर्ती कर दिया गया।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः भई बारी आयेगी बोलने की, उनको बोलने दीजिये।

श्री मोहन सिंह बिष्टः अध्यक्ष महोदय।

माननीय अध्यक्षः बारी आयेगी बोलने की तब बोलेंगे।

श्री मोहन सिंह बिष्टः अध्यक्ष महोदय।

माननीय अध्यक्षः जवाब दीजियेगा आप, प्लीज़।

...व्यवधान...

श्री मोहन सिंह बिष्टः अध्यक्ष महोदय, मेरा तो सीधा-सीधा कहना है कि ये पूरा सदन बैठा है हम सब लोग भी आपने कहा, तुरंत हम अंदर आये हैं हम, समर्थन करो ना ऐसे लोगों का। मुझे आपसे एक बात और कहनी है इन मार्शलों को पक्का करने की योजना क्यों नहीं बनाई गई? आज हम घोषणा कर रहे हैं कि मज़दूर की इन्कम 18 हज़ार उसकी बेसिक पे, अरे तुमने उनको तो आज तक तुम कर नहीं सके, दिल्ली के अंदर कोई ऐसी industries खोल नहीं सके जिससे लोगों को रोज़गार मिले, आपने ऐसा नहीं किया। अध्यक्ष महोदय दूसरी ओर देखते हम सब लोग दिल्ली के लोग हैं दिल्ली के बारे में हम सब लोगों को चिंता करनी चाहिये यदि केन्द्र सरकार से, अभी बोल रहे थे इसी सदन के अंदर, राशन कार्ड जो नहीं बन रहे हैं उसके लिये दोषी कौन है?

...व्यवधान...

श्री मोहन सिंह बिष्टः दोषी ये सरकार है। इस सरकार ने 2015 के बाद एक भी राशन कार्ड नहीं बनाया।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः भई कुलदीप जी आपके विधायक उत्तर देंगे ना।

श्री मोहन सिंह बिष्टः और राशन कार्ड जिन लोगों को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा।

माननीय अध्यक्षः मदन लाल जी की बारी है वो उत्तर देंगे, जरनैल सिंह की बारी है वो उत्तर देंगे।

...व्यवधान...

श्री मोहन सिंह बिष्टः अध्यक्ष महोदय।

माननीय अध्यक्षः ऐसे तो नहीं चलेगा।

...व्यवधान...

श्री मोहन सिंह बिष्टः हमने यही सदन देखा है।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः ऐसा नहीं चलेगा प्लीज़, चलिये।

...व्यवधान...

श्री मोहन सिंह बिष्टः सर मैं आपसे एक निवेदन, आप कंट्रोल, अरे हुआ ना, हुआ ना रेप बस के अंदर, क्यों नहीं हुआ।

माननीय अध्यक्षः मोहन सिंह बिष्ट जी।

श्री मोहन सिंह बिष्टः सर सर।

माननीय अध्यक्षः एक सेकेंड-एक सेकेंड-एक सेकेंड बैठ जाईये आप। क्या सरकार के और विभागों में, पुलिस विभाग में किसी और में क्या आज तक कोई रेप नहीं हुये, क्या सबके लोगों को.

श्री मोहन सिंह बिष्टः जिन लोगों को आप, अध्यक्ष जी आप.

माननीय अध्यक्षः सुन लीजिये बात को, फालतू मत बोलिये आप, आप दिल्ली की महिलाओं की बेइज्जती कर रहे हैं।

श्री मोहन सिंह बिष्टः मैं महिलाओं के पक्ष में ही बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं।

माननीय अध्यक्षः क्या और विभागों में, क्या वो विभाग बंद कर दिये गये?

...व्यवधान...

श्री मोहन सिंह बिष्टः यदि आप आइडेंटिफिकेशन करवाते, उनकी जानकारी लाते तो कभी इस प्रकार का नहीं होता। हम समर्थन के पक्ष में हैं हम जब बोल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी ओर कहना चाहता हूं इसी सदन....

माननीय अध्यक्षः मदन लाल जी इसके बाद आपकी बारी है, बैठिये। मदन लाल जी इसके बाद आपकी बारी है।

श्री मोहन सिंह बिष्टः अध्यक्ष महोदय।

माननीय अध्यक्षः और कुछ कहना है आपने।

श्री मोहन सिंह बिष्टः अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक करबद्ध प्रार्थना करना चाह रहा हूं आप प्रस्ताव रखिये ना, करिये ना regularization आपके हाथ में सब कुछ है आपने हमको हाउस से बाहर कर दिया क्योंकि ये आपका अधिकार क्षेत्र है लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इसी सदन के अंदर चर्चा करना चाहता हूं हमने देखा है 2015 से पहले AAY के कार्ड बनते थे, बीपीएल के कार्ड बनते थे।

माननीय अध्यक्षः भई अब चर्चा जिस विषय पर उस पर बात करिये।

श्री मोहन सिंह बिष्टः अरे भाई साहब आप जब यहां चर्चा क्यों बोली तुमने, तुमने राशन के बारे में क्यों बोला।

माननीय अध्यक्षः चर्चा पर जो बात हो रही है।

श्री मोहन सिंह बिष्टः तुमने क्यों नहीं बनाये राशन कार्ड?

माननीय अध्यक्षः जिस विषय पर चर्चा हो रही है उस विषय पर रहिये।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः राशन कार्ड पर भी चर्चा करवा देंगे।

श्री मोहन सिंह बिष्टः मैं सर उसके पक्ष में खड़ा, मैं मार्शलों के पक्ष में, गरीब को रोजी-रोटी मिलनी चाहिए।

माननीय अध्यक्षः आप बस मार्शल पर चर्चा करिये।

श्री मोहन सिंह बिष्टः यदि आपका मार्शल इतना ही वो था, आज होमगार्ड की भर्तियां चल रही हैं, होमगार्ड भर्ती हो रहे हैं सर, यदि उनमें क्वालिफिकेशन है, वो वास्तव में जा सकते हैं तो होमगार्ड के थ्रु भी तो आ सकते हैं। दिल्ली के अंदर एल.जी. महोदय ने होमगार्ड के लिये भी तो इस प्रकार की व्यवस्था रखी हैं। मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाह रहा हूं।

श्री कुलदीप कुमारः ये लोग चाहते ही नहीं हैं।

श्री मोहन सिंह बिष्टः अरे कौन नहीं चाहता, आप पक्का करो ना।

माननीय अध्यक्षः भई कुलदीप जी आपके विधायक उन्हें उत्तर दे रहे हैं ना।

श्री मोहन सिंह बिष्टः आप पक्का करो ना उनको, आप प्रस्ताव लाओ ना।

श्री विजेंद्र गुप्ता (माननीय नेता प्रतिपक्ष): पक्का करो।

माननीय अध्यक्ष: भई मुझे ये बात पसंद नहीं आती, कुलदीप जी प्लीज,

श्री मोहन सिंह बिष्ट: हम बिल्कुल विरोध नहीं करेंगे। अध्यक्ष महोदय हम बिल्कुल विरोध नहीं करेंगे।

माननीय अध्यक्ष: बैठिये, बैठिये मोहन सिंह बिष्ट जी अब हो गया।

श्री मोहन सिंह बिष्ट: अब इनको बोलिये प्रस्ताव लाओ, प्रस्ताव लाकर के आप तय करो ना अभी।

...व्यवधान...

श्री मोहन सिंह बिष्ट: हम उनके पक्ष, सर मैं विरोध ही नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं प्रस्ताव लेकर आओ ना, पक्का करो ना, हमारा पूरा विपक्ष पूरा उनका समर्थन करेगा। मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूं, इस सदन से जानना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिये कि जिन मार्शलों की नियुक्ति की हम सब लोगों को चिंता है, तो हम प्रस्ताव क्यों नहीं ला सकते, इस सदन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव लायें, आप पेश करो ना।

माननीय अध्यक्ष: अभी प्रस्ताव भी आयेगा। एक प्रस्ताव बना लीजिये, ले आईये।

श्री मोहन सिंह बिष्ट: प्रस्ताव लाओ ना, पेश करो ना। हम इनके पक्ष में, मैं भी तो पेश कर रहा हूं।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: रोहित जी, रोहित जी ये तरीका ठीक नहीं है प्लीज़।

श्री मोहन सिंह बिष्ट: सर ये हमको बोलने नहीं देते।

माननीय अध्यक्ष: हो गया।

श्री मोहन सिंह बिष्ट: सर ये हमको बोलने नहीं देते।

...व्यवधान...

श्री मोहन सिंह बिष्ट: जिस प्रकार से।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: रोहित जी नीचे बैठिये, रोहित जी।

श्री मोहन सिंह बिष्ट: बोला है ना प्रस्ताव लेकर आओ, प्रस्ताव क्यों नहीं लाते तुम।

...व्यवधान...

श्री मोहन सिंह बिष्ट: तुम्हें क्या खतरा है लेकर आओ, सरकार तुम्हारी है ना।

माननीय अध्यक्षः आप दोबारा ले आईये ना, क्या दिक्कत हो रही है।

श्री मोहन सिंह बिष्टः तुम क्या कहते थे, इसी सदन में ये कह दिया ना।

माननीय अध्यक्षः पास करवाईये ना।

...व्यवधान...

श्री मोहन सिंह बिष्टः हम एल.जी. को नहीं मानते, हम उनको नहीं मानते, आखिर क्यों नहीं ला सकते हो प्रस्ताव?

माननीय अध्यक्षः मोहन सिंह जी बैठिये।

श्री मोहन सिंह बिष्टः क्या बात कर रहे हो।

...व्यवधान...

श्री मोहन सिंह बिष्टः सदन को गुमराह मत करो, सदन का टाइम बरबाद मत करो।

माननीय अध्यक्षः मोहन सिंह जी बैठिए। नहीं हो गया, बहुत हो गया, प्लीज़।

श्री मोहन सिंह बिष्टः नहीं ये तो गलत तरीका है जिस प्रकार से टोकाटाकी हो रही है।

माननीय अध्यक्षः नहीं हो गया, आपने बात रख दी अपनी, मदन लाल जी।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः भई रोहित जी, आप बैठिये चुप।

श्री मदन लालः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।

माननीय अध्यक्षः ये कोई तरीका नहीं है सदन चलाने का, बैठिये प्लीज़, मदन लाल जी।

श्री मदन लालः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस ज्वलंत मैटर पर बोलने का अवसर दिया। 2014 में एक बहुत ही ज्यादा फरेबी सरकार पर भरोसा करके लोगों ने उन्हें सत्ता सौंप दी, ये बीजेपी की सरकार थी। उस समय लोगों ने सोचा था कि देश का भला होगा, हिन्दुस्तान विश्व गुरू बनेगा, यही सरकार कहती थी कि लोगों को पंद्रह लाख भी आयेंगे और रोज़गार देंगे सबको, आज मैं उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं। हिन्दुस्तान में एक रिपोर्ट के मुताबिक 29 साल तक के नौजवान 83 परसेंट बेरोजगार है इस सरकारी रिकार्ड में 83 परसेंट और सर 2014 में जब सरकार आई तो उसके बाद बेरोजगारी का आलम ये था की 9.4 परसेंट पूरे इंण्डिया में बेरोजगारी थी। दिल्ली में 2.1 परसेंट, कहां 9.4 परसेंट कहां 2.1 परसेंट दिल्ली। सर इसका एक कारण ये भी था की यहां माइग्रेटिड पोपुलेशन बहुत ज्यादा आती है और जैसा मैंने कहा कि 2014 पर लोगों ने भरोसा करके मोदी जी की

जिस सरकार को चुना था उन्हें भरोसा था कि देश की इकॉनॉमी सुधरेगी, बेरोजगारी दूर होगी, लोगों को जो inflation है, जो मंहगाई है, वो कम होगी और जब ये सब कुछ नहीं हुआ तो लोगों ने अपनी-अपनी जगह से माइग्रेट करना शुरू किया। उसमें लोग दिल्ली भी आये। आज कई बार मैं अपने दफ्तर में देखता हूं कि पहले जो लोग प्राइवेट स्कूल की बात करते थे और वहां के लिये रिक्वेस्ट करते थे अब वो ये कहते हैं कि अब हम प्राइवेट स्कूल पढ़ा नहीं पा रहे हैं, अपफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, मंहगाई बहुत ज्यादा है और सरकारी स्कूल दिल्ली के बहुत अच्छे हो गये हैं लिहाज़ा हमने अपने बच्चे गांव से अभी बुलाये हैं आप सरकारी स्कूल में एडमिशन करा दो, ये माइग्रेशन करा दो, ये इसी माइग्रेशन ने लोगों को उत्तेजित और उत्साहित किया कि वो दिल्ली जैसे शहरों में जाकर बसे हैं। यही कारण है कि माइग्रेशन की वजह से और शायद इसका एक और कारण भी है जहां-जहां unemployment बढ़ी है बेरोजगारी बढ़ी है उसके कारण हैं unskilled labour माइग्रेशन और उसका भी सबसे ज्यादा बड़ा एजुकेशनल सिस्टम। हमारे देश में जहां माननीय केजरीवाल जी ने दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम में बिज़नेस केरिकुलम जैसे सब्जैक्ट डालकर लोगों को स्कूल की शिक्षा के साथ ही बिज़नेस करने का एक आइडिया देना शुरू कर दिया।

माननीय अध्यक्षः मदन लाल जी विषय पर आईये प्लीज़।

श्री मदन लालः सर मैं आ रहा हूं उसी पर आ रहा हूं जिसके लिये आप शोर मचा रहे थे आप लोग।

...व्यवधान...

श्री मदन लालः मैं आ रहा हूं होमगार्ड पर ही आऊँगा सर।

माननीय अध्यक्षः वहीं से शुरू करिये प्लीज़।

श्री मदन लालः सर मुझे पता है मैं होमगार्ड पर ही हूं।

माननीय अध्यक्षः होमगार्ड से ही शुरू करिये।

श्री मदन लालः सर मैं होमगार्ड पर ही हूं होमगार्ड पर।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः नहीं ओमप्रकाश जी में रोक रहा हूं ना उनको।

श्री मदन लालः सर जितनी देर ये टोकेंगे।

माननीय अध्यक्षः आप करिये, करिये।

श्री मदन लालः सर इनका काम है हम बोलें ना, प्लीज़ आप।

माननीय अध्यक्षः मदन लाल जी आप विषय पर रहिये प्लीज़।

...व्यवधान...

श्री मदन लालः सर यही कह रहा हूं कि यहां जिस तरीके से एजुकेशन का सिस्टम और ज्यादा बढ़ा है, माइग्रेशन भी बढ़ा है। लोगों की इच्छा है वो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ायें।

उससे निकलने वाला बच्चा बिज़नेस करता है और जो माइग्रेशन करके आ रहा है या जो दिल्ली का जिस आदमी को opportunity नहीं मिली वो कहीं ना कहीं नौकरी तलाश करता है। दिल्ली की पिछली महिलाओं के साथ बसों में हुई घटना ने सरकार को झंकझोर करके रख दिया था। यही कारण था कि 2015 में जो सिविल डिफेंस 1963 से चल रही थी जो 40 डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार में कार्यरत हैं सरकार ने सोचा कि क्योंकि दिल्ली पुलिस अवेलेबल नहीं हो पाती हर बस में और महिलाओं को सबसे ज्यादा इसकी जरूरत है क्योंकि लगातार ऐसी-ऐसी घटनायें हो गई जहां सीसीटीवी कुछ नहीं कर पाये। जहां पैनिक बटन आपके काम नहीं आयेगा, आपको तुरन्त महिला की मदद करनी है और बहुत सारे लोग यहां पर मूकदर्शक बने होते हैं क्योंकि कई बार जो अपराधी जो है वो बहुत ज्यादा छिंछोरा और ताकतवर है। उसके लिए बस मार्शल की जरूरत थी। मैं अपने इन साथियों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि शायद आप लोग ये भूल गए कि सिविल डिफेंस के वॉलेन्टीयर्स की ट्रेनिंग होती है। दो महीने की ट्रेनिंग है सर उनकी। पूरी जांच पड़ताल के बाद ये सिविल डिफेंस के वर्कर की नौकरी दी जाती है। ये प्रोसेस है सरकार का और वो प्रोसेस कौन चलाता है, दिल्ली सरकार के अधिकारी चलाते हैं। हरेक आदमी का, एक-एक का antecedent चैक किया जाता है और मैं सबकी इनकी खासकर जानकारी बता दूं। सर आज दिन तक एक भी सिविल डिफेंस के वॉलेन्टीयर के खिलाफ किसी ने, चाहे महिला हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो कोई और हो, एक भी शिकायत नहीं की है। आज जिस तरीके से हमारे दोस्त

महिलाओं का character assassination कर रहे थे। आप कह रहे थे उनका antecedent भी चैक किया, उनका पिछला इतिहास चैक किया। तो क्या आप अंगुली उठा रहे है कि वो गलत हो सकती है। आपको कहने से पहले बहुत बार सोचना चाहिए। आप कह किनके बारे में रहे है, हमारी बहन बेटियों के बारे में। वो लोग जो हम लोगों की सुरक्षा के लिए लगाई गई हैं और सर जो नौकरी दे रहा है, जिन्होंने 2015 में सिविल डिफेंस के वॉलेन्टीयर्स को बसों में लगाया, नौकरी दी। भला कौन कैसे मान लेगा कि वो उनकी नौकरी खाना चाहते हैं, उन्हें बेरोजगार करना चाहते हैं। कौन मानेगा और क्यूं मानेगा। सर माननीय केजरीवाल जी ने तो लोगों को, उन दस हजार वॉलेन्टीयर्स को नौकरी दी और नौकरी देकर अपना हिस्सा बनाया कि वो सरकार का हिस्सा बनें और महिलाओं और बच्चो और बुजुर्गों की रक्षा करें। ये ही कारण था कि वो लगातार 2023 तक काम करते रहे। पर चूंकि एक और सैंन्ट्रल गवर्नमेंट लोगों को employment नहीं दे पा रही है। जैसा मैने कहा कि 83 परसेंट यूथ 29 साल की उम्र तक का बेरोजगार है उसको अपने काम के नौकरी नहीं मिल रही है। उस बड़ी सरकार को लगा कि इनकी पोपोलेरिटी अगर खत्म करनी है तो एक-एक जगह से काटना होगा। ये ही कारण है कि अप्रैल 2023 में पहले उनकी तनख्वाह बंद की फिर उनको नौकरी से बेघर कर दिया। तो आपने एक और जहां दिल्ली सरकार से बदला लिया दिल्ली के लोगों से वहीं आपने अपनी बहन बेटी और मॉं को निराश छोड दिया। डर के साये में जीने को बाध्य कर दिया। आज दिल्ली की बसों में आपके पास सिक्योरिटी नहीं

है और बहाना क्या था कि वहां सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। वहां तो पैनिक बटन है और पैनिक बटन दबेगा तो रक्षा कौन करेगा? पैनिक बटन किसी को इन्वाइट करने के लिए है कि वो उसकी मदद करे। सर ये जानबूझकर किया हुआ एक शडयंत्र है। दिल्ली विधान सभा लगातार इस ओर पहले से भी कई बार ये कहती रही है कि इन लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए और दिल्ली सरकार ने तो नौकरी दी थी। तो नौकरी छीनेगा कौन, जो दिल्ली सरकार के विरूद्ध काम कर रहा है। जो दिल्ली सरकार को नहीं चाहते कि कोई ऐसा काम करे। सर दिल्ली सरकार लोगों के भले के लिए हमेशा से कार्यरत है। जिस तरीके से अभी दो दिन पहले कल माननीय मंत्री हमारे लेबर मिनिस्टर ने 18 हजार, 20 हजार और 22 हजार रूपये की तनख्वाह घोषित की है, ये बहुत सराहनीय कदम है। हमारी सरकार काम देना चाहती है। हमारी सरकार लोगों को बढ़ोतरी करना चाहती है। हमारे यहां मंहगाई दर सबसे कम है। हम दिल्ली में लोगों को इतना ज्यादा स्पोर्ट करते हैं कि पानी, बिजली, एजूकेशन चिकित्सा ये सब फ्री है, बस फ्री है। तो लोगों के खर्च कम किये जा रहे है। आप लोगों की नौकरी खत्म कर रहे हो। बार-बार लोगों को गुमराह करते हो कि ये तो केजरीवाल जी की सरकार है, जिन्होंने आपके पक्का करने के, पक्का सर्विस तो आपके पास है। आप तो सर्विस में हाथ ही नहीं लगाने देते। सर्विस में लोग आपके बैठे हैं। आप ही लोग हो जो उनको बार-बार बढ़ोतरी देते हो कि वो ऐसे काम करें जिससे केजरीवाल जी की सरकार बदनाम हो। सर आज अगर हमारा एजूकेशन सिस्टम ठीक होगा तो बहुत सारे लोगों

को और रोजगार मिलेगा। ये सरकार उस ओर कार्यरत है। जिस तरीके से सिविल डिफेंस के लोगों की नौकरी खत्म की है इस सरकार ने सर ये बेहद शर्म की बात है और उससे भी ज्यादा बेशर्मपन ये है कि आप महिलाओं की तरफ अंगुली उठाने लगे हो। अब आप नौकरी देने से तो रहे, उनके चरित्र का हनन कर रहे हैं, ये आपको सोचना चाहिए। हम भले ही किसी राजनैतिक पार्टी से आते हों, पर जब हम इस सदन के हिस्सा हैं तो दिल्ली की हर बहन बेटी हम सबकी अपनी है। हमको उनका सम्मान करना है और उनके सम्मान के लिए जरूरी है कि ये जो सिविल डिफेंस के लोग है अभी आपने कहा होम गार्ड का हो रहा है ये। होम गार्ड वाले भी हमारे भाई बहन हैं। पर सवाल ये है कि 2023 में आप नौकरी खत्म करेंगे सिविल डिफेंस के वॉलेन्टीयर्स की और सितम्बर 2024 में आप नये लोगों की भर्ती करने की बात शुरू करेंगे। तो जो डेढ़ साल है उसने आपके इस काम के द्वारा लोगों को सजा दी गई है। आपने ना केवल उन दस हजार लोगों की नौकरी खत्म की है बल्कि डेढ़ साल तक उन महिलाओं को बच्चों को, बुजुर्गो को जो सिक्योरिटी मिल रही थी आपने उसको जान बूझकर खत्म किया। ये बेशर्मपन है। आपको सोचना होगा और लोग सब जानते हैं कि आप जो मीठी-मीठी बातें करके दूसरे की तरफ इशारा करके लोगों को भ्रम में डालने की कोशिश करते हैं। वो सब लोग जानते हैं कि नौकरी देने वाला नौकरी खत्म नहीं करता। माननीय केजरीवाल जी ने नौकरी दी थी। माननीय केजरीवाल जी ने उन सभी को इज्जत दी थी। अपनी माँ, बहन, बेटी को इज्जत दी और उनकी इज्जत को बरकरार रखने के लिए

उसमें बसों में मार्शल लगाये थे। वो मार्शल भी कौन थे, हमारी बहन, बेटियां थी। उनमें आधे से ज्यादा लगभग आधे के करीब महिलाये भी थी। ट्रेंड महिलायें काम कर रही हैं। आप केवल एक सरकार को बदनाम करने के लिए, केवल उन महिलाओं को जो दिल्ली सरकार के वोटर हैं, जो आम आदमी पार्टी के और केजरीवाल जी के स्पोर्टर हैं, उनको सजा देने के लिए आपने डेढ़ साल बाद एक नया प्रोसेस शुरू किया होमगार्ड का। सर पीस के समय सिविल डिफेंस का अहम काम है और अभी मेरे दोस्त बता रहे थे जून साहब। जून साहब उसमें एक प्वाइंट है। उस प्वाइंट में लिखा है कि सिविल डिफेंस क्या कर सकता है। मैं exact लाईन पढ़ रहा हूं। to regulate the conduct of persons in areas to control. सर ये, ये ही तो है। सिविल डिफेंस का काम क्या है कि ऐसे लोगों को कन्ट्रोल करना है, ऐसे लोगों के कन्डक्ट को कंट्रोल करना जो सिक्योरिटी के लिए threat है। जो लोगों के लिए threat है। तो बस में महिला बस कन्डैक्टर, सॉरी ये सिविल डिफेंस की वॉलेन्टीयर क्या करती है कि महिला की बस में अगर कोई बैठी है और कोई महिला ऐसी हो जो वहां उत्पात करे तो उसको कन्ट्रोल करने के लिए वो पैनिक बटन काम नहीं आयेगा। वो सीसीटीवी कैमरा आप वह evidence के लिए तो ले सकते हैं पर तुरन्त मदद के लिए आपको चाहिए। कई बार पिक पॉकेट की बात आती है। कई बार महिलाओं में जो दोनों जिसमें जो जनरल बस है उसमें दोनों तरह के लोग जाते हैं। ऐसे लोगों में बहुत छिछोरे, बहुत बदतमीज और बहुत घटिया लोग होते हैं। उनके लिए सिक्योरिटी चाहिए। ये हम सबकी जिम्मेवारी है,

(माननीय अध्यक्ष द्वारा समय की घंटी बजाई गई)

श्री मदन लालः इस सरकार की जिम्मेवारी थी। इसलिए इन्होंने ऐसा किया। मैं इस सदन के माध्यम से अपने इन दोस्तों से ये निवेदन करता हूं कि महिलाओं के बारे में ऐसी अभ्रद भाषा का इस्तेमाल ना करें क्योंकि वो हमारी माँ बहन बेटियां है। हम उनका सम्मान करते हैं। आप लोगों को भी करना चाहिए और शायद आप इसीलिए यहां वापिस आ गए कि आप चाहते थे कि इसके बारे में कुछ ना कुछ ऐसा बोलें, अनर्गल बोलें जिससे यहां जो ये सदन इस पर चर्चा कर रहा है वो उससे भ्रमित हो जाये। हमारे कुछ दोस्त भ्रमित हो रहे थे। हम चाहते थे कि आप भाषा का इस्तेमाल करते रहे। आप लोगों को पता चले लोग जाने कि आपके मन में क्या है महिलाओं के प्रति। उम्मीद है आप आगे से ध्यान रखेंगे। सर मैं आपसे निवेदन करूंगा जो ये अनर्गल बातें इन्होंने कही वो कन्डक्ट यहां रिकार्ड से भी हटाई जाएं। सर वो हटनी चाहिए, वो अभद्रता थी। वो अभद्रता थी। लोगों ने जिन्होंने सुनना है सुन लिया। ऐसी अभद्र भाषा रिकार्ड पर भी नही रहनी चाहिए ये सारी हदें पार कर गई है।

माननीय अध्यक्षः चलिए।

श्री मदन लालः सर मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इनको इसके वाबजूद भी यहां बैठे रहने दिया। जबकि हम सब जानते हैं कि ये सबसे ज्यादा खिलाफ हैं, सिविल डिफेंस के वॉलेन्टीयर्स के खिलाफ है। अगर ये खिलाफ ना होते...

माननीय अध्यक्षः मदन लाल जी।

श्री मदन लालः अगर ये खिलाफ ना होते तो.

माननीय अध्यक्षः कन्क्लूड करिये प्लीज।

श्री मदन लालः तो हमारे उस प्रदर्शन में शामिल होते जो अभी कुलदीप कुमार जी और संजीव कुमार जी और उनके साथियों ने अभी पीछे किया था वॉलेन्टीयर्स के साथ। ये उसमें शामिल होते और ये एलजी महोदय को कहते कि सिविल डिफेंस के लोग सबसे ज्यादा अच्छा काम कर रहे थे उनको आप करते रहने दीजिए, होम गार्ड को कहीं और इस्तेमाल कर लीजिए। हमें और बहुत सारी जगह जरूरत है जहां दिल्ली पुलिस adequately available नहीं है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक्यू।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद मदनलाल जी। श्री जरनैल सिंह जी। जरनैल सिंह जी संक्षेप में रखिए प्लीज।

श्री जरनैल सिंहः धन्यवाद स्पीकर साहब। सर दिल्ली के बस मार्शल्स जो लगभग दस हजार के आसपास है उनकी नौकरियां जो भाजपा के ईशारों पर अफसरों द्वारा छिनवाई गई इस गम्भीर मामले पर आपने मेरे को बोलने का मौका दिया। स्पीकर साहब भाजपा के विधायक इस चर्चा की शुरूआत में ही उठकर चले गए थे। इस चर्चा को रोकने की कोशिश इन्होंने की तो इससे साफ जाहिर हो गया कि ये कितना खिलाफ है बस मार्शल्स की इस नौकरी के। हद तो तब हो गई जब

हमारे सदन के साथी मोहन सिंह बिष्ट जी ने बस मार्शल्स को रेपिस्ट और बलात्कारी तक बोल दिया अध्यक्ष जी, इससे बड़ी शर्म की बात हो नहीं सकती। अध्यक्ष जी ये बात जब उन मार्शल्स को पता लगेगी कि जो भाजपा कभी-कभी तो नौटंकी करती है कि हम आपके साथ है और सदन के अंदर ऑन रिकार्ड उनको बलात्कारी बोल रही है तो ये उनकी सेवाओं और उनकी निष्ठा के ऊपर एक बहुत बड़ा धक्का उनको लगेगा। मेरे को लगता है कि नेता प्रतिपक्ष को अपने दल की तरफ से उन सभी बस मार्शल्स से माफी मांगनी चाहिए नहीं तो ये बात अब यहां रूकेगी नहीं अध्यक्ष जी। एक-एक बस मार्शल खुद इनसे इस बात का जवाब मांगेगा। सितम्बर 2023 से लेकर अब तक जो लैटर रेवेन्यू मिनिस्टर ने लिखा, रेवेन्यू सैक्रट्री को लिखा। उसके बाद इस विधान सभा में प्रस्ताव पास हुआ। दुनिया भर का हमने हर वो सम्भव प्रयास करा कि किस तरीके से बस मार्शल्स की नौकरी उन्हें वापिस दिलवाई जा सके, पर भाजपा जो कि अफसरशाही पर कंट्रोल करके उनके अफसरों के पीछे छुपकर गंदी राजनीति कर रही है वो इस काम को होने नहीं दे रही। मैने सुना था कि बुलेटप्रूफ जैकेट पहनकर बंदा बुलटप्रूफ हो जाता है। उसके ऊपर ये कदम निकाला ये बेज्जतीप्रूफ हो गये, इनको बेज्जती का भी अहसास नहीं होता। उसके ऊपर बंदा, मैं तो ये कह रहा हूं बुलेटप्रूफ हो सकता है, बेज्जतीप्रूफ हो सकता है पर बंदा बद्दुआप्रूफ नहीं हो सकता। कितनी बद्दुआएं भाजपा वाले लेंगे। स्पीकर साहब बस मार्शल्स की बद्दुआएं ये ले रहे हैं। होम गार्ड्स की बद्दुआएं इन्होंने ली। सफाई कर्मचारियों की नौकरी छीन कर उनकी

बद्दुआएं इन्होंने ली। दिल्ली के बुजुर्गों की बद्दुआएं उनकी पेंशन रोककर ले रहे हैं। दिल्ली के अस्पतालों में डेटा इन्ट्री ऑपरेटर्स की नौकरी छीन कर उनकी बद्दुआएं ये लेते हैं। किस-किस की राशन कार्ड रोक देते हैं। यहां तक कि बुजुर्गो की पेंशनें तक रोकर उनकी बद्दुआएं ले रहे हैं। तो मैं इनको ये प्रार्थना करता हूं कि बद्दुआएं झेल नहीं पाओगे। देर सवेर हर रात की सुबह होती है। तो अभी से सद्बुद्धि लो, परमात्मा से प्रार्थना करो कि तुम्हें सद्बुद्धि आये। तुम दिल्ली के लोगों से जो दुश्मनी का बदला ले रहे हो ये लेना बंद करो। ठीक है हार जीत लगी रहती है। सबको मालूम है। सत्तर में से तीन सीटें तुम्हें भाजपा वालों को दी दिल्ली वालों ने। सत्तर में से आठ सीटें 2020 में दी तुमको दिल्ली वालों ने, तुम्हारी वो खुंदक ही नहीं खत्म हो रही। इस बार दिल्ली वाले भाजपा को सत्तर में से जीरो सीटें देंगे। ये बद्दुआओं का दर्द तुम्हें दिखेगा। तुम्हें ये सारा दर्द दिखेगा। तुम सबकी जमानतें जब्त होंगी। तुम्हें क्या लगता है तुमने बलात्कारी बोला था वो कुछ करेंगे नहीं। एक-एक सिविल डिफेंस वॉलेन्टीयर तुमसे इस चीज का बदला लेगा जो तुमने सभी सिविल डिफेंस वॉलेन्टीयर्स को बलात्कारी बोला है। हद होती है। शर्म आनी चाहिए थी बिष्ट साहब आपको। शर्म आनी चाहिए थी आपको बिष्ट साहब।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र अगर आप बोलेंगे तो सत्ता पक्ष के लोग टोकेंगे तो रोकना नही, ये ध्यान रखना।

श्री जरनैल सिंह: इतनी हिम्मत कैसे हो गई आपकी सदन में कि आपने सभी सिविल डिफैंस वॉलेन्टीयर्स को बलात्कारी बोल दिया।

माननीय अध्यक्ष: नहीं बैठ जाईये आप। बैठ जाईये।

श्री जरनैल सिंह: अध्यक्ष जी, ऑन रिकार्ड बोला तो ये हाल है। शर्म की हद होती है। इनको कोई हक नहीं है। इन्होंने भरे सदन के अंदर सिविल डिफेंस वॉलेन्टीयर्स को बलात्कारी बोला है। रिकार्ड गवाह है इस चीज का। अध्यक्ष जी मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं। मैं एक आपको कहानी छोटी सी बता रहा हूं। एक सच्ची कहानी है। मेरा एक जानने वाला है सिविल डिफैंस वॉलेन्टीयर है। सुमित नाम है। तिलक नगर की शहीद भगतसिंह कालोनी में रहता है। मैं काफी सालों से उसको जानता हूं। वो जवान हुआ। मेरे साथ बैठा था। मैने कहा जी क्या बनेगा बड़े होकर। कह रहा है कि भाई साहब मैं आर्मी में जाना चाहता हूं। नहीं जा पाया चलो किसी परिवारिक मजबूरी थी नहीं जा पाया। उसके कुछ समय बाद मेरे पास आता है वर्दी पहन कर आता है। फख्र से छाती चौड़ी करके आता है। कह रहा है भाई साहब आर्मी में तो नहीं जा पाया पर मेरी आपकी यहां पर दिल्ली सिविल डिफैंस के माध्यम से मेरी बस मार्शल की नौकरी लग गई। भाई साहब बड़ा खुश हुआ और इतनी निष्ठा से भाई साहब स्पीकर साहब वो अपनी डयूटी करता था और फिर वो ही नहीं यहां पर दुनिया भर के एग्जाम्पल है। अरूण कुमार का एग्जाम्पल है जिसने बच्ची का रेप होते बचाया। दुनिया भर के ऐसे बच्चे जो सेवा भावना से पूरी निष्ठा से बस मार्शल्स की

डयूटी कर रहे थे। सुरक्षा कर रहे थे यात्रियों की, उन सबके ऊपर इन्होंने सवाल उठा दिया। सबको बलात्कारी बोल दिया। शर्म आनी चाहिए थी बिष्ट को। तो अध्यक्ष जी एक तरफ तो ये अफसरों के पीछे छुपकर भाजपा गंदी राजनीति कर रही है। अलग–अलग तरीके से दिल्ली वालों के काम रोक रही है। दिल्ली वालों की नौकरियां छीन रही है। बुजुर्गो की पेंशन रोक रही है। इन सब कामों का हिसाब दिल्ली की जनता आने वाले चुनाव में सत्तर में से जीरो सीट देकर भाजपा का करेगी। और मैं उन सभी बस मार्शल्स से ये कहना चाहता हूं कि.

(समय की घंटी)

श्री जरनैल सिंहः आप ये संघर्ष का रास्ता छोडें न। हम भी दस सालों से लड़–लड़कर भाजपा से सारे काम करवा रहे है और आगे भी करवायेंगे।

ये राहें ले ही जायेंगी मंजिल तक हौंसला रख,

कभी सुना है अंधेरों ने सवेरा होने ना दिया।

बहुत–बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। थैंक्यू।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद। श्री विजेंद्र गुप्ता जी।

श्री विजेंद्र गुप्ताः आदरणीय अध्यक्ष जी आपका बहुत बहुत आभार। आज बहुत ही सदन में गर्मागर्म चर्चा हो रही है और बड़ी

हैरानी की बात है कि जिन लोगों ने खता की वही जो है यहां पर अब पक्ष लेने की बात कर रहे हैं। दिल्ली के दस हजार सिविल डिफेंस वालंटियर्स, बस मार्शल्स के साथ जिस तरह से केजरीवाल जी ने और उनकी सरकार ने धोखा किया वो पूरी दिल्ली और पूरा देश देख रहा है। आपने इन नौजवानों के सपनों को तोड़ा है, इन नौजवानों के अरमानों को कुचला है और ये बस मार्शल बहुत गरीब परिवारों से आते हैं। एक आस जगी थी लेकिन इन युवाओं को क्या पता था कि आम आदमी पार्टी मतलब धोखाधड़ी पार्टी। हर किसी के अरमानों को कुचलना, आस दिखाना और फिर उस पर राजनीतिक रोटियां सेंकना, ये आम आदमी पार्टी की आदत बन चुकी है। दिल्ली के टीचर्स के साथ ये किया, कितने लोगों को कहा कि हम आपको पक्का करेंगे और बाद में आरोप प्रत्यारोप, बयानबाजी, झूठ-सच, नतीजा क्या निकला? वो सब लोग बेरोजगार हो गये। आज भी सदन में जो चर्चा हो रही है उसके बारे में भी मैं बड़े स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि मैं प्रस्ताव पेश कर रहा हूं आप उसको समर्थन करिये कि जो बस मार्शल्स हैं अध्यक्ष जी आपकी अनुमति से प्रस्ताव पेश कर रहा हूं, जो बस मार्शल हैं जिनको लगाया गया था बसिज के अंदर, मेरा प्रस्ताव ये है कि उन सबको तुरंत बहाल किया जाये और उनकी नौकरियां पक्की की जाये। ये प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सदन के समक्ष है। दूसरा, अभी जरनैल सिंह जी काफी कुछ कह रहे थे युवा हैं अभी, अभी देख रहा हूं दस साल में थोड़े से बड़े हो गये हैं। जोश में रहते हैं, होश कई बार खो देते हैं। लेकिन हम यही मानकर के कि युवा हैं, नौजवान

हैं तो भई निश्चित रूप से गुस्सा आयेगा, तो कोई बात नहीं हमारे छोटे भाई हैं। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि पहली बात तो अध्यक्ष जी, हमें मार्शलों से आपने बाहर निकाला था, हम अपनी मर्जी से नहीं गये थे। आपके आदेशानुसार, आपने मार्शलों से कहा 15 मिनट के लिये हम, चूंकि हम भी बहुत महत्वपूर्ण बात 12 सीएजी की रिपोर्ट क्या सदन के पटल पर नहीं आनी चाहिए पांच साल हो गए, तो विपक्ष ने भी जो मुद्दा उठाया है और वो जारी रहेगा ऐसा नहीं है कि वो मुद्दा मार्शलों से बाहर चले गए तो निकाल दिया गया तो नहीं है, वो है। वो मद्दा बना रहेगा लेकिन चूंकि ये अति महत्वपूर्ण चर्चा यहां हो रही है, हमने अपना कर्तव्य समझा कि हमें इस चर्चा में भाग लेना है और इसलिए हमारा जो तिरस्कार भी किया गया सही बात पर, संवैधानिक व्यवस्था को लेकर के, हमें मार्शलों से निकाला गया, धक्का मुक्की की गई उसके बाद भी।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः अब उनको बोलने दो।

श्री विजेंद्र गुप्ताः हम अपने व्यक्तिगत।

माननीय अध्यक्षः उनको बोलने दो, भई कुलदीप जी आपकी ये आदत ये बड़ी खराब है। प्लीज।

श्री विजेंद्र गुप्ताः हमारे 280 जिनमें जनहित के तमाम मुद्दे थे राशन का मुद्दा था, सीवर बंद पड़े हैं, खराब हैं बच्चे मर गए डूब

के, 50 लोगों की मौत हो गई, नालों की सफाई नहीं हुई, सड़कें टूटी हुई तमाम मुद्दे थे। हमारे 280 स्वीकार भी किए गए लेकिन बहुत दुर्भाग्य है कि हमें उनको यहां पर प्रस्तुत नहीं करने दिया गया और इसलिए हमने स्पीकर साहब के कमरे के बाहर हमने मौक असेंबली लगाई और वहां अपने मुद्दे रख दिए और उसके बाद इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने के लिए हम अध्यक्ष जी के आदेश का पालन करते हुए सदन में मौजूद हैं। हमें अच्छा लग रहा है, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, मार्शलों को पता लगना चाहिए कि सच क्या है, स्थिति क्या है और किसने उनको हटाया है ये मार्शलों को पता लगना चाहिए और मैं चुनौती देता हूं पूरे सत्तारूढ दल को, आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल जी और आतिशी जी की मिली जुली सरकार को, ये जो पक्ष मैं यहां रखूंगा उसका आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। आपने हमारे वरिष्ठ, पांच बार के विधायक जिन्होंनें चिंता व्यक्त की किसी एक दुर्घटना की, क्या इस सदन में अगर कोई दुर्घटना हुई कहीं, क्या उस महिला के साथ जो अपराध हुआ, क्या उस महिला की आवाज उठाना अपराध है क्या? अगर उसका दर्द उन्होंने बयान करने की कोशिश की तो आप उस पर राजनीति कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए सत्तारूढ़ दल को कि अगर कोई मुद्दा।

...व्यवधान...

श्री विजेंद्र गुप्ताः सदन के समक्ष एक घटना के तौर पर उठाया जाता है तो आप हर चीज पर राजनीति करते हैं।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे।

...व्यवधान...

श्री विजेंद्र गुप्ताः अब मैं आपके समक्ष।

माननीय अध्यक्षः माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे बाद में।

श्री विजेंद्र गुप्ताः मुझे अध्यक्ष जी ने जो समय दिया, मैं जानता हूं कि सदन का समय बहुत सीमित है और बहुत इंपोरटेंट है, सभी सदस्यों को अपनी बात रखनी है लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिये, अपने साथियों का पक्ष रखने के लिये, अध्यक्ष जी की अनुमति से आप के समक्ष मार्शलों के मामले में जो मैंने प्रस्ताव पेश किया है, मेरा अनुरोध है उसको आप स्वीकार करें और उस पर सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित होना चाहिये। अब मैं आपको आगे की स्थिति बताना चाहता हूं। मेरे हाथ में ये केजरीवाल जी का पत्र है जो उन्होंने उपराज्यपाल को लिखा है और ये पत्र है 11 अक्तूबर 2023 का, इसमें केजरीवाल जी ने मार्शल्स के बारे में क्या लिखा है मैं पूरा पढ़ूंगा तो बहुत लंबा है, बहुत सारे पेजिज भी हैं लेकिन कोई बात नहीं वो आप हो न, आप पढ़ना न, मैं gist दो लाईन का दो लाईन का gist मंत्री जी। देखिये, if the correct… केजरीवाल जी लिखते हैं the correct legal position may be ascertained. Till it is decided, services of all civil defence volunteers may be terminated at the end of October.

...व्यवधान...

श्री विजेंद्र गुप्ताः The correct legal position may be ascertained. Till it is decided, the correct legal position may be ascertained. Till it is decided, services of all Civil Defence Volunteers may be terminated at the end of October और आगे लिखते हैं regarding

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः एक सैकिण्ड शिव चरण जी मैं कर रहा हूं।

श्री विजेंद्र गुप्ताः regarding making payment...पूरा एक मिनट, बैठिए, आप बैठिए।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः भई दो मिनट, महेंद्र जी अभी मैं कर रहा हूं।

श्री विजेंद्र गुप्ताः मुझे मालूम था आपको मिर्च लगेगी क्योंकि जब सच सामने आता है और आम आदमी पार्टी का झूठ पकड़ा जाता है तो ऐसा ही होता है। आगे सुनिये। regarding making payments for the services rendered till now, the same should be made immediately. अक्तूबर, 23 को उनकी सर्विसिज को समाप्त करने का आदेश दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने स्वयं और इसमें लिखा है Till it is decided. Till it is decided, the correct legal position may be ascertained. Till it is decided जब तक ये तय नहीं हो जाता till it is

decided मैं बार बार इसको पढ़ रहा हूं till it is decided और उसके बाद इन तमाम लोगों को हटा दिया जाता है। एक तरफ आप लगाने की बात कर रहे हैं, एक तरफ आप उनको हटा रहे हैं और ये जो डबल स्टैंडर्ड है आम आदमी पार्टी का वो साफ रूप से लोगों के बीच में आ गया है और अब इसलिये आपको चुनौती देता हूं।

माननीय अध्यक्षः महेंद्र जी प्लीज।

(समय की घंटी)

श्री विजेंद्र गुप्ताः जो प्रस्ताव मैंने रखा है (समय की घंटी) उसको आप सब लोग, विपक्ष के इस प्रस्ताव को स्वीकार करें।

माननीय अध्यक्षः लाइए विजेंद्र जी।

...व्यवधान...

श्री विजेंद्र गुप्ताः धन्यवाद और दूसरा अभी जरनैल सिंह जी रिजल्ट की बात कर रहे थे अभी ताजा ताजा आप जीरो हुए दिल्ली में और कांग्रेस के साथ मिल कर जीरो हुए हो। तो आप जिस कांग्रेस को, कांग्रेस के साथ मिल कर जीरो हुए हो।

माननीय अध्यक्षः विजेंद्र जी अब इसको छोड़िए।

श्री विजेंद्र गुप्ताः विधान सभा में भी आप जीरो होने वाले हो, विधान सभा में भी जीरो होने वाले हो धन्यवाद।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः ये एक सैकिंण्ड विजेंद्र जी ने जो लैटर पढ़ा है ये सदन के रिकार्ड पे पूरा रख दें और रिकार्ड में ले लिया।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः हां दीजिए, दीजिए।

...व्यवधान...

श्री विजेंद्र गुप्ताः मेरे पास जो है वो मैं दूंगा।

माननीय अध्यक्षः हां दे दीजिए।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः मैं रिकार्ड में ले रहा हूं भई। ये एक ही पेज दे रहे हैं आप।

...व्यवधान...

माननीय मंत्री (श्री सौरभ भारद्वाज): एक एक करके बताइए,

...व्यवधान...

श्री विजेंद्र गुप्ताः मैनें जिस्ट पढ़ दिया अध्यक्ष जी जो

माननीय अध्यक्षः नहीं ये एक ही पेज दे रहे हैं आप।

...व्यवधान...

श्री विजेंद्र गुप्ताः और इस पे जो जिस्ट है मैंने पढ़ दिया अब आपको जो करना है करो आप पढ़ो।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः महेंद्र जी बैठिए, परेशान हो गये ना एक सैकिण्ड में, आप चिल्लाते रहिए परेशान हो गए एक सैकिण्ड में।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः चलिए।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः भई दो मिनट।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः देखिए विजेंद्र जी मैं बड़ी शालीनता से कह रहा हूं, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मोहन सिंह बिष्ट जी ने, एक सैकिण्ड रूक..

श्री विजेंद्र गुप्ताः आप समर्थन कर दीजिए ना।

माननीय अध्यक्षः अरे भई दो मिनट तो रूकिए आप। दो मिनट तो रूकिए आप। मैं दूसरी बात कह रहा हूं। आदरणीय मोहन सिंह बिष्ट

जी ने जो बात कहा मार्शल्स रेपिस्ट हैं वो आप सुन लीजिएगा, मार्शल्स रेपिस्ट हैं।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः अब सुनवा दूंगा मैं, बैठ जाईए, बैठ जाईए आप। मार्शल्स रेपिस्ट हैं आपने ये बोला।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः नहीं बिल्कुल, नहीं मेरे चैम्बर में आ जाईएगा मैं सुनवा दूंगा। मेरे चैम्बर में आ जाईए।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः अगर आपने ये बोला, अगर ये बोला पहले, मार्शल रेपिस्ट हैं, बैठिए।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः आप सदन से माफी मांगेंगे बाद में। सदन से माफी मांगेंगे, अगर.

श्री मोहन सिंह बिष्टः किस बात की माफी मांगे?

माननीय अध्यक्षः मार्शल रेपिस्ट हैं ये बोला।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः बैठिए, आप बैठिए, बैठिए श्रीमान, भई अब नहीं प्लीज। माननीय सौरभ भारद्वाज जी, माननीय मंत्री चर्चा का उत्तर देंगे।

माननीय मंत्री (श्री सौरभ भारद्वाज): अध्यक्ष जी काफी बहस हुई है इस मुद्दे पे और पहले भी इसपे चर्चा हो चुकी है। मुझे डर ये है कि इस चर्चा में, इस बहस में एक दूसरे से उपर उठने की होड़ में ये जो दस हजार बस मार्शल हैं दिल्ली के, ये लोग लगभग बर्बादी के कगार पे हैं, इनके घर के चूल्हे नहीं जल रहे हैं, जो किराये पे लोग रहते हैं वो किराया नहीं दे पा रहे हैं, कुछ लोग आत्महत्या कर चुके हैं और बहुत खराब हालात के अंदर ये लोग अपना जीवन बिता रहे हैं। जो लोग इन बस मार्शलों के परिवारों को जानते हैं, वो जानते हैं कि ज्यादातर ये बस मार्शल्स बेहद गरीब परिवारों से हैं और अपने घर के इकलौते, ये कह सकते हैं घर चलाने वाले थे और एक अच्छी सर्विस मिल रही थी दिल्ली के अंदर, महिलायें, हमारी बहनें, हमारी बेटियां जो बसों में सफर करती हैं अगर लोगों ने बसों में सफर किया हो, मैं स्कूल डेज़ में और कालेजों के दिनों में बसों में घूमा हूं दिल्ली की, तो उसके अंदर ये अक्सर है कि बस के अंदर अगर भीड़भाड़ थोड़ी भी बढ़ती हैं तो महिलाओं के साथ बदतमीजी होती है और वो महिलायें, कालेज की लड़कियां, इस तरह से मजबूर होती हैं कि बकायदा बदतमीजी, छेड़छाड़ के बावजूद भी वो कुछ नहीं कर पाती हैं, वो सोचती हैं कि बस किसी तरीके से हमारा बस स्टैंड आये और हम उतरें और हमारा पीछा छूटे। ये बदतमीजियां होती हैं और ऐसा नहीं कि

जवान लड़के बदतमीजी करते हैं, मैंने देखा है अधेड़ उम्र के बूड्ढे लोग भी जो हैं इस तरीके की हरकतें करते हैं। इस चीज को ध्यान में रख के ये बस मार्शल लगाये गये थे कि कम से कम उस महिला के दिल में ये हो कि भई अगर मेरे साथ कोई बदतमीजी कर रहा है, मैं शोर मचाउं तो कोई तो आदमी हो जिसकी ड्यूटी हो, जिसकी जिम्मेदारी हो कि वो इस चीज के अंदर आके बोले कि हां भाई ये कैसे कर रहे हो तुम। अब ये बस मार्शल जैसे तैसे लगाये गये और ये बस मार्शल काम भी कर रहे थे, इनको तनख्वाह भी मिल रही थी। जनवरी 2023 में इनकी तनख्वाहें रोक दी गयी। तो अध्यक्ष जी, ये एक सैट पैटर्न है जब से दिल्ली के अंदर विनय सक्सेना जी को एलजी बनाया गया एक सैट पैटर्न है जिस डिपार्टमेंट को बर्बाद करना हो या जिन लोगों को बर्बाद करना हो उसमें कोई खामी निकाली जाती है। अब ये अफसर ही बनाते हैं फाईलें, हम तो बनाते नहीं हैं। अब वो कोई भी स्कीम हो दुनिया की, कुछ भी हो उसमें अगर खामी निकालने बैठोगे तो उसके अंदर एक खामी तो कोई भी निकाल देगा, हर चीज के अंदर खामी निकाली जा सकती है। अब हर स्कीम के अंदर खामियां ढूंढने का काम अफसरों को दिया गया कि भई इसको किसी तरह से खामी ढूंढो इसके अंदर और इसको रोको। और उसने इसके अंदर खामी देखी कि साहब ये स्कीम ठीक नहीं है और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के एलजी साहब के एक बड़े चहेते अफसर थे आशीष कुंद्रा, उनके डिपार्टमेंट ने ये फाईल नोटिंग बनाई ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के। अच्छा क्यों चहेते हैं वो मैं बता दूंगा क्यों थे। उन्होंने एक फाईल नोटिंग बनाई कि साहब इनकी जरूरत ही क्या

है जब बसों के अंदर सीसीटीवी लग गये, पैनिक बटन लग गये तो इनकी जरूरत क्या है। तो अफसर को बस इतना ही लिखना होता है स्पीकर महोदय और कुछ नहीं करना होता, उसको जाके कोई तनख्वाह कोई न रोकनी होती है, उसको तो उस फाईल को खराब करना, इसको हमारी भाषा में कहते हैं फाईल खराब करना, तो अफसर क्या है किसी नीचे वाले, अच्छा इनकी ये जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, इनकी रीढ़ की हड्डी में इतना भी दम नहीं है कि अपनी कलम से लिख सकें, बहुत डरपोक हैं, क्योंकि आगे डरते हैं कि कल को सरकार बदलेगी, कल को केंद्र में सरकार बदलेगी तो हो सकता है उलटा लटकाया जाये ऐसे अफसरों को जिन्होंने गरीबों को इस तरीके से दुखी किया। तो ये अपने एक नीचे के एसओ से, किसी क्लर्क से ये फाईल नोटिंग बनवाते हैं। उसको बताते है कि तू ऐसा-ऐसा लिख दे इसके ऊपर। क्लर्क के लेवल के, एस.ओ. के लेवल से एक घटिया फाइल नोटिंग लिखवाई जाती है फाइल पर और फिर नीचे से लेकर ऊपर तक डिप्टी सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सब उसके ऊपर अप्रूव, अप्रूव, अप्रूव, अप्रूव करते चले जाते हैं मतलब जो घटिया विचार उस एस.ओ. ने इस फाइल पर डाला मैं उस घटिया विचार से सहमत हूं। तो ऐसे ही घटिया विचार से सहमत होते-होते ये फाइल मंत्री तक पहुंची, मंत्री असहमत थे, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के मंत्री-कैलाश गहलोत जी और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की मंत्री उस वक्त की आतिशी, दोनों आतिशी जी, कैलाश जी दोनों असहमत थे, मंत्री के तौर पर दोनों ने फाइलों पर लिखा कि ये क्या बकवास है कि अगर आपको सीसीटीवी लग गए हैं बस में या पैनिक

बटन लग गया तो आप बस मार्शल हटा दोगे। खैर मंत्रियों के एतराज से कोई फर्क नहीं पड़ा, अफसर ने लिख दिया, आई.ए.एस. अफसर जो थे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर उनकी बात हो गई, तो लिहाजा इनकी तनख्वाह रोक दी गई। रेवेन्यू के जो असफर थे डिविजनल कमिश्नर वो अश्विनी कुमार थे वो भी एल.जी. साहब के खास चहेते आदमी है, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जो थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी वो आशीष कुंद्रा थे, खास इसलिए थे क्योंकि ये करने के बाद उनको एल.जी. साहब ने अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना लिया, आज वो उनके, एल.जी. साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, इससे आपको पता चलता है कि उनके चहेते भी थे और उनके खास भी थे और उनके इशारे पर इतने बड़े-बड़े काम कर रहे है तो और क्या मिलेगा। इन बेचारों की तनख्वाहें रोक दी गई। तो ये सोचा कि तनख्वाह ही नहीं मिलेगी तो अपने आप ही भाग जाएंगे। जनवरी बीता, फरवरी बीता, मार्च बीता, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, सितम्बर, सितम्बर के अंदर फिर से ये मामला गरमाया, फिर से फाइलों पर लिखा गया कि भई इनकी तनख्वाह रिलीज करो। तो अफसरों का ये ही कि जी ये फाइल ये जो है ये स्कीम ठीक नहीं है, तो उस विषय के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने ये लिखा है, ये पूरा जानबूझकर नहीं लेकर आये हैं, मैं क्योंकि विभाग का मंत्री नहीं हूं इसलिए मेरे पास जानकारी नहीं थी ये, अरविंद केजरीवाल जी ने, मैं इनको चुनौती दे रहा हूं इस चीज की, ये है 218/एन, 217/एन और 218/एन दोनों पेजों में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इनको बहाल किया जाए और अगर आप ये कहते हों कि ये गैर कानूनी हैं तो क्या था अध्यक्ष महोदय 8-10

हजार तो ये हमारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर बस मार्शल लगे हुए थे और करीब 179 सिविल डिफेंस वॉलंटियर लगे हुए थे जो डी.एम. और एस.डी.एम. की चाकरी करते हैं, उनके घर में उनके कुत्ते घूमाते हैं, उनकी फाइलें इधर से इधर करते हैं, छोटे-मोटे काम करते हैं, तो अरविंद केजरीवाल जी ने ये लिखा था उसके अंदर कि अगर ये 8 हजार बस मार्शल गैर कानूनी हैं तो ये 179 सिविल डिफेंस वॉलंटियर भी जो लगाए हुए हैं तुमने एस.डी.एम. और डी.एम. के यहां वो भी गैर कानूनी हैं, उन्होंने ये लिखा है इसमें और उन्होंने आगे क्या लिखा है-I am shocked to learn that payments have not been made to them for seven months since 1st April. Most of them come from very poor background. Their jobs are very tentative in nature. They can be called anytime for work and they can be asked to stop coming next day suddenly. Imagine the plight of a person who is doing such a tentative job. He must be in dire need of money. That's why he is coming for such a temporary job and if we do not pay them in time, we have committed a crime against them. Some officers in the system are so insensitive and so selfish that it is only their own salaries, perks and promotions that matter to them. They are least bothered about the plight of such poor people. They keep playing football with the files. In fact, they derive sadistic pleasure in obstructing work and stopping files.

I recommend exemplary punishment against the officers, including the most senior officers in the present case, which are directly and indirectly responsible for this delay. We should give such punishment to these officers that henceforth, any other officer does not indulge in such dilatory tactics. The officers responsible for the delay in this case should be immediately suspended and disciplinary proceedings should be initiated against them.

If Hon'ble LG shares my sentiments, this matter may be placed before the next Authority meeting. तो अरविंद केजरीवाल इसमें कहते हैं कि जिन नालायक अफसरों ने including the top most जिन्होंने इनकी तनख्वाह रोकी उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए, उनके ऊपर डिसप्लनेरी प्रोसीडिंग की जाए, की एल.जी. साहब ने? उन्होंने कहा कि इन गरीबों की तनख्वाहों को रोकने वाले को मजा आता है कि गरीब आदमी को सताया जा रहा है जबकि जो अपना पैसा, अपनी प्रमोशन, अपने perk अपना घर, उसके लिए उनको जो है हर चीज चाहिए, ये अरविंद केजरीवाल ने लिखा और ये जो पहला पेज है उसमें लिखा कि इनको दुबारा नौकरी पर दिया जाए। खैर ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री को कोई बात नहीं, ये हम पर आरोप लगाएंगे अध्यक्ष जी, हम इन पर आरोप लगाएंगे, उससे मामला हल नहीं होगा।

...व्यवधान...

माननीय स्वास्थ्य मंत्रीः ठीक है, आ गया। अब मसला ये है कि अगर आज आप लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, अगर आप लोग आज तैयार हैं, हम आज तैयार हैं कि इन सबको वापिस रख लिया जाए, ठीक है जी, ऊपर बैठे हुए हैं वो लोग, ऐसा नहीं है नहीं बैठे हुए हैं, ऊपर जो है वो लड़के बैठे हुए हैं। वो देखने आए हैं कि आज इस सदन में क्या हुआ। तो अध्यक्ष जी, एक रेजोल्यूशन बना लिया जाए कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, रेजोल्यूशन इससे पहले भी था,

...व्यवधान...

माननीय स्वास्थ्य मंत्रीः मैं ला रहा हूं।

माननीय अध्यक्षः दो मिनट, उनको बोलने तो दो।

माननीय स्वास्थ्य मंत्रीः मैं बता रहा हूं।

...व्यवधान...

श्री ओम प्रकाश शर्माः ये हमने दे तो दिया।

श्री विजेन्द्र गुप्ता (माननीय नेता, प्रतिपक्ष): ये दे तो दिया।

माननीय स्वास्थ्य मंत्रीः हां, मैं मान गया आपकी। तो अध्यक्ष जी, 29 फरवरी, 2024 को एक रेजोल्यूशन इस हाउस से पास हुआ है, उस रेजोल्यूशन को हम दुबारा रख देते है इस पटल पर। आज इनकी वोट भी आ जाएगी इसमें, हैं ना, इनकी वोट भी आ जाएगी,

...व्यवधान...

माननीय स्वास्थ्य मंत्रीः ठीक है।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी, दो मिनट बैठिए अभी।

माननीय स्वास्थ्य मंत्रीः तो अध्यक्ष जी, इनके रेजोल्यूशन में हम अपना जोड़ देंगे, इनको बड़ा रखेंगे और हमें बड़ा बनने का शौक नहीं, ये बड़े हैं, ये बड़े भाई हैं, मगर अध्यक्ष जी 24 फरवरी, माफ कीजियेगा, 29 फरवरी, 2024 को ये संकल्प जो है सदन में पास हुआ था, ऐसे ही आज भी सदन में ये संकल्प पास हो जाएगा। मगर समस्या ये है..

...व्यवधान...

श्री ओम प्रकाश शर्माः सरकार कुछ नहीं करती.

माननीय स्वास्थ्य मंत्रीः हां-हां, समस्या ये है..

माननीय अध्यक्षः ओम प्रकाश जी, अब क्यूं, प्लीज, एक गंभीर विषय पर बात हो रही है। इतना, अब ये दस हजार कर्मचारियों का विषय है। हम मजाक बना रहे है यहां। उनके घरों में रोटियां नहीं चल रही हैं, हम मजाक बना रहे है।

...व्यवधान...

श्री अजय कुमार महावरः सर, हम समर्थन में हैं।

माननीय अध्यक्षः चलिए।

श्री ओम प्रकाश शर्माः नहीं, हम तो समर्थन..

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः अरे भई बीच-बीच में टोका-टोकी कर रहे हैं।

...व्यवधान...

माननीय स्वास्थ्य मंत्रीः अध्यक्ष जी, मैं बहुत खुश हूं इस बात से कि ये समर्थन में हैं और ये बहुत अच्छी बात हुई है कि ये समर्थन में हैं। अब अध्यक्ष जी क्योंकि ये मामला, इसके अंदर दो या तीन स्टेक होल्डर हैं, वैसे तो दो ही हैं हम तीन कह सकते हैं। एक दिल्ली की चुनी हुई सरकार जोकि हम हैं, हमारे मंत्री हैं, एक एल.जी. साहब जिनके पास सर्विसेज हैं और तीसरे इस विधान सभा के सारे विधायक जो तीसरे स्टेक होल्डर हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, ये तीन स्टेक होल्डर हैं जिनका इस मामले से सीधा लेना देना है। मैं इस रेजोल्यूशन में चाहता हूं अगले हफ्ते की, क्योंकि इस हफ्ते तो एल.जी. साहब बाहर विदेश में गए हुए हैं, उन्होंने बताया नहीं है मीडिया को मगर हैं विदेश में, अगले हफ्ते की कोई एक तारीख विजेन्द्र गुप्ता जी बता दें, एल.जी. साहब के पास हमारे सारे मंत्री इन्क्लूडिंग चीफ मिनिस्टर चलेंगे, सारे के सारे विधायक चलेंगे और

एल.जी. साहब से बैठकर कहेंगे भई जिस कागज पर तुम्हें हमारे मंत्री से साइन कराने हैं, अध्यक्ष जी, सुनिए न, अध्यक्ष जी,..

...व्यवधान...

माननीय स्वास्थ्य मंत्री: ठीक है, ठीक है।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: विजेन्द्र जी, अब ये उचित नहीं है।

...व्यवधान...

माननीय स्वास्थ्य मंत्री: ठीक हैं न। अरे तो नए मुख्यमंत्री जो कहोगे लिख देंगे।

...व्यवधान...

माननीय स्वास्थ्य मंत्री: अध्यक्ष जी,, देखिए क्या कह सकते हैं, ये यही कह सकते हैं न कि भई फलां कागज गलत लिख दिया, फलां कागज के अंदर पता नहीं था इनके, फलां कागज के अंदर गलती हो गई, चलो ठीक है जी। अब जिस कागज पर तुम्हें जो लिखवाना है, जिस कागज पर आपको जो लिखवाना है वो लिख देंगे, एल.जी. साहब के सामने लिख देंगे और वहीं तय हो जाएगा कि कौन इनके साथ हैं, कौन इनके खिलाफ हैं। अब ये बताए कि किस दिन चलना है?

...व्यवधान....

माननीय स्वास्थ्य मंत्री: अब आप ये बताओ कि चलना किस दिन है?

...व्यवधान...

माननीय स्वास्थ्य मंत्री: न, न, न।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: विजेन्द्र जी, अब आप कहां जा रहे हैं?

...व्यवधान...

माननीय स्वास्थ्य मंत्री: अध्यक्ष जी, अब उस रेजोल्यूशन में सिर्फ डेट डालनी है अगले हफ्ते की कि किस दिन चलना है और मैं कसम खा रहा हूं कि जब तक एल.जी. साहब उनको पास नहीं करेंगे हम वहां से आयेंगे ही नहीं, एल.जी. के घर बैठ जाएंगे। चलो।

...व्यवधान...

माननीय स्वास्थ्य मंत्री: आप तारीख बताओ। आप तारीख बताओ किस दिन चलोगे।

...व्यवधान...

माननीय स्वास्थ्य मंत्री: देख लो भई, देख लो सब।

...व्यवधान...

(समय की घंटी)

...व्यवधान...

माननीय स्वास्थ्य मंत्री: भैया सारा कागज विदड्रॉ कर लेंगे वहां पर और बताओ।

...व्यवधान...

माननीय स्वास्थ्य मंत्री: अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, मैं, अब ये तो बताएंगे नहीं, मैं कह रहा हूं, पहला नवरात्रा 3 अक्टूबर का है, पहले नवरात्रे पर चलते हैं। बताओ।

...व्यवधान...

माननीय स्वास्थ्य मंत्री: अरे सब वापिस ले लेंगे न। चलो।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: भई विजेन्द्र जी, अभी आपने कहा प्रस्ताव रखिये।

...व्यवधान...

माननीय स्वास्थ्य मंत्री: वहां जो कहोगे वो साइन करेंगे।

...व्यवधान...

माननीय स्वास्थ्य मंत्री: तो अध्यक्ष जी, रेजोल्यूशन में..

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः आप रेजोल्यूशन रखिए पहले।

माननीय स्वास्थ्य मंत्रीः 3 अक्टूबर 11.00 बजे हम उसके अंदर ऐड कर रहे हैं।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः आप रेजोल्यूशन रखिए।

...व्यवधान...

श्री विजेन्द्र गुप्ताः ..दोनों प्रस्ताव रख दो।

...व्यवधान...

श्री दिलीप पाण्डेयः अरे भाई साहब उससे पहले मेरा वाला भी है।

...व्यवधान...

श्री विजेन्द्र गुप्ताः आप भी रख दो।

श्री दिलीप पाण्डेयः अध्यक्ष महोदय, 24 फरवरी को दिया हुआ है...

...व्यवधान...

माननीय स्वास्थ्य मंत्रीः चलिए। तो यहां के जो वो है स्टाफ वो इस रेजोल्यूशन को लिख लें। विजेन्द्र गुप्ता जी का प्रस्ताव ये था कि जितने भी बस मार्शलों को डीटीसी बसों से हटाया गया है उनको वापिस लिया जाए, उसके अंदर अगली लाईन आएगी और आम आदमी पार्टी विधायक दल ने इसमें जोड़ा है कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के..

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः भई अब बैठ जाइये।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः नहीं,

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः उन्होंने बोला है अपने मुख से।

...व्यवधान...

श्री विजेन्द्र गुप्ताः इनको परमानेंट..

...व्यवधान...

माननीय स्वास्थ्य मंत्रीः परमानेंट किया जाए, ठीक है, परमानेंट किया जाए।

...व्यवधान...

माननीय स्वास्थ्य मंत्रीः ठीक है, परमानेंट किया जाए, लो, परमानेंट किया जाए और 3 अक्टूबर को सुबह 11.00 बजे दिल्ली सरकार के सभी मंत्री, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक एल.जी. साहब के यहां जाएंगे और एल.जी. साहब जो, जिस कागज पर हस्ताक्षर करने के लिए दिल्ली की चुनी हुई सरकार को कहेंगे इन मार्शलों की नियुक्ति से संबंधित, दिल्ली की सरकार वचनबद्ध है कि उन कागजों को साइन करके ही वहां से आएगी। करो।

...व्यवधान...

(सत्ता पक्ष द्वारा सदन में नारेबाजी)

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः ये प्रस्ताव कौन बनायेगा?

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः प्रस्ताव, प्रस्ताव कौन बनायेगा?

...व्यवधान...

माननीय स्वास्थ्य मंत्रीः प्रस्ताव वो लिख रहे हैं। टाइप करके ले आओ।

...व्यवधान...

श्री मोहन सिंह बिष्टः सर, ये प्रस्ताव ऐसे नहीं बनता..

...व्यवधान...

माननीय स्वास्थ्य मंत्रीः बन जायेगा वो तो।

...व्यवधान...

श्री विजेंद्र गुप्ताः प्रस्ताव वही होगा कि..

...व्यवधान...

श्री मोहन सिंह बिष्टः ये सदन संकल्प करता है..

...व्यवधान...

माननीय स्वास्थ्य मंत्रीः अब 3 तारीख की तैयारी करो।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः बैठिए, बैठिए। सदन के सामने ये प्रस्ताव है जो नेता–विपक्ष ने दस हजार मार्शल्स को पक्का करने का प्रस्ताव रखा है और उसमें जो माननीय मंत्री जी ने संशोधन रखा है,

उसके पक्ष में हैं वो हां कहें,

(सदस्यों के हां कहने पर)

जो उसके विरोध में हैं न कहें,

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः भई अब नहीं, आपका प्रस्ताव मैंने जो सुना,

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः मैंने बोल दिया है। मैंने बोल दिया है।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः मैंने बोल दिया है पूरा, सम्मान के साथ बोल दिया है और ये प्रस्ताव इस सदन ने..

...व्यवधान...

माननीय स्वास्थ्य मंत्रीः सर, एल.जी. साहब को भेज दिया जाए प्रस्ताव।

माननीय अध्यक्षः एक सेकंड। यह प्रस्ताव इस सदन ने पहले भी पारित किया था, दिलीप पाण्डेय जी लाए थे ये भी उसमें जोड़ा जाए और ये प्रस्ताव एल.जी. साहब को भेज दिया जाए। ठीक है।

...व्यवधान...

(सत्ता पक्ष द्वारा सदन में नारेबाजी)

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: विजेन्द्र गुप्ता जी प्रस्ताव से मुकर रहे हैं। एक सेकंड विजेन्द्र जी। विजेन्द्र जी बैठ जाइये।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: नहीं, विजेन्द्र गुप्ता जी..

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: देखिये। बैठ जाइये, दो मिनट। दो मिनट बैठिए। एक सेकंड,

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: सौरभ जी। सौरभ जी ने प्रस्ताव में संशोधन किया, स्वीकार किया बड़े मन से,

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: एक सेकंड,..

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: मैं खड़ा हूं.

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः ओम प्रकाश जी, आपकी हर बात का उत्तर मैं देना पसंद नहीं करता। प्लीज। उस प्रस्ताव में जो संशोधन रखा है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों साथ जाएंगे.

श्री विजेन्द्र गुप्ताः हम नहीं जायेंगे पक्ष के साथ..

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः अब ये विजेन्द्र गुप्ता जी इस बात से मुकर रहे हैं।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः सदन लंच के लिए ढाई बजे तक स्थगित किया जाता है।

(सदन की कार्यवाही अपराह्न 2.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

सदन 2.38 बजे पुनः समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

माननीय अध्यक्षः बड़े हर्ष का विषय है केरला विधानसभा हाउस कमेटी के माननीय 5 विधायक हमारे मध्य में आए मैं दिल्ली विधानसभा की ओर से उनका स्वागत करता हूं। अल्पकालिक चर्चा श्री विनय मिश्रा जी।

अल्पकालिक चर्चा (नियम-55)

श्री विनय मिश्राः बहुत-बहुत धन्यवाद माननीय स्पीकर साहब जो आज आपने मुझे जिस विषय पर बोलने का मौका दिया है एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक बहुत ही गंभीर विषय है। वो विषय ऐसा है कि जिसमें साफ-साफ दर्शाया गया है कि कैसे दिल्ली के लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, कैसे दिल्ली के environment को खराब किया जा रहा है, कैसे दिल्ली के ईको सिस्टम को खराब किया जा रहा है। दिल्ली में लगभग 8 हजार हेक्टेयर रिज एरिया है जो 4 भागों में बंटा हुआ है और उस रिज एरिया के अंदर हजारों पेड़, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स, बायोडायवर्सिटी पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐसी तमाम सुविधाएं वहां पर हैं और जो रिज एरिया है वो दिल्ली वालों के लिए लंग का काम करता है क्योंकि जो भी गर्म हवा बाकी प्रदेशों से आती है उसको रोकने का काम करता है जैसे राजस्थान से आता है तो अरावली की तरफ से आता है नार्थन की तरफ से तो उसको रोकने का काम करता है और वहां पर जो इस बार दिल्ली के माननीय एलजी साहब द्वारा जो तहस-नहस किया गया है जो मतलब खिलवाड़ किया गया है जिसकी वजह से हमने देखा इस बार पहली बार दिल्ली में 53 डिग्री टेम्परेचर गर्मी इस बार रहा जिस वजहं से पूरी दिल्ली वाले लोग परेशान रहे, गर्मी से परेशान रहे और उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का था वो दिल्ली के एलजी का था। जहां एक ओर दिल्ली सरकार दिल्ली में पेड़ लगा रही है लगभग 64 लाख पेड़ दिल्ली सरकार के माध्यम से लगाये गये। दिल्ली सरकार स्कूलों के माध्यम से, छोटे

बच्चों के माध्यम से लोगों में जाग्रति ला रही है कि हमें अपनी दिल्ली के इनवायरमेंट को बचाना है, पेड़ लगाओ, सेंपलिंग्स हम लोग दे रहे हैं लेकिन एक तरफ आप देखिये ऐसा क्रूर तानाशाह हम लोगों को मिला है जिसने दिल्ली में 1100 पेड़ जो रिज एरिये में थे वो अमीरों की मदद करने के लिए, फार्म हाउस वालों की मदद करने के लिए उन्होंने तत्काल काटने का आर्डर दे दिया। जहां एक ओर अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में गरीबों को मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त वाईफाई, महिलाओं को मुफ्त यात्रा, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा ऐसी तमाम सुविधाएं जहां दिल्ली के लोगों को मिल रही है लेकिन एलजी साहब के माध्यम से जिनको बीजेपी ने बिठाया है वो गरीबों के हित में काम नहीं कर रहे हैं, वो अमीरों के हित में काम कर रहे हैं, उनके फार्म हाउस को बचाने के लिए जो सतबड़ी में करोड़ों के फार्म हाउस हैं उनको बचाने के लिए उन्होंने 1100 पेड़ों को काटने का आर्डर दिया। लेकिन स्पीकर साहब, इसमें एक उनके साथ लोचा हो गया, लोचा ये हो गया कि उनके पास सौरभ भाई जैसा समझदार आदमी नहीं था जिसने उनको ये बताया नहीं कि जो रिज एरिये के पेड़ हैं ये Delhi Tree Preservation Act 1994 के तहत प्रिजर्वड हैं और इन पेड़ों को, रिज एरिया में पेड़ काटने के लिए उनका कंसेंट लेने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट से परमीशन लेनी पड़ती है। लेकिन दिल्ली के एलजी साहब तो मानते ही नहीं हैं किसी को, न कोर्ट को मानते हैं। वो कहते हैं मुझे इम्युनिटी है, न पुलिस को मानते हैं, न दिल्ली की चुनी हुई सरकार को मानते हैं साथ में पूरा अमला-जमला लेकर सब जगह जाते हैं। लेकिन जानकारी

का इस बार अभाव हो गया। तो इस बार एलजी साहब जो है दिल्ली के लोगों के साथ जो खिलवाड़ कर गये वो कोर्ट में उसकी सुनवाई हो गई। मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा डिटेल के साथ आपको बताना चाहूंगा इसमें हुआ कैसे, कैसे क्या-क्या हुआ। 3 फरवरी, 2024 को एलजी साहब ने रिज एरिया का दौरा किया और मौखिक आदेश दिया कि भइया ये फार्म हाउस बचाना है मुझे इनके 5-5, 10-10 परसेंट मत लो इनकी जमीन छोड़ देना लेकिन जो दिल्ली वालों को सांस मिलती है उस सांस को तुम रोक देना। तो 3 फरवरी को दौरा करके काटने का आदेश दिया, 7 फरवरी को डीडीए ने कांट्रेक्टिंग कंपनी को पेड़ काटने के संबंध में ईमेल कर दिया, 13 फरवरी को वन विभाग ने परमीशन न होने की वजह से पेड़ काटने से रोका, 14 फरवरी को डीडीए ने ईमेल किया कि 3 फरवरी के एलजी के आदेश का हवाला देकर ठेकेदारों को कहा गया तुम ये पेड़ काट दो। उसी बीच में किसी ने इनको बता दिया कि भइया ये पेड़ काटने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट की परमीशन की जरूरत है। मार्च में इन्होंने अप्लाई कर दिया कि जो है ये पेड़ काटने की परमीशन दी जाए। लेकिन मार्च में परमीशन काटने के लिए ली लेकिन पता चला कि ये तो 16 से 26 फरवरी के बीच में ही सारे पेड़ काट दिये गये। यहां से सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी सामने आई और ये नाराजगी जायज भी है एलजी साहब के खिलाफ। जिस तरीके से दिल्ली के लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और हर काम में हस्तक्षेप कर रहे हैं, बिना किसी जानकारी के चुनी हुई सरकार को काम से रोकना। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अबकी बार दिल्ली के

लोग इस कृत्य के लिए माफ नहीं करेंगे जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली के लोगों के साथ खिलवाड़ किया है, दिल्ली के लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया है इस बार दिल्ली की जनता माफ नहीं करेगी और मैं ये भी कहना चाहता हूं एलजी साहब, बाकी प्रदेशों में इम्युनिटी प्रेजीडेंट को या गवर्नर को इसलिए मिल जाती है क्योंकि वहां के गवर्नर्ज डे टू डे एक्टिविटी में इनवाल्व नहीं होते इसलिए वो बच जाते हैं कि भई हम जो है हमें इम्युनिटी है क्योंकि वो इनवाल्व नहीं हैं लेकिन आप तो एलजी साहब आपके हजारों फोटोग्राफ्स फाइलों पर, हजारों जगह आपके मिल जाएंगे जहां आपने अपनी कलम से यहां आपने दौरा करके आर्डर दिया हुआ है कि दिल्ली सरकार के कामकाज को कैसे रोका जाए और जाकर हर जगह आपने जो दौरे किये हैं उससे साफ-साफ जाहिर हो रहा है कि आपने दिल्ली के हर काम में डिले करा है और डेली आपने दिल्ली के कामकाज में हस्तक्षेप किया है, तो आप इस बार बचने वाले नहीं हैं। आपने जगह-जगह घूमकर हर जगह रिकार्ड है, तो मैं यह मांग करता हूं कि जो दिल्ली के लोगों के साथ खिलवाड़ किया है एलजी साहब पर मर्डर का केस चलना चाहिए जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली के लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया है, उनके खिलाफ मर्डर का केस चलना चाहिए, इस बार इम्युनिटी नहीं मिलनी चाहिए। ये इम्युनिटी से बार-बार बच जाते हैं कभी गुजरात में कोई केस होता है तो वहां लिखकर देते हैं इम्युनिटी। अरे किस बात का डर है, आओ कोर्ट में अबकी बार, क्यों नहीं, एलजी अपने डीडीए के आफिसर्स पर आप प्रेशर डाल रहे हो। बेचारे कभी वो कुछ जो है

गलत लिखकर भेज रहे हैं कि हमारे को आर्डर नहीं है। कभी वो बेचारे अपने आप को बचा रहे हैं, कभी वाइस चेयरमैन को, अब जो है आप नोटिस दिला रहे हो। मैं कहता हूं आप इतने बड़े शेर हो, मुख्यमंत्री को ललकारते हो, चुनी हुई सरकार को ललकारते हो, तो क्यों नहीं अबकी बार सामने आकर कह रहे हो हां मैंने आर्डर दिया था, तब हम माने आप बहुत बड़े शेर हो। तो इस बार आप खाली जो अफसरों के पीछे जो खेल रहे हैं वो इस बार दिल्ली की जनता ने देख लिया है। मैं यही मांग करता हूं इस हाउस के माध्यम से कि एलजी साहब पर कानूनी कार्यवाही कराई जाए, उनके ऊपर मर्डर का केस चलाया जाए जो दिल्ली के लोगों के साथ खिलवाड़ किया है उनको इसकी सजा मिलनी चाहिए, तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफा देकर दिल्ली के लोगों को, दिल्ली की सरकार को काम करने की अनुमति देनी चाहिए। साथ-साथ हमारे बीजेपी के बैठे हुए हैं मैं क्या बोलूं सिर्फ दिल्ली में ही नहीं पूरे देश में जहां-जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये अमीरों की सरकार है। अडानी के लिए इन्होंने छत्तीसगढ़ में हसदेव जंगल काटने का परमीशन दे दिया। अडानी के लिए इन्होंने महाराष्ट्र में जो है 3 एकड़ जगह अलॉट हुई थी साढ़े 5 एकड़ वहां जो है पेड़ काटने की परमीशन दे दी। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ अमीरों की सरकार है। दिल्ली में एक सरकार है गरीबों की आम आदमी पार्टी की सरकार है वो भी इनको पच नहीं रही है उसके भी कामकाज समय-समय पर रोककर उनको परेशान करके कैसे गरीबों का हक छीना जाए चाहे वो दिल्ली के मार्शलों की नौकरी छीनने की बात

हो, चाहे मुफ्त बिजली पर अड़ंगा डालने की बात हो, चाहे मुफ्त पानी पर अड़ंगा डालने की बात हो, चाहे डॉक्टरों की नौकरी की बात हो, चाहे महिलाओं की यात्रा की बात हो हर जगह इनके पेट में दर्द है। मैं यही मांग करता हूं कि एलजी के खिलाफ केस चलाया जाए और उनको सख्त से सख्त सजा दिलाने की बात की जाए बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः श्री संजीव झा जी।

श्री संजीव झाः बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय कि आपने मुझे इस गंभीर विषय पर बोलने का मौका दिया। आज मैं जिस विषय पर बोलने जा रहा हूं अध्यक्ष महोदय ये व्यथा है दिल्ली वासी की और कहानी है ये नासमझ प्रशासक का। एक प्रशासक अगर नासमझ हो तो वो सूबे को कैसे बर्बाद कर सकता है इसकी ये कहानी है। एक प्रशासक को जो नासमझ हो अगर उसको असीमित पावर दे दी जाए तो किस तरह से फली-फूली बगिया को उजाड़ सकता है उसका आज की चर्चा जीता-जागता उदाहरण है। आज की ये चर्चा इस बात का साक्ष्य है कि चुनी हुई सरकार को एक नासमझ प्रशासक जिसके पास असीमित पावर हो कैसे शक्ति को छीन सकता है और रौंद सकता है। हालांकि इस पूरी कहानी जो कुछ भी मैं कहना चाह रहा हूं मैं पहली बार नहीं कह रहा हूं। इस कहानी के शिल्पकार इसी सदन में माननीय मंत्री सौरभ भारद्वाज जी हैं जो बैठे हुए हैं उन्होंने एक-एक बात को प्रैस के जरिये दिल्ली की जनता के सामने रखा, सभी एजेंसीज के सामने रखा

और माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखा। एक नासमझ प्रशासक को अगर असीमित पावर दे दी जाए तो उसका ये आतंक क्या हो सकता है आज की चर्चा ये उदाहरण है और ये कहानी शुरु होती है जो अभी विनय भाई ने कहा सतबरी के जंगल से। सतबरी का जंगल जो इको सेंसेटिव एरिया माना गया उस जंगल को कैसे उजाड़ा गया और दिल्ली के लोगों की सेहत के साथ कैसे खिलवाड़ किया गया ये पूरी कहानी उसका उदाहरण है। अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ विस्तार से कुछ डेटा हमारे माननीय सदस्य साथी जिनको मैं शुभकामनाएं भी देता हूं अभी जलबोर्ड के उपाध्यक्ष बने हैं बड़ी विस्तार से उन्होंने इस बात को रखा कि किस तरह से सतबरी के जंगल को उजाड़ा गया। माननीय एलजी साहब सतबरी के जंगल का दौरा करते हैं। माननीय एलजी किसी जंगल का दौरा करें और ईको सेंसेटिव एरिया है तो उम्मीद ये थी कि जंगल और हराभरा होगा, जंगल और सुन्दर होगा और बढ़ेगा जिसकी कोशिश दिल्ली सरकार ने की है। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने पिछले 10 साल में 3 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाये हैं। डेटा ये कहता है कि हमारा ग्रीनरी एरिया 3 परसेंट बढ़ा है। तो ये उम्मीद थी लोगों की कि जब एलजी साहब सतबरी के जंगल में गये हैं तो ये ग्रीनरी का एरिया और बढ़ेगा और सुन्दर होगा लेकिन कहानी बिलकुल उल्टी हुई कि 3 फरवरी को एलजी साहब जाते हैं और 12, 13, 14 फरवरी से वो जंगल उजाड़ने की कहानी शुरु होती है। आंकड़ा ये कह रहा है कि लगभग 1100 पेड़ काटे गये और ये 1100 पेड़ उस एरिया के थे जो रिज पर है। रिज पर सभी पेड़ काटे गये और डीडीए का एक भी

अधिकारी ये मानने के लिए तैयार नहीं है, ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि ये पेड़ एलजी साहब के आदेश से डीडीए के लोगों के आदेश के बाद ये पेड़ काटे गये। डीडीए ने कोर्ट को यहां तक गुमराह कर दिया कि ये जो मेल लिखा गया है ये मेल कंप्यूटर को हैक करके किया गया है, डीडीए के अधिकारियों ने मेल नहीं किया। ये डर और ये खौफ क्या दर्शाता है? ये डर, ये खौफ ये दर्शाता है कि एक नासमझ प्रशासक को असीमित पावर है तो वो किसी भी अधिकारी को बर्बाद कर सकता है, अधिकारी अपनी नौकरी बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक में जाकर झूठ बोला। हैरत और हास्यास्पद तो बात यह है अध्यक्ष महोदय कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा क्योंकि वन विभाग दिल्ली सरकार के पास आता है, क्या वन विभाग का परमीशन लिया गया और दिल्ली सरकार को एफिडेविट डालने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद माननीय हमारे पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी ने सभी अधिकारियों की मीटिंग बुलाई, उस मीटिंग में एनवायरनमेंट के सेक्रेटरी, उस मीटिंग में जो हमारे प्रिंसिपल कंजर्वेटर ऑफिसर हैं फारेस्ट के वो, सारे कंजर्वेटर्स, सब को बुलाया गया। उस मीटिंग में एनवायरनमेंट मिनिस्टर ने कहा कि सभी घटना का तथ्यात्मक जानकारी सरकार को दी जाये। आपको सुन के आश्चर्य होगा अध्यक्ष महोदय, पूरे दिल्ली और देश के लोगों को सुन के अचरज होगा कि एनवायरनमेंट मिनिस्टर के आदेश के बावजूद दिल्ली सरकार के, इस सरकार के सेक्रेटरी ने अपने मिनिस्टर को जानकारी नहीं दी। लगातार डायरेक्शन देने के बावजूद अधिकारियों ने जवाब नहीं दिया। क्यूं नहीं

दिया? ये जवाब इसलिये नहीं दिया कि उसको पता था कि नासमझ प्रशासक के पास असीमित पावर है, अगर हम जानकारी देंगे तो गाज हम पे भी गिरेगा। फिर आल मिनिस्टर्स की मीटिंग में सभी मिनिस्टर्स ने एक फैक्ट फाईंडिंग कमेटी बनाई और उस फैक्ट फाईंडिंग कमेटी में माननीय मिनिस्टर सौरभ भाई अभी माननीय सीएम तब मिनिस्टर थीं वो आतिशी जी और इमरान भाई एक कमेटी बनी, उस कमेटी में फैक्ट फाईंडिंग कमेटी में सभी अधिकारियों को जानकारी इकट्ठा करने के लिये डायरेक्शन दिया, लगातार डायरेक्शन दिया, बाद में एनवायरनमेंट सेक्रेटरी की चिट्ठी आती है, बड़ा ये हास्यास्पद है, सुनकर अचरज होगा आपको कि एनवायरनमेंट सेक्रेटरी ने ये लिखा कि हम अपने मंत्री के सिवाए बाकी किसी की जानकारी नहीं दे सकते और हमें अपने मंत्री से डिटेल में बात हुई है लिख के फैक्ट नहीं दिया जबकि पक्ष के भी और विपक्ष के भी साथी हैं पूरा देश ये जानता है कि अलग अलग मिनिस्टर्स, अलग अलग विभाग के सेक्रेटरिज़ को बुलाते हैं भले ही उस विभाग के हों या न हों, और ये बात Transaction of Business Rules में भी है चूंकि ये कमेटी एनवायरनमेंट मिनिस्टर के डायरेक्शन पे बना था लेकिन ये जानकारी वो जो फैक्ट फाईंडिंग कमेटी थी उस फैक्ट फाईंडिंग कमेटी को जानकारी मुहैया नहीं कराया गया। फैक्ट फाईंडिंग कमेटी जब जहां पे पेड़ कटा वहां गया तो फैक्ट फाईंडिंग कमेटी ने ये पाया कि न केवल पेड़ काटा जा रहा है बल्कि पेड़ को जड़ से उखाड़ कर हटाया जा रहा है ताकि कोई साक्ष्य न मिले। ये तो कोई घनघोर अपराधी कर सकता है, ये कोई प्रशासक नहीं कर सकता, वो

भी दिल्ली का अधिकारी नहीं कर सकते। अध्यक्ष महोदय जो आगे मैं कहने वाला हूं ये उससे भी सनसनीखेज कहानी है जो सौरभ भाई पहले ही प्रेस कांफ्रेंस में कह चुके हैं कि ये रास्ता बनाने की जिम्मेदारी यूटीपैक के पास है। अभी जो प्रशासक हैं जो एलजी साहब हैं वो ये मई में बने। उससे पहले अप्रैल में यूटी पैक ने ये बताया कि ये रास्ता कहां से बनेगा। मई में जब ये प्रशासक बने हैं उसके बाद यूटीपैक ने जहां से रास्ता बनाने की बात की थी उसके उलट रास्ता बनाया गया और ये रास्ता इसलिये उलट दिया गया और यूटीपैक के चेयरमैन एलजी होते हैं मेंबर होते हैं वीसी, ये रास्ता इसलिये बना दिया गया, उलट पलट दिया गया चूंकि यूटीपैक जहां से रास्ता दे रही थी, वहां फार्म हाउस था और यूटीपैक ने इसलिये उधर से दिया था कि वो चाहता था कि ये जंगल न कटे। तो आखिर एलजी साहब की ऐसी क्या मजबूरी थी कि फार्म हाउस वाले और जंगल में चुनने का अगर था तो उन्होंने फार्म हाउस वालों को चुना, दिल्ली के जंगल का सत्यानाश कर दिया। आखिर एलजी की ऐसी क्या मजबूरी थी कि एलजी साहब ने दिल्ली के लोगों की सांसों के साथ खिलवाड़ किया। जिस जंगल को हम दिल्ली का फेफड़ा कहते थे उस फफेड़ा को छेदने का काम किया। और ऐसा नहीं था यूटीपैक ने ये भी लिखा था कि केवल फार्म हाउस के 5 से 10 परसेंट एरिया लिये जायेंगे, ऐसा नहीं था कि पूरा का पूरा फार्म हाउस जायेगा। तो ऐसी कौन सी मजबूरी थी एलजी साहब की कि एलजी साहब ने इतना बड़ा कुकृत्य किया, दिल्ली की जनता और हम सब सदन के सदस्य ये जानना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, बार बार

सुप्रीम कोर्ट ये पूछती रही कि आखिर किसके आदेश पे ये जंगल काटा गया। एक भी अधिकारी जिम्मेदारी लेने के लिये इस बात को नहीं माना कि जिम्मेदारी किसकी थी। नाराज होकर सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि एलजी अपने आप को सुप्रीम कोर्ट न समझें, ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर रिज़ पे कोई जंगल कटेगा तो सुप्रीम कोर्ट की परमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन सच को आप ज्यादा छुपा नहीं सकते। जब सुप्रीम कोर्ट ने ठेकेदार को बुलाया, ठेकेदार से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आखिर ये किसकी परमिशन थी तो ठेकेदार इनसे नहीं डर रहा था क्योंकि ठेकेदार इनका मातहत नहीं था, उसने कहा कि मेरे पास एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का मेल आया जिस मेल में उसने कहा कि हमने ये जंगल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के मेल के बाद उस मेल में ये लिखा था कि ऑनरेबल एलजी दौरा किये थे और वहां पे उसने मौखिक आदेश उन्होंने दिया था और उस मौखिक आदेश के कारण हमने ये जंगल को काटा। ठेकेदार ने ये भी कहा कि जंगल काटते समय वहां के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, वहां का एई, वहां का जेई सब दौरा करता रहा। उस ठेकेदार ने ये भी कहा कि तत्कालीन इंजीनियर इन चीफ ने मेल में ये भी लिखा था कि ठेकेदार का कम्यूनिकेशन इंजीनियर इन चीफ से होता रहेगा। अब जब बात एई, जेई की आ गयी, फिर एई, जेई गवाह बना और उसने कहा हां कि एलजी के आदेश पे ये हमने इस ठेकेदार को चिट्ठी लिखी थी। अब समझिये उसके बाद क्या होता है और हद तो तब हो गयी जब दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने ये कह दिया कि माननीय एलजी को ये जानकारी नहीं थी कि पेड़ काटने के लिये सुप्रीम कोर्ट की परमिशन

की जरूरत है। तब मैंने पहले कहा था एक नासमझ प्रशासक जिसके पास असीमित पावर हो तो चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों न हो, उसके सामने सर झुकायेगा, अगर सर झुकायेगा तो दिल्ली को बर्बाद करेगा। अध्यक्ष महोदय, पूरी जांच पड़ताल के बाद बाद में डीडीए के वीसी ने माफी मांगा जिसमें कहा था कि ईमेल हैक हो गया हमारा। मजाक बन गया इंस्टीट्यूशन का और मजाक इसलिये बना कि एक नासमझ प्रशासक के पास असीमित पावर था तो सब कुछ को उसने ताक पर रख दिया और उसके बाद अध्यक्ष महोदय कार्रवाई की बारी आयी, आपको सुन के आश्चर्य होगा कार्रवाई किस पे हुई, उस एई और जेई पे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पे जो कोर्ट में गवाह बना था। पहले ये सभी कहे कि जंगल कटने के बाद जानकारी मिली तो 3 फरवरी के दौरे में जो डीडीए का वीसी, इंजीनियर इन चीफ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कंजर्वेटर सब गये थे, कैसे जानकारी नहीं थी। इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया है। मेरे ख्याल से आज ही सुप्रीम कोर्ट में केस है और मैं माननीय मुख्य न्यायधीश से भी ये निवेदन करता हूं कि इस पूरी एफिडेविट को पढ़े कि किस तरह से एक नासमझ प्रशासक ने सभी प्रशासनिक ईकाई को झूठ बोलने पर मजबूर किया और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो भी दोषी हो उसको बख्शा न जाये। एक बात बताईये अध्यक्ष महोदय कि आज तमाम तरह की कवायद करने की इन्होंने कोशिश की, कहानियां तो बहुत सारी हैं, मैं उस डिटेल में नहीं जाउंगा कि कैसे किस किस तरह से दिल्ली को बर्बाद करने की साजिश एलजी साहब ने किया है लेकिन आज इस पूरे जंगल काटने के

एपिसोड में जिस तरह से चुनी हुई सरकार को सुपरसीड करके सभी अधिकारियों को डरा करके ये साजिशें की गयी, आखिर उसका कारण क्या था? भई हम लोग दिल्ली के निवासी हैं, मैं इस सदन में आज रख रहा हूं और जो मैं रख रहा हूं उसकी जांच एजेंसीज़ करे वहां लोग ये कह रहे हैं कि अगर ये पहले यूटीपैक ने जो रास्ता बताया, उधर से रास्ता जाता तो कम से कम 75 फार्म हाउस को नुकसान पहुंचता, उस 75 फार्म हाउस वालों ने दो दो करोड़ रूपये दिये हैं और वो डेढ सौ करोड़ रूपया लेकर के ये सारी कवायद जंगल को बर्बाद करने की, दिल्ली को बर्बाद करने की साजिश प्रशासक ने रचा है। अगर मैं झूठ बोलता हूं तो वो ईडी, सीबीआई जांच करे। जंगल बर्बाद हुआ है दिल्ली का, वो जंगल जो ईको सेंसिटिव एरिया था, जो रिज़ था, एक पेड़ काटने के लिये अगर मेरे यहां मेन सड़क पे एक सूखा हुआ पेड़ है, कटवाने में जो पांच साल लगे, नहीं कट पाया, ये 1100 पेड़ ऐसे काट दिये तुमने, इतनी तुम्हारी हिम्मत, इसलिये कि तुमको केंद्र की सरकार ने असंवैधानिक बिल के जरिये पावर दे दिया। तो तुम्हारी नासमझी का आखिर भुगतान दिल्ली की जनता क्यों करे? उसका नुकसान चुनी हुई सरकार को क्यूं हो? तो अगर थोड़ी सी भी शर्म-ओ-हया है बीजेपी में तो मैं आज सदन से बीजेपी के सभी नेताओं से, खासकर प्रधानमंत्री से मांग करना चाहता हूं कि ऐसे नासमझ प्रशासक को तुरंत इस्तीफा दिलाये ताकि दिल्ली की जनता का भला हो। बस इतनी ही मेरी मांग है अध्यक्ष महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने का मौका दिया।

माननीय अध्यक्षः अजय दत्त जी।

श्री अजय दत्तः अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस बहुत ही गंभीर मुद्दे पे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी ये मुद्दा सिर्फ इसलिये गंभीर नहीं है कि इसमें 1100 पेड़ काटे गये, ये मुद्दा सिर्फ इसलिये गंभीर नहीं है कि एलजी साहब ने अपनी शक्तियों का दुरूपयोग किया, ये मुद्दा इसलिये भी गंभीर है इन दोनों बातों के अलावा कि एलजी साहब ने दिल्ली वालों की सांसें रोकने का जो जघन्य अपराध किया है वो बर्दाश्त के बाहर है। आज दिल्ली सरकार दिल्ली में एक हरित क्रांति के रूप में आई है। आम आदमी पार्टी की सरकार आने से पहले दिल्ली में 18 से 20 परसेंट हरियाली हुआ करती थी लेकिन पिछले 4-5 सालों से दिल्ली में करीबन 24 से 25 परसेंट हरियाली मापी गयी है और ये ऐसे ही नहीं हुआ अध्यक्ष जी, इसके पीछे दिल्ली सरकार ने बहुत सारे आम आदमी पार्टी की सरकार ने करीबन 60 लाख से ज्यादा दिल्ली के अंदर पेड़ लगाये 64 लाख पेड़ लगाये और एलजी साहब ने बिना सोचे समझे, बिना किसी से पूछताछ के, बिना किसी कोर्ट की परमिशन के क्योंकि ये जो एरिया सतबड़ी का एरिया है ये ईको सेंसेटिव एरिया कहा जाता है और इसमें एक भी पेड़ काटने के लिये बाकायदा सुप्रीम कोर्ट से परमिशन ली जाती है। लेकिन एलजी साहब ने यहां पे अपनी पावरों का दुरूपयोग करके पेड़ कटाने का जो जघन्य अपराध किया है ये माफी के काबिल नहीं है। हमारे साथी झा जी ने बहुत विस्तार से इसमें बताया और इसमें ये बात साफ खुल के सामने आ गयी है कि किसी भी डिपार्टमेंट के अधिकारी को अगर ये कहना

पड़ा कि एलजी साहब ने ये करा है तो उसकी शामत आ जाएगी। इसलिये सारा डिपार्टमेंट डरा हुआ है, यहां तक कि वीसी, डीडीए ने भी एक नयी स्टोरी बना ली कि जी डीडीए का सर्वर हैक हो गया था, ये ईमेल हैक हो गयी थी, इतना डर, इतना डर तो सिर्फ एक तानाशाह से होता है। और आज दिल्ली के अंदर एलजी साहब की तानाशाही चरम पे है, वो कुछ भी ऑर्डर दे देते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, किसी भी नाले में जाके खड़े होके फोटो खिंचा लेते हैं, किसी भी टूटी सड़क के सामने फोटो खिंचा लेते हैं और सारा अमला जुमला उनके पीछे पहुंच जाता है। लेकिन काम कुछ नहीं होता, काम होता है एलजी साहब का सिर्फ बड़े बड़े लोगों, अमीरजादों के लिये काम होता है। उनके फार्म हाउस बनाने के लिये दिल्ली के लोगों की सांसों से खिलवाड़ किया जाता है। हजारों पेड़ काट दिये जाते हैं और जब ये पेड़ काटने की बात सामने आती है तो हरेक छोटे बड़े अधिकारी को उनको डिफेंस करने के लिये लगा दिया जाता है और आखिर में जैसा कि ये सरकारी तंत्र की एक तरीके से ये एक प्रोसेस बना दिया है कि अगर कोई सीएस गलती करे तो बेचारे किसी इंजीनियर को नाप दो, और इसमें भी यही हुआ कि सीएस ने सारी लीपापोती कर ली, डीडीए ने सारी लीपापोती कर ली और एलजी साहब को बचाने के लिये वो दो तीन इंजीनियरों पे गाज डाल दी।

अध्यक्ष जी, ये देशएक लोकतंत्र से चलने वाला देश है। यहां पर एलजी साहब को अगर appoint किया गया है, तो उनको सिर्फ देखरेख के लिए appoint किया गया थां। आज वो अपने आपको इतना

पावरफुल समझ रहे हैं कि दिल्ली में जो वो मनमर्जी आए वो कर लें। दिल्ली के अंदर पेड़ काट दें, दिल्ली के अंदर किसी नाले में बैठ के तैरने लग जाएं, दिल्ली के अंदर किसी सड़क पर जाकर खड़े हो जाएं, फोटो सैशन करा लें, ये चल रहा है। जो मन किया वो कर दिया और देश के कानून को ताक पर रखने की कोशिश है। जब इसमें साफ-साफ लिखा है, दिल्ली प्रोविजन एक्ट-1993 में ये साफ लिखा है कि अगर सतबड़ी के जंगल में एक भी पेड़ कटेगा तो वो कोर्ट की परमिशन से होगा और जब कोर्ट ने इस बात को जानने की कोशिश की तो कोर्ट को पहले गुमराह किया गया, दुबारा गुमराह किया गया और आज तक गुमराह कराया जा रहा है। अध्यक्ष जी मैं आपके सामने एक और मसला लेकर आ रहा हूं। अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा की मैक्स होस्पिटल के अंदर कई हजार पेड़ थे, वो भी काट दिये गए और उनका कुछ अता-पता नहीं है, किसने परमिशन दी। जब मैंने एक पत्र के माध्यम से साउथ डिस्ट्रीक डीसीएफ को लिखकर भेजा, उसने कोई जवाब नहीं दिया और मैंने मंत्री साहब को लिखकर भेजा उन्होंने उसको बुलाने की कोशिश, उन्होंने आने से मना कर दिया। तो ये जंगल विभाग के लोग भी जानबूझ के एलजी जी के साथ मिलकर और इस तरीके के जंगल काटने की पूरी मुहिम चला रहे हैं। अगर एक पेड़, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसके घर के सामने एक पेड़ आ रहा था, वो किसी वजह से गिर गया, उसके ऊपर उन लोगों ने ढ़ाई लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया और दूसरी तरफ अमीरजादों को बचाने के लिए उनके यहां रास्ते निकालने के लिए, उनके यहां फार्म हाउस बनाने के लिए

हजारों-हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं जिसको कोई देखने सुनने वाला नहीं है। एलजी साहब ये बिल्कुल गलत सिस्टम है, ये बिल्कुल गलत तरीके हैं, ये बिल्कुल एक तरीके से भ्रष्टाचार है कि दिल्ली की सांसों के साथ अगर आप ये खिलवाड़ करोगे तो दिल्ली की जनता आपको माफ नहीं करेगी। दिल्ली की सरकार, हम लोग प्रदूषण को बचाने के लिए कितना काम कर रहे हैं, हमारे पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी अभी पोल्यूशन नवम्बर में आना होगा, उससे पहले वो तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने ग्रीन रूम बनाए, इतने काम कर रहे हैं, इतने काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप पेड़ काट रहे हो। एक जगह नहीं, दो जगह नहीं दस जगह आपने पेड़ काट दिये होंगे। जो मामले सामने आए हैं वो तो एक अलग हैं और जो मामले सामने आने वाले हैं, उनके विषय में भी और बहुत सारा उजागर होना बाकी है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि एलजी साहब आपने बहुत दिन दिल्ली वासियों पर राज करने की कोशिश की है, अब आप नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दे दो। ये दिल्ली की सांसों के साथ जो आपने खिलवाड़ किया है, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता, क्योंकि पर्यावरण बचाना, लोग कहते हैं जल ही जीवन है, बिल्कुल ठीक है। मैं ये भी कहता हूं कि जंगल ही जीवन है, अगर ऑक्सीजन मिलती रहेगी तो जीवन चलता रहेगा, अगर आप पेड़ों को काट दोगे, उनकी हत्याएं कर दोगे तो ये ना तो दिल्ली बचेगी ना दिल्ली के लोग बचेंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी नहीं बचोगे। ये जघन्य अपराध आपने किया है आप इस्तीफा दो और यहां से आप अपना गुजरात वापस पहुंच जाओ।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद। विशेष रवि जी अनुपस्थित, सोमनाथ भारती जी अनुपस्थित। शिवचरण गोयल जी।

श्री शिवचरण गोयलः धन्यवाद अध्यक्ष जी आपने मुझे इस गम्भीर मुद्दे पर बोलने का मौका दिया। 1100 पेड़ आज एक आम आदमी दिल्ली का एक पेड़ की छटाई करना चाहता है तो उसके लिए परमिशन, परमिशन और गलती से वो एक 6 इंचि का एक डाली काट ले तो उसके पीछे पूरा डिपार्टमेंट लग जाता है और उसको फिर प्रताड़ित किया जाता है और यदि एक पेड़ काट ले फिर तो मुझे लगता है कि उसके कई साल कोर्टों में चक्कर काटते हुए गुजर जाते हैं। मेरे घर के सामने एक स्कूल है उसमें किसी ने ये शिकायत कर दी, उससे उसकी रंजिश थी। पेड़ काट के तस्वीर डाली उस हैड ऑफ दा स्कूल की, वो प्रिंसिपल कम से कम भी 4 साल कोर्ट में चक्कर काटती रही और यहां पर जो मसला आया है 1100 पेड़ और अभी तो मुझे याद आ रहा है कि तीन साल पहले हमारे मंत्री सौरभ भारद्वाज जी एक-एक पेड़ को बचाने के लिए सरोजनी नगर के, जहां पर बिल्डिंगे बन रही थी वहां पर सब पेड़ों के साथ खड़े हो गए थे कि पेड़ नहीं कटने देंगे। उन पेड़ों को बचाने के लिए हम पेड़ों के साथ चिपक के खड़े हो गए थे कि पेड़ नहीं कटने देंगे। तो आज हमारे एलजी साहब ऐसे काम कर रहे हैं जैसे की वायसराय काम करते थे अंग्रेजों के समय में, जिसको मर्जी ऑर्डर दे दिया, जहां चले गए जो मर्जी हुकुम कर दिया, कोई कानून का पालन नहीं। अब 1100 पेड़ काट दिये गए हैं सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि आप इस तरह से पेड़ काटें हैं किसी से परमिशन

ली और पूरी तरह से लताड़ा गया, पूरी सरकार को, एलजी साहब को। लेकिन ये जो लताड़ने से यदि एक आम आदमी जेल में जा सकता है, तो उनके लिए कानून अलग है इनके लिए कानून अलग है। कानून सबके लिए एक है, इसके ऊपर एलजी के ऊपर जो भी बनता है उसपर कार्रवाई होनी चाहिए और आज ये कहीं ना कहीं जो अजय जी ने कहा है, सांसों को लेकर भी बात है। पूरे देश में पॉल्यूशन बढ़ रहा है। महाराष्ट्रा में पॉल्यूशन बढ़ा, गुड़गांवा में बढ़ रहा है, नॉएड़ा में बढ़ रहा है, वाराणासी में बढ़ रहा है और दिल्ली में पॉल्यूशन कम हो रहा है। दिल्ली में 32 परसैंट पॉल्यूशन कम हो चुका है और अभी तीन दिन पहले रिपोर्ट आई है कि दिल्ली का टैंपरेचर 3.75 डिग्री कम हो गया है क्योंकि यहां पर 4 करोड़ पेड़ लग चुके हैं। ये सैंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट है। अब जिस तरह से काम हो रहे हैं दिल्ली गवर्नमेंट के, हमारे माननीया मुख्यमंत्री आज नहीं है, लेकिन हमारे तो वे आज भी मुख्यमंत्री हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने जो यहां नींव रखी और उन्होंने एक ही बात की दिल्ली को पोल्यूशन से राहत देनी है। मुझे याद आ रहा है कि हम 10 साल पहले निकलते थे दिल्ली में तो कोहरा छाया होता था तो हम कहते थे ये कोहरा छा गया भई। किसी को नहीं पता था पोल्यूशन है ये। एक बारी मैं गया जयपुर की तरफ 11–12 साल पहले की बात है, तो जैसे ही हम गुड़गांव से बाहर निकले तो कोहरा गायब और सन लाइट चमक रही है, तो एक दिन बाद मैं वापस आया तो जैसे ही गुड़गांव में एंट्री की तो कोहरा। तो हम उस समय कोहरा कहा करते इस पॉल्यूशन को, उस समय नहीं पता था कि पॉल्यूशन है ये

क्योंकि उस समय पॉल्यूशन की परतें इतनी गहरी थी, उनको मापने की मशीन नहीं थी, 999 पॉल्यूशन क्रॉस कर चुका होता था और आज तो यदि 300 भी क्रॉस करते हैं तो हमारे गोपाल राय जी अपनी कैबिनेट बुला लेते हैं, पूरी दिल्ली इकट्ठी कर लेते हैं कि इसको 300 से कम लेकर जाना है, जो मर्जी करना पड़े, हमने हर दिल्लीवासी की सांस बचानी है। चाहे हमें इलैक्ट्रीकल व्हीकल करने पड़ें, हमें ग्रीन एरिया बढ़ाना पड़े, हमें सोलर सिस्टम कराना पड़े, कुछ भी कराना पड़े, ऑड-इवन करना पड़े, लेकिन हम हर दिल्लीवासी की सांसों से खिलवाड़ नहीं करने देंगे और ये अभी सर्दी आएगी, हरियाणा में पराली जलेगी और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि भई ये पराली जलेगी इसकी जिम्मेदारी किसकी है और हरियाणा में सरकार किसकी है, किसकी जिम्मेदारी है। लेकिन ये जानबूझ कर वहां पराली जलाएंगे और वहां का पॉल्यूशन दिल्ली में लेकर आएंगे, फिर ये विपक्ष वाले कूदेंगे, टीवी में कूदेंगें, सड़कों पर कूदेंगे, कहेंगें जी दिल्ली की सांसें दिल्ली सरकार खराब कर रही है, ये ओनली और ओनली सिर्फ पोलिटिक्स, पोलिटिक्स। पिछले 10 सालों से सैंटर की गवर्नमेंट है, एक काम किया हो, ओनली झूठ-झूठ, अब ये जुमला पार्टी नहीं है ये झूठी पार्टी है। हर काम के अंदर लोगों को बहकाना और अब यहां पर कोई कह रहा था बलात्कारी, इनकी बोलने की सारी मर्यादायें खत्म हो चुकी हैं। क्योंकि जो काम नहीं करता वो टांगे अड़ाता है और इनके पास काम करने को कुछ नहीं है, टांग अड़ाने के अलावा और कुछ नहीं है और मैं अध्यक्ष जी आपसे अपील करता हूं, जो कानून एक आम आदमी के लिए है वो कानून

हमारे वायसराय पर लागू होता है और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, शुक्रिया मुझे बोलने का मौका दिया।

माननीय अध्यक्ष: अजय महावर जी।

श्री अजय कुमार महावर: धन्यवाद अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूं कि बड़ा सुबह आपने सबको बधाई भी दिलवाई, आतिशी जी पहली बार मुख्यमंत्री बनी उसके बाद ये पहला सदन है और इसी में नेता प्रतिपक्ष भी पहले सत्र में उपस्थित थे और सेक्रेटरी साहब भी पहली बार इस सत्र में उपस्थित हैं, तीनों को बहुत-बहुत बधाई। वैसे मैं पहले घंटे में भी आपको एक्सपैक्ट कर रहा था कि पहला सत्र है तो पहले घंटे में आप रहतीं तो और भी अच्छा लगता। इस सदन में चर्चा में पेड़ों की और सांसों की बातें हो रही है और हर व्यक्ति ने यहां पर सांसों के बारे में बहुत कुछ कहा। सबने देखा है कोराना काल में एक-एक सांस की कीमत को और एक-एक सांसों से लड़ते हुए। छाज तो बोले जो बोले, छलनियॉं बोल रही है। ये सरकार जो कोराना काल में एक-एक सांस का दम घुट रहा था, तब अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर पा रही थी। केंद्र के interference के बाद बार-बार जो यहां झूठ परोसा जा रहा था ऑक्सीजन का उस साक्ष्य को प्रस्तुत करके और कोरोना से लड़ने की उन सांसों से पहल शुरू की गई थी। मेरे मित्र अभी कह रहे थे कि केंद्र ने कुछ नहीं किया, सिर्फ झूठी बातें कर रहे थे। अगर केंद्र सरकार ने पैरीफेरल रोड न बनाई होती ईस्टर्न और वेस्टर्न तो आज 50 हजार से ज्यादा व्हीकलस

रोज अभी भी प्रदूषित कर रहे होते राजधानी को। इलैक्ट्रीक बसें अगर केंद्र ने ना दी होती, तो दिल्ली ने परिवहन का दम तोड़ दिया होता।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः चलिये ठीक है, ठीक है, ठीक है कोई बात नहीं।

...व्यवधान...

श्री अजय कुमार महावरः और।

माननीय अध्यक्षः रोहित जी प्लीज।

श्री अजय कुमार महावरः आपने तो दिल्ली की सांसों को बंधक बनाकर रखा है खुद ही और बार-बार एक आवाज आ रही थी, मैं पहली बात तो इस बात से सहमत हूं कि पूरी तरह से इसका ट्रायल हो रहा है होना चाहिए, कसूरवार को सजा मिलनी चाहिए, जिसने गुनाह किया उसको सजा मिलनी चाहिए, न्याय होना चाहिए। लेकिन मैंने जैसा कहा कि छाज तो बोले बोले छलनी क्या बोले। बात कर रहे थे कि अमीरों की बात कर रहे थे, एक मुख्यमंत्री अपना राजमहल, शीश महल अपनी सुख-सुविधा के लिए सैकड़ों पेड़ काट देता है मुख्यमंत्री निवास के लिए तब इस सरकार को शर्म नहीं आती, तब उस समय गरीबों की चिंता नहीं होती, तब उस समय पर्यावरण का और सांसों की चिंता नहीं होती। अच्छा रहता कि उस समय भी हम गरीबों की, पेड़ों

की और सांसों की चिंता कर रहे होते। प्रदूषण की बात कर रहे थे अभी आप, दिल्ली को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मैं नहीं कह रहा, मेरा दल नहीं कह रहा कि दम घोटू राजधानी, डब्ल्यूएचओ कह रही है, दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी और सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजिज ने कहा है कि इससे अच्छा तो हमें जहर देकर मार दो। ये मैं नहीं कह रहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, कोटेड है। दस साल आपके पास सत्ता है लेकिन अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करना है, हजारों करोड़ रुपए, एक हजार से ज्यादा करोड रुपया ग्रीनसैस टैक्स ले रखा है आपने। कोई डस्ट कलैक्टींग मशीन इकट्ठी नहीं करी, वार्डों को और विधान सभाओं को नहीं दी गई। आप हैलीकोपटर से बारिश कराने की बात करते हो। जनरल छिड़काव भी नहीं करा पा रहे। एंटीस्मोगगन कितनी खरीदी है आपने, एंटीस्मोग टॉवर कितने लगाए, एक कनॉट प्लेस में वो भी वर्षों बंद रहा, ये प्रफोर्मेंस प्रदूषण पर और अपनी पीठ थपथपाना चाहते हैं। पूरी दिल्ली को प्रदूषण में, दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनाकर के आपने दिल्ली का अपमान किया, दिल्ली वालों का अपमान किया है और जिस प्रदूषण पर आप पीठ थपथपाना चाहते हैं, मेरी यमुना मां की, क्या किया यमुना मां का आपने? आठ हजार करोड रुपया केंद्र सरकार ने दिया आपको। और जब जल मंत्री, केन्द्र ने दिल्ली सरकार को चिट्ठी लिखकर के मांगा हिसाब तो दिल्ली सरकार हिसाब भी नहीं दे पाई और कितनी यमुना जी साफ करें उसका भी जवाब हर बार दूसरों पर ठीकरा फोड़ना। प्रदुषण में पराली अभी ये कह रहे थे हरियाणा है, अब पंजाब का नामनहीं लेंगे। पहले आप रिकार्ड के भाषणों

में देखिये विधानसभा में भी अध्यक्ष महोदय press conference में भी सारा रोना पंजाब पर होता था अब पंजाब में पराली हट गई, अब हरियाणा पर ठीकरा है। कभी इस राज्य पर कभी इस राज्य पर ठीकरा है कभी केन्द्र पर कभी एल.जी. पर पहले एमसीडी नहीं थीतो एमसीडी पर, अरे अपनी जिम्मेदारी कब निभायेंगे आप, दस बरस हो गये इसलिये दिल्ली दुःखी है, इसलिये नाराज़ है, इसलिये referendum जब मांगा तो लोकसभा के चुनाव में गठबंधन के बाद भी आपको zero पर all out किया और इसलिये अब मीठा-मीठा गपगप कड़वा-कड़वा थू-थू, हमारे अटल जी कहा करते थे। अभी किसी बात पर 40 हज़ार की दवाई छिड़ककर कर करोड़ों का विज्ञापन देकर भी कहते हैं ये काम हमने किया है मोहल्ला क्लीनिक हमने ये कर दिया, शिक्षा का ये कर दिया और कुछ भी गलत हो वो अधिकारी ने कर दिया, वो एल.जी. ने कर दिया, वो कोर्ट ने कर दिया, वो विपक्ष ने कर दिया, वो केन्द्र ने कर दिया, अरे भई ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छा काम तो एक भी हो, ऐसा तो मैं नहीं कहता कि कुछ अच्छे काम हुये ही नहीं होंगे, हर सरकार में कुछ ना कुछ अच्छा और बुरा दोनों होता है लेकिन मीठा-मीठा गपगप कड़वा-कड़वा थू-थू, चलेगा नहीं। अगर क्रेडिट आपका है तो डिसक्रेडिट भी आपका है अदरवाइज़ आपका कोई क्रेडिट है ही नहीं इस सरकार का और इसलिये जो लोग दिल्ली में सेवक के रूप में बोलकर आये थे और इसी सदन में हाथ बाहें फैलाकर कहे थे कि हम दिल्ली के मालिक हैं, उन मालिकों ने दिल्ली की शासक को खुद बंधक बनाकर के दिल्ली की जिन्दगी खराब की है और जो लोग अभी

कहते थे जो काम नहीं करते, गोयल साहब कह रहे थे वो कुछ और करते हैं मैं कहता हूं जो काम नहीं करते वही सिर्फ बहाने बनाते हैं, वहीं सिर्फ दूसरों का माथा ढूंढ़ते हैं कि किस पर हम ठीकरा फोड़ें और मेरी गुजारिश है की सदन इस पर सार्थक चर्चा करे और प्रदूषण की, अच्छा होना चाहिये दिल्ली में, अच्छी लोगों को सांसें मिलनी चाहिये, पेड़ों पर कन्ट्रोवर्सी अलग-अलग बयान दे रहे हैं कोई 64 लाख बोल रहा है कोई 04 करोड़ बोल रहा है, पेड़ और लगने चाहियें। हम विपक्ष की ओर से रचनात्मक सहयोग करने के लिये तैयार हैं, दिल्ली हमारी खूबसूरत होनी चाहिये, दिल्ली हमारी ग्रीन होनी चाहिये, दिल्ली की सांसें अच्छी होनी चाहिये, हम ग्रीन दिल्ली के साथ हैं, धन्यवाद अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः श्री राजेश गुप्ता जी।

श्री राजेश गुप्ताः धन्यवाद अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी अभी जो हमारे भाई विनय जी ने एक बड़ा गंभीर मुद्दा उठाया और आपने देखा कि उनके बाद में संजीव झा जी ने, अजय दत्त जी ने और बाकी हमारे विधायकों ने बड़े प्वाइंट टू प्वाइंट बहुत सारी बातें करीं तो मुझे लगा कि विपक्ष के साथी भी कुछ ऐसी बातें बतायेंगे कि पेड़ क्यों कटे, किसने काटे, नहीं काटने चाहिये थे लेकिन बड़े शेर सुना रहे थे तो सर,तू इधर-उधर की बात ना कर ये बता एल.जी. ने जंगल क्यों काटा, ये तो बात बताई नहीं आपने, ये बताओ ये बेकार की जांच छोड़ दो कोरोना-वोरोना की ये जो हो गई वो हमने क्या किया और

आपने क्या किया, गंगा पर हमने खूब लाशें देखी हैं, छोड़ो इन बातों को। आपको लाइव बताते हैं सर लाइव पोल्युशन के बारे में। इण्डिया के अंदर जो पहली city है ना रामेश्वरम् 346 severe दुनिया पूजा करने जाती है भगवान राम की, बड़ा पाप कर रहे हो आप लोग, सेन्टर से करते हो चाहे आपकी सरकार हैना। दूसरी सुनो, वृंदावन हम दिल्ली के लोग बहुत जाते हैं सर वहां 244 unhealthy तीसरी हाथरस, आप ही की सरकार है ना काफी मशहूर करी थी आपने अभी रेप कांड में 180 poor चौथी गुवाहाटी, पांचवीं भरतपुर आपकी ही सरकार है ना, छठी मथुरा, सातवीं अलीगढ़ ये रियल टाइम इर्न्फोमेशन बता रहा हूं जहां आपकी सरकार है कहां जा रहे हो, सुन तो जाओ यार, अरे यार अपनी बारी ले ली, अपनी बारी लेकर भाग जाओगे क्या? अपनी बारी लेकर मत जाओ हमारी बात सुन लो। अब ये वो जगह है जहां आपकी सरकारें हैं या वो जगह है जहां हम राम भक्त वहां पर पूजा करने जाते हैं, ये वृदांवन जहां भगवान कृष्ण की नगरी है आप ही की सरकार है योगी जी महाराज की, तो इतना पोल्युशन काहे है भाई वहां बताओ, है ना, अब आप उस पर बात नहीं करते, आप कहते हो दिल्ली में हमने पोल्युशन कर दिया, दिल्ली के चारों तरफ हमने दीवारें खड़ी कर दीं और यहीं पर अपने पोल्युशन पैदा करा, यहीं पर घोंट-घोंटकर मार रहे हैं, हैना, वहां आपने बस भी नहीं ली। उसके बाद में दिल्ली में तो बड़ी high density है छोटी सी दिल्ली में बहुत बड़ी आबादी है, वहीं पर तो ये गाड़ियां चल रही हैं, वहां की बता दो जहां पर जंगल है वहां पर इतना पोल्युशन क्यों करवा दिया आपने। महाराष्ट्रा- जैसे मुम्बई

के अंदर इस बार इन्होंने इतना पोल्युशन आया, गोआ में इनकी सरकार चल रही है वहां पर इतना पोल्युशन आ गया, हमारी बात करते हैं चलो दिल्ली की सुनो, यार पंडित जी सुनो दिल्ली की सुनो। दिल्ली के अंदर अभी आपने सुना दोबारा सुन लो थोड़ा लिख लो इस बार इस बात को कि 20 परसेंट था 23.5 परसेंट ग्रीनरी है, महानगरों में सबसे ज्यादा, इसको चैक कर लेना आप जाकर जो लड़के-वड़के आपके लिये लिखते हैं, हम तो खुद ही लिखते हैं, हमारे पास लड़के-वड़के हैं नहीं आप चैक करा दें। सबसे ज्यादा ग्रीन बैल्ट दिल्ली में है सारे महानगरों में इसे आप चैक कर लेना। पिछले छः महीने में 128 दिन क्लीन थे दिल्ली के अंदर चैक कर लेना आपके हाथ में तो आईफोन है उसमें देखो ऊपर AQI लगा दो उसमें आ जायेगा वो आपके पास साफ दिखा देगा कितना पोल्युशन है कितना नहीं है। 2022 में भारत 180 देशों में 180वें नम्बर पर था भारत में किसकी सरकार है कह दो केजरीवाल की है, हम मान लेंगे। अरे मैं क्या कह रहा हूं बताओ ना भारत का नम्बर 180वें में 180वां नम्बर था सरकार आपकी, एक बार भी प्रधानमंत्री जी ने ये मीटिंग करी और रशिया जा रहे हैं, यूक्रेन जा रहे हैं पता नहीं किस किसकी लड़ाई लड़वा देते हैं किस-किसकी लड़ाई जुड़वा देते हैं, यहां पर पोल्युशन के ऊपर बैठ जाओ ना आप बात ही नहीं करते आप बात नहीं करते, एक मीटिंग करी हो तो बता दो। अरे किसलिये रशिया-यूक्रेन पता नहीं कहां-कहां लड़ाईयां रूकवाते फिर रहे हो, तुम यहां पोल्युशन क्यों नहीं रूकवा देते। एक मीटिंग करी हो तो आप मुझे बता देना आंकड़े चैक कर लो विजेंद्र गुप्ता जी नये हमारे विपक्ष के

नेता दोबारा बने हैं अगर वो चैक कर लें, मुझको बता दें आज भी दिल्ली की रैंकिंग इस साल में 177 हुई हैं इण्डिया की रैंकिंग 180 देशों में, उसके जिम्मेदार भी हम हैं, कह दो केजरीवाल ही है।

...व्यवधान...

श्री राजेश गुप्ताः अरे दिल्ली तो भारत के अंदर ही है भारत से उठाकर बाहर थोड़ी ले जायेंगे यार, जब भारत में पोल्युशन हुआ दिल्ली को बाहर ले जायें स्वीज़रलैंड में ले जायें, Jurich में ले जायें इसको उठाकर।

.....व्यवधान...

श्री राजेश गुप्ताः चला लेंगे सर ये पूछ रहे हैं भारत सरकार चलाओगे हम चला लेंगे हम राजी हैं सब राजी हो भई हम राजी हैं छोड़ दो हम तो राजी हैं। इतना खराब हालत है 177वें नम्बर पर है भारत 180 देशों में कौन जिम्मेदार है, प्रधानमंत्री कौन है, बोलो कौन है, कह दो अरविंद केजरीवाल है, हम फिर मान लेंगे। अरे एक शहर तो बीच में है कमाल कर दिया एक इतना छोटा सा शहर पूरे भारत के अंदर इन्होंने हालात बनाये हुये हैं बात करते हैं संस्कृति की, देश की, इतना पोल्युशन तुमने करवा दिया और पोल्युशन हर तरीके का करते हो आप दंगों का, लड़ाई का, झगड़े का, नफरत का, हवा का इतना बुरा हाल इन्होंने करा हुआ है। दिल्ली की यमुना की बात करते हैं वहां पानीपत से गंदा पानी छोड़ देते हैं, वे नये वी.सी. साहब मैं आपको

बताता हूं पानीपत जाकर देखियेगा वहां पर खूब पोल्युशन छोड़ते हैं पानी के अंदर, सुप्रीम कोर्ट जब गाइडलाइन देती है, जब उनको फटकार लगाती है तो थोड़ा सा खोल देते हैं पानी डायलूट हो जाता है तो कहते हैं देखो जी हट गया, नहीं तो हम दिनेश मोहनिया से रोज़ पूछते थे जब वी.सी. थे कि यहां अमोनिया क्यों आता है रोज़ पूछता था मैं उनसे तो उन्होंने बताया था ऐसी-ऐसी चीज़ें होती हैं इतना बुरा हाल इन्होंने मचा रखा है पोल्युशन का और ये दिल्ली की बातें करते हैं। गंगा पूरी साफ है गंगा तो गाना बहुत पहले आ गया था राम तेरी गंगा मैली हो गई इस बीजेपी वालों के पाप धोते-धोते, इतने पाप ये लोग रोज़ करते हैं। अब कह रहा हूं राजनीतिक लोग अपनी बात करते रहेंगे अब आगे की सुनो कोर्ट की तो मानोगे।

...व्यवधान....

श्री राजेश गुप्ताः तो बात हो रही थी पोल्युशन की और जहां तक मैंने कहा कि पूरी दुनिया के अंदर 177वें नम्बर पर हिन्दुस्तान है जिसमें दुनिया में टोटल 180 देश हैं। दिल्ली के अंदर लगातार ग्रीनरी बढ़ी 20 परसेंट थी 23.5 हो गई, आज सारे महानगरों में सबसे ज्यादा ग्रीन बैल्ट दिल्ली के पास है पिछले छः महीनों में 128 दिन हमने साफ हवा के देखे हैं ये सब सांइटिफिक चीज़ें आपको समझ में नहीं आतीं लेकिन आप अपने लड़कों से पूछना वो थोड़ा सा आपको बता देते। अब मैं बात करता हूं राजनीतिक लोग तो बहुत सारी बातें करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो तो आप वैसे मानते नहीं क्योंकि सुप्रीम

कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को ये पावर है कि वो दिल्ली की सरकार को चलाये ट्रांसफर-पोस्टिंग कर सके आपने नहीं माना। आपने हमें सुपारी पार्टी कहा लेकिन आप इतने डर गये कि आपने संसद में जाकर उस कानून को बदल दिया, हमसे पावर छीनी। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है सुनो, तीन दिनों तक लीपापोती की, खुद को कोर्ट समझते हैं एल.जी. वी.के. सक्सैना। सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार- मैं तो नहीं कर रहा मेरी बात मत मानना, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है मानोगे? आगे कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुनवाई के पहले दिन ही ये बता देना चाहिये था कि एल.जी. पहले ही पेड़ काटने के आदेश जारी कर चुके हैं। मैं नहीं कह रहा, मुझे बहुत डर लगता है एल.जी. साहब से, हमारे बाल-बच्चे हैं भईया हम बहुत डरते हैं ऐसे लोगों से लेकिन मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। दिल्ली के रिज़ एरिया में पेड़ काटे जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सैना पर सख्त टिप्पणी की है हमने नहीं करी, ध्यान रखो, बार-बार लिख लो, कोर्ट ने कहा कि इस मामले में डीडीए के एप्लीकेशन कोर्ट के पास में पैंडिंग होने के बावजूद पेड़ों की कटाई की अनुमति देने में दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सैना ने समझदारी का इस्तेमाल नहीं किया। अब होगी तब तो करेंगे, है ही नहीं करेंगे कहां से। ये मैंने नहीं कहा आप बताओ इस पर खड़े होकर बोलो, जस्टिज़ अभय एस. ओका और जस्टिज़ उज्जवल गुईयां की पीठ ने कोर्ट की अनुमति के बिना पेड़ों की कटाई में एल.जी. की भूमिका पर कड़ी आपत्ति जताई। इसी के साथ इस मामले में एल.जी. की

भूमिका को छिपाने की कोशिश को लेकर भी डीडीए को अभी फटकार लगाई। बैंच ने कहा कि सुनवाई के पहले दिन ही ये बता देना चाहिये था कि एल.जी. पहले ही पेड़ के काटने के आदेश जारी कर चुके हैं। जस्टिज़ ओका ने कहा पहले तारीख में हमें बताया जाना चाहिये था कि एल.जी. के निर्देश थे, तीन दिनों तक लीपापोती की गई, हमें एल.जी. के इस मामले में शामिल होने के बारे में पहले दिन से ही समझ आ गया था, बताओ अब तो एल.जी. के बारे में कोर्ट को भी सब कुछ पता है। और जब ए.जी. आर. वेकेंटरमणी खुद हमारे सामने आये तब एकदम साफ हो गया। हलफनामे से पता चलता है कि डीडीए ने अनुमति मांगी थी, एल.जी. द्वारा भी पूरी तरह से विवेक का प्रयोग नहीं किया गया, अब बताओ इस्तीफा देना चाहिये नहीं देना चाहिये? कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट तुम मानते नहीं हो, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है नहीं मानते लेकिन हम तो अपनी बात कह लें। अब आप बताओ अध्यक्ष जी कि सुप्रीम कोर्ट की इतनी कड़ी टिप्पणी, एक इतनी गरिमामयी सीट के लिये हो, एल.जी. साहब के लिये और आप सोचिये आप क्या देकर जा रहे हैं अपने बच्चों को, एक 300 गज की कोठी, एक बिल्डिंग आप लोग ज्यादा दे जाते हैं, मुझे मालूम है फार्म हाउस वगैराह भी आपने, लेकिन अपने बच्चों को वो पोल्युशन भी देकर जा रहे हो आप, अब मरने छोड़ना चाहते हो उन बच्चों को। अगर आपने फरारी भी दिला दी तो किस रोड़ पर चलायेंगे, ये हालात इन्होंने देश के बना दिये। सिर्फ दिल्ली नहीं, मैंने आपको पूरे रिकार्ड से रामेश्वरम् से लेकर वृंदावन तक के बताये कि किस तरीके से पोल्युशन का भारत

के अंदर हाल है। ये अपने बच्चों के फ्यूचर के या तो ये बाहर पढ़ने भेज देंगे जैसे ये करते हैं, बाहर भेज देंगे क्योंकि हमारे बच्चे ही हैं ना कि जाओ त्रिशुल उठाओ, हमारे बच्चे कांवड़ में जायेंगे इनके बच्चे क्रिकेट का मैच, अब ICC में पहुंच गये, पहले BCCI में थे। इनके बच्चे तो वहां जायेंगे हमारे हनुमान सेना में जायेंगे, बजरंग दल बनायेंगे और इनके बच्चे जायेंगे सीधे BCCI, ICC चले गये बताओ। सबका यही हाल है इनका, इस पोल्युशन में किसके बच्चे जायेंगे, अभी हमारे विधायक जी ने ठीक कहा था एक पेड़ भी छंटवाना हो ना पागल हो जाता है एक विधायक, लोग चिट्ठी पर चिट्ठी भेजे जा रहे हैं, एमसीडी का ऑफिस करके राजी नहीं, फोरेस्ट डिपार्टमेंट कहता है सर इससे उपर नहीं काट सकते, परमीशन चाहिये। पिछले डेढ़ साल से हाई कोर्ट ने किसी पेड़ की छंटाई के आर्डर नहीं दिये पता है आपको, लेकिन आपका उन बातों से कोई मतलब नहीं है। एक बार भी अजय महावर जी ने यह नहीं बताया कि एल.जी. साहब ने इन पेड़ों को क्यों कटवाया, आप एक बार भी बता दो और आप बताओ की ठीक करा की गलत करा? हमारी सरकार लगातार काम करती है लगातार पिछले तीन महीने से गोपाल राय जी मीटिंग करते हैं, हर हफ्ते, सौरभ जी लगातार इसमें PC करते रहे, हमारे मंत्री PC करते रहे कि पेड़ नहीं कटने चाहिये थे। आप लोगों को इतना भी दर्द नहीं होता हर चीज़ में राजनीति-राजनीति-राजनीति एक बात ध्यान रखना, एक पेड़ लगभग तीन जनरेशन्स को फायदा देता है फल देता है, फूल देता है, उसकी छाया देता है और आप लोग अपनी राजनीति में सब कुछ बरबाद करना

चाहते हो। मैं विनय भाई ने जो अपनी बात रखी उसके समर्थन में ये कहना चाहता हूं की एल.जी. साहब को इस्तीफा देना चाहिये क्योंकि इस्तीफा दिये बिना उनके ऊपर कार्यवाही जिस तरीके से होनी चाहिये वो नहीं हो पायेगी, तो एल.जी. साहब को अपनी गरिमा थोड़ी सी बनाकर रखनी चाहिये और इस्तीफा देना चाहिये और मेरे को पूरा भरोसा है कि हमारे बीजेपी के साथी इसमें हमारा पूरा साथ देंगे, बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः श्रीमान विजेन्द्र गुप्ता जी।

श्री विजेंद्र गुप्ता (माननीय नेता, प्रतिपक्ष): धन्यवाद अध्यक्ष जी, सदन के समक्ष रूल-55 में short duration discussion हो रहा है और एक महत्वपूर्ण मामले पर यहां पर गैर-जिम्मेदाराना बयानबाजी हो रही है। मैं स्पष्ट कर दूं कि पूरा मामला क्या है हालांकि हमें तो आपने घंटे भर पहले ही बताया, ये एलओबी में कहीं नहीं था ये सब, 11.00 बजे जब हाउस बैठा कुछ नहीं था लेकिन उसके बावजूद भी हमें कोई excuse नहीं है जितना आप बता रहे हो उससे ज्यादा मैं आपको दूध का दूध और पानी का पानी कर देता हूं, मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी दोनों यहां बैठे हैं हम तो उन्हें भी इसी कैटेगरी में मानते हैं सीट उनकी कहीं कर दो आप उससे क्या फर्क पड़ता है। ये Central Armed Police force ये Institute of Medical Sciences ये जो Central Armed Police forces है उनका institute है और ये multi speciality hospital वहां research and referral hospital for para military

forces ये वहां बनाया गया है 22 सौ करोड़ रुपये की लागत से मैदानगढ़ी में। ये अति महत्वकांक्षी योजना है इसको एम्स को हैंडओवर कर दिया गया है और ये top tier hospital है para military forces का पूरे इण्डिया में, जहां पर भारत की जो para military forces हैं उनका ट्रीटमेंट होगा और उनकी बेहतरी के लिये ये 22 सौ करोड़ रुपया खर्च करके उसे सेन्ट्रल गर्वमेंट ने बनाया है। इसकी जो approach road है वो सिर्फ साढ़े सात मीटर की थी उस पर चार लेन में उसको कन्वर्ट करना था दो से तो 15 मीटर right of way हो गया। right of way टोटल 24 मीटर हो गया और जो vehicular है वो पन्द्रह मीटर हो गया। इसमें मजे की बात ये है कि first stage of clearance from ministry वो सब आई है। हमारे गोपाल जी यहां बैठे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी यहां बैठे हैं। वो सब अप्रूवल आई है और मैं पढ़ देता हूं वो, मुख्यमंत्री जी ने क्या लिखा ये प्रपोजल पेज 11/एन पर है। ये मैं 12/एन पढ़ रहा हूं -the proposal at page 11(1) is approved. Hon'ble LG is ये सीएम साहब लिख रहे हैं Hon'ble LG is bound by aid and advice on this subject यानि कि 11/एन पर क्या लिखा है, 11/एन पर ये सारा जो ईशू है वो ये लिखा है इसमें ये सब लिखा है कि ये top tier hospital है। ये 22 सौ करोड रूपया इस पर खर्च हुआ है। इसकी जो है सारी कार्यवाही कर ली गई है, वगैरह-वगैरह और फिर उससे पहले हमारे गोपाल राय जी के भी साईन है जिन्होंने मुख्यमंत्री जी को भेजा और उसके बाद एलजी साहब ने अप्रूवल दे दी। तो स्टेज वन की जो अप्रूवल है वो पूरी हो गई। इसमें सीईसी जो सुप्रीम कोर्ट ने

constitute की थी उसकी अप्रूवल हो गई है 24 अगस्त, 2023 को। इसके साथ-साथ इसमें the Ridge Management Board ने भी रिक्मेंड कर दिया है और उन्होंने भी अपनी अप्रूवल दे दी है। अब ये सारा मैटर हॉस्पिटल शुरू हो जाये, हॉस्पिटल तैयार है right of way हॉस्पिटल भी है और ये कॉलेज भी है, मैडिकल कॉलेज भी है। तो वहां सैकड़ों हजारों बच्चे पढ़ेंगे। मैडिकल ट्रीटमेंट होगा। हॉस्पिटल चलेगा दिल्ली को एक नया हॉस्पिटल मिला है पैरा मिलिट्री फोर्सेज के लिए जो हमारे लिए एक शान की बात है। स्टेज वन की सारी अप्रूवल हुई है। दिल्ली सरकार की अप्रूवल के बाद ही काम आगे बढ़ा है और उसके बाद जो-जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इस पूरे मामले में। एक बात मैं अध्यक्ष जी और बता दूं। 2017 में इस मामले में पहले ही सुप्रीम कोर्ट इसकी अप्रूवल दे चुका है और सुप्रीम कोर्ट की गाईड लाईन के accordingly काम आगे बढ़ा है। इसमें कुछ एरिया non-forest land है, कुछ एरिया फोरेस्ट लैंड है। तो ये सारी सिर्फ एक टैक्निकल पेंचिदगी का विषय है। आप इस पूरे मामले में जिस तरह की राजनीति खेल रहे हैं, जो बदले की भावना से आप एक अच्छे प्रोजेक्ट को जनता के सामने गुमराह करने की दृष्टि से पेश कर रहे हैं, ये आपकी फितरत बताता है कि आप लोग किस तरह बहरूपिये हैं, किस तरह रंग बदलते हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री की भाषा ये साफ दर्शा रही है कि आपको मानना पड़ेगा एलजी साहब ये aid and advice पर आप काम करते हो और हम इसकी अप्रूवल दे रहे हैं और आपको इसकी अप्रूवल देनी होगी। वरना aid and advice के सब्जेक्ट का यहां पर यूज करने की कोई जरूरत नहीं

थी, सीधा चीफ मिनिस्टर साईन करते नीचे एलजी कर देते। लेकिन आपने लिखा Hon'ble LG is bound by aid and advice on this subject. तो एक तरफ आप conviction से लिख रहे हैं और दूसरी तरफ जब उस पर कार्यवाही आगे बढ़ गई तो उस पर टैक्निकल मुद्दे उठा रहे हैं। सवाल ये है कि जब पॉलिटिकल क्लीयरेंस दे दी, आपकी सरकार ने मिनिस्ट्री ने क्लीयरेंस दे दी, गोपाय राय जी ने इसकी क्लीयरेंस दे दी, चीफ मिनिस्टर ने उसकी क्लीयरेंस दे दी तो उसके बाद आप बराबर के सहयोगी हो उस पूरे मामले पर कार्यवाही करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ केजरीवाल साहब का शीश महल बना। आलीशान शीश महल, डेढ़ सौ करोड रूपये का। 55 करोड तो उसकी construction में खर्च कर दिया। अरे साहब मैने फोटो देखे। I swear कसम खाता हूं भगवान की मैने ऐसा घर ही नहीं देखा। महल, ऐसा घर आपने भी नहीं देखा होगा। मैं फोटो देखता रह गया और साहब उसमें रह रहे हैं। साहब की आरामगाह, साहब की आरामगाह। दस लाख के टीवी टॉयलेट में लग रहे हैं। डेढ़ सौ करोड और घर बनाते वक्त पेड़ो की कटाई हो रही है। पेड़ काट दिये। पेड़ कौन-कौन से थे, सारे देशी पेड़ थे वो और उन देशी पेड़ो को बेदर्दी से काटा गया और काटने वालों को डर था अगर आधा घंटा भी देर हो गई तो श्रीमती मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जी छोडेंगे नहीं हमें क्योंकि उनको लगता है फटाफट ये तैयार होना चाहिए। फटाफट तैयार होना चाहिए। अप्रूवल आई नहीं आई काटो और वो भी कोविड में। जब सब कोविड चल रहा था, सब लोग परेशान थे, पेड काटे गए। पेड़ काटने के बाद वहां पर उसके बदले में पेड़ लगाने थे। पेड़ लगाये

नहीं। ये मेरे पास एनजीटी के आर्डर है। ये रहा। ये एनजीटी का आर्डर लेकर आया हूं मैं। इस आर्डर में कहा गया कि मुख्यमंत्री को.

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी।

माननीय नेता, प्रतिपक्षः 19 हजार सात सौ..

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी विषय से। विजेन्द्र जी विषय पर.

...व्यवधान...

श्री विजेंद्र गुप्ताः एनजीटी ने कहा..

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी आपका विषय पूरा हो गया।

श्री विजेंद्र गुप्ताः मैं, मेरी बात.

माननीय अध्यक्षः नहीं पूरा हो गया।

श्री विजेंद्र गुप्ताः अब असली बात बता रहा हूं तो पूरा हो गया।

माननीय अध्यक्षः नहीं अब आप दूसरी तरफ ले जा रहे है।

श्री विजेंद्र गुप्ताः एनजीटी ने ये आर्डर...

माननीय अध्यक्षः अब देखिये आप पहलू को व्यक्तिगत ले जा रहे हैं।

श्री विजेंद्र गुप्ताः एनजीटी ने, एनजीटी ने ये आर्डर निकाला है। 19 हजार सात सौ पेड़ लगाने थे। नहीं लगाये गए।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः बैठिये। बैठिये।

श्री विजेंद्र गुप्ताः जो पेड़ काटे आपने उसमें 19 हजार सात सौ पेड़ लगाने थे आपको आपने नहीं लगाये और आप धींगा-मस्ती कर रहे हैं। दादागिरी कर रहे है। आप एनजीटी के आर्डर को नहीं मान रहे हैं।

माननीय अध्यक्षः बैठिये विजेन्द्र जी अब बैठिये।

श्री विजेंद्र गुप्ताः डेढ़ सौ करोड़ का और जो हॉस्पिटल पैरा मिलिट्री फोर्सेज के लिए बना है।

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी हो गया अब। बैठिये-बैठिये।

श्री विजेंद्र गुप्ताः जो मैडिकल कॉलेज बच्चों के लिए पढ़ने के लिए बना है। जिससे पूरे देश को लाभ होगा, जिससे हमारी फोर्सेज का मनोबल बढ़ेगा। एक सम्मान का जिस निर्णय में आप शामिल हो। आज आप टांग खिंचाई पर उतर आये। आज आप उस पर राजनीति कर रहे है।

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी विषय पूरा हो गया।

श्री विजेंद्र गुप्ताः शर्म आनी चाहिए आपको।

माननीय अध्यक्षः अब बैठिये प्लीज।

श्री विजेंद्र गुप्ताः आपको इस तरह के एनजीटी के मानको को एक तरफ रखकर.

माननीय अध्यक्षः आपका विषय पूरा हो गया।

श्री विजेंद्र गुप्ताः सीवर जाम है, पानी नहीं आ रहा।

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी बैठिये।

श्री विजेंद्र गुप्ताः बुजुर्गो को पेंशन नहीं मिल रही, उस पर आप बात नहीं करने देंगे।

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी मैं अब और समय नहीं दूंगा।

श्री विजेंद्र गुप्ताः दिल्ली की सड़कें टूटी पड़ी हैं, उस पर बात नहीं करने देंगे आप।

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी आप बैठिये अब। विजेन्द्र जी मैं अब और समय नहीं दूंगा।

श्री विजेंद्र गुप्ताः ये मनगढंत मुद्दे बनाकर लोगों को परेशान करना चाहते है।

माननीय अध्यक्षः सौरभ भारद्वाज जी। श्रीमान सौरभ भारद्वाज जी। नहीं राजेश जी। सौरभ जी बोलेंगे। नहीं अब नहीं प्लीज। मैं इसको, सदन है ये बैठिये आप। राजेश जी बैठिये प्लीज। सौरभ जी उत्तर देंगे ना। बैठिये प्लीज। सौरभ जी।

माननीय मंत्री (श्री सौरभ भारद्वाज): अध्यक्ष जी, देश की सबसे बड़ी अदालत जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं उसकी डबल बैंच पिछले आठ महीने से परेशान है कि ये जो पेड़ कटवाये हैं ये किसने कटवाये हैं उसका नाम बता दो। सुप्रीम कोर्ट ने एलजी से पूछ लिया, डीडीए के वाईस चेयरमैन से पूछ लिया। इनकी केन्द्र सरकार से पूछ लिया। अगर विजेन्द्र गुप्ता जी को पता है कि ये पेड़ गोपाल राय जी के कहने पर, अरविन्द केजरीवाल जी के कहने पर कटे हैं तो ये बता क्यों नहीं देते वहां पर अब तक, इसको छुपा कर क्यों बैठे हैं? वहां जाओ बता दो। भई ये जो कागज तुम लेकर घूम रहे हो, ये नौ महीने से तुम बेज्जती करा रहे हो अपनी सुप्रीम कोर्ट में हर महीने। सुप्रीम कोर्ट तुम्हारी खिंचाई कर रहा है। कभी कहते हो कि जी ईमेल जो है वो हैक हो गई थी डीडीए की। अध्यक्ष जी,

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः नहीं विजेन्द्र जी अब नहीं। विजेन्द्र जी प्लीज।

माननीय मंत्रीः अध्यक्ष जी, ये डीडीए की ई-मेल है। डीडीए के इन्जीनियर इन्चार्ज ने चीफ इन्जीनियर को कॉपी करके एसई को कॉपी

करके ठेकेदार को लिखी हुई है और उसमें उसने एलजी का नाम लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि हवा में चल रहा है सबकुछ। क्या कहता एक्सईन। एक्सईन कहता –Hon'ble LG daily visited CAPFIMS road on dated 3-02-2024 and directed to clear the trees coming in the row इससे ज्यादा क्या हो सकता है। साफ–साफ एलजी का नाम लिखा हुआ है इस ई–मेल मे। डीडीए ने नहीं बताया। ठेकेदार ने बताया कि मेरे पास ई–मेल आई हुई है। अब जब ये पकड़े गए। अध्यक्ष जी, मजेदार बात ये है जब ये पकडे गए कि एक्सईन ने तो नाम लिखा हुआ है इन्जीनियर इन्चार्ज ने। एलजी से पूछा आप गए थे वहां पर तीन तारीख को, एलजी साहब ने मना कर दिया। हिम्मत होती तो कहते ना, हॉं मैं गया था। कह रहे है नहीं एलजी साहब नहीं गए एलजी साहब तो अस्पताल में गए थे। कौन से अस्पताल में गए थे, उसका नाम भी नहीं बताया। बोले भई ई–मेल कैसे लिखी गई है। डीडीए का अधिकारिक ब्यान है। सैन्ट्रल गवर्नमेंट के सबसे बड़े वकील ने वहां पर कहा है कि डीडीए की ई–मेल हैक हो गई। इनका ब्यान है वहां पर। मगर सुप्रीम कोर्ट कोई मानने वाला कोई ना था। सुप्रीम कोर्ट पीछे पड़ा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने ठेकेदार को बुला लिया। ठेकेदार ने बताया कि जिस दिन ई–मेल लिखी गई 14 फरवरी को उसके बाद रोज डीडीए का एई, डीडीए का जेई साईट पर आता था देखने के लिए कि पेड़ कट रहे है नहीं कट रहे हैं। तो ये बात ही खत्म हो गई कि ई–मेल असली है नकली है। डीडीए की तो जानकारी में थे कि पेड़ कट रहे हैं और एक दिन पहले तक उन पेड़ो को कटने से रोकने के लिए फोरेस्ट डिपार्टमेंट का

फोरेस्ट रेंजर वहां पर आ रहा था, ये बात भी ई-मेल के अंदर लिखी हुई है। ई-मेल में क्या लिखा है आगे -during the process of felling of the trees that forest officials did not let us cut the tree even on 13-02-2024. Forest Rangers came at site and did not permit on account of non-approval from competent authority, but after perusal, they permitted us verbally, verbally मौखिक to cut and fell the trees from today i.e. 14-02-2024 अध्यक्ष जी, जब एलजी साहब यहां पकड़े गए तो हलफनामे में डीडीए को ये बात लिखनी पड़ी कि एलजी साहब वहां पर गए थे मौके पर और वहां पर जहां पर मौके पर पेड़ कटने थे वहां पर भी गए और एलजी साहब ने वहां पर आदेश दिये। ये बात ई-मेल के अंदर और डीडीए के अफसरों के हलफनामे के अंदर आई है। ये तो बहुत चिंता की बात है अध्यक्ष जी कि वहां पर पेड़ काटे गए। उससे ज्यादा बड़ी चिंता की बात ये है एलजी साहब ने देश की सबसे बड़ी अदालत को धोखा देने की कोशिश की, उनको mislead करने की कोशिश की, उनको गुमराह करने की कोशिश की। एलजी साहब और डीडीए को मालूम था कि फोरेस्ट में पेड़ काटने के लिए सुप्रीम कोर्ट की express permission चाहिए। मगर एलजी साहब ने मौखिक आदेश पर पहले पेड़ कटवा दिये और जब वहां पर किसी एनजीओ पता चल गया और उसने फोरेस्ट डिपार्टमेंट से चिट्ठी पत्री करनी शुरू करी कि ये पेड़ कैसे कटे इसकी परमिशन दो तो फिर आनन-फानन में एलजी साहब की डीडीए सुप्रीम कोर्ट गई और जो पेड़ पहले ही कट चुके थे उनकी परमिशन मांगने गए कि हमें पेड़ काटने

है उसकी परमिशन दो। उस परमिशन को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया ये कह कहकर कि आप पेड़ काटने के अलावा कोई alternative solution देखो। जंगलों के अंदर इतने पेड़ कटाने की हम परमिशन नहीं देंगे। उसके बाद जब ये पेड़ काट चुके थे। पेड़ काटने के बाद उन्हीं पेड़ों को काटने की परमिशन मांग रहे थे और सुप्रीम कोर्ट ने वो परमिशन रिजेक्ट कर दी। उसके बाद इनके ऊपर contempt proceeding हुई है। इस चीज का contempt हुआ। पहली बात आपने बिना सुप्रीम कोर्ट की परमिशन के पेड़ काटे, पहला contempt दूसरा contempt कि झूठ बोल कर आप सुप्रीम कोर्ट में आए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट हमें परमिशन दे दे, हमें पेड़ काटने हैं और जब सुप्रीम कोर्ट ने आपकी परमिशन रिजेक्ट कर दी तो भी आपने सुप्रीम कोर्ट को नहीं बताया कि हम पेड़ तो माननीय पहले ही काट चुके हैं। अब तो धोखा देने आए थे सुप्रीम कोर्ट में। ये एलजी का चरित्र है। उस आदमी का चरित्र है जो half basket पहनकर जो एलजी बनता हुआ इठलाता है। क्या चरित्र है! अरे मर्द बनो। अगर तुमने अफसरों को कहा है और आपने अफसरों को डायरेक्शन दी है। इतनी मर्दांगी तो होनी चाहिए कि आए चौड़े में और बोले कि हॉं मैने दी थी परमिशन, मैने कहा था। उसने तो अफसरों के ऊपर डाल दी। एक्सईन, एई, जेई को सस्पेंड कर दिया। अध्यक्ष जी सोचिये ये किरदार है इन लोगों का जो इतनी बड़ी-बड़ी पोजिशन्स पर बैठे हैं। इन्होंने डीडीए के एई, एक्सईन और जेई को सस्पेंड कर दिया कि इन लोगों ने जो है परमिशन दे दी। ऐसा कैसे हो सकता है अध्यक्ष जी और उससे भी बड़ी गम्भीर बात अध्यक्ष जी जो

है वो वो बात है जिसके बारे में मैं अक्सर जो है और हमारी सरकार अक्सर दिल्ली के अफसरों के बारे में कहती है। जिस दिन ये मैं हलफनामा पढ़कर बता रहा हूं अध्यक्ष जी जिस दिन एलजी साहब वहां पर दौरे पर गए और मेरी जानकारी के हिसाब से एलजी साहब कई बार वहां पर दौरे पर गए। वहां का हलफनामा Pr. Chief Conservator of Forest कहता है एलजी साहब के साथ कौन-कौन थे। Pr. Secretary (Environment and Forest), Addl. Pr. Chief Conservator of Forest, Spl. Secretary (Environment), DCF, दिल्ली के चीफ सैक्रेट्री, दिल्ली के प्रिंसिपल सैक्रेट्री, पीडब्ल्यूडी, सीईओ जलबोर्ड और तमाम बड़े बड़े एमसीडी के कमिशनर तमाम दिल्ली के बड़े बड़े अधिकारी उस दिन एलजी साहब के साथ दौरे पे थे 3 फरवरी 20024 को जहां पे एलजी साहब ने मौखिक आदेश दिए कि इन पेड़ों को काट दिया जाए और अब जो सबसे सीरियस बात ये है अध्यक्ष जी जब हम ये बात कहते हैं कि एलजी साहब के आदेश पे अफसर गैर कानूनी काम करते हुए दिल्ली के अंदर कामों को रोक रहे हैं, कई लोग नहीं मानते वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, अफसर ऐसे कैसे कर सकते हैं। आज जो मैं तस्वीर दिखाऊंगा अध्यक्ष जी जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस चीज पे रूका नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को पकड़ लिया और मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इतना समय निकाला। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी बारीक बात पकड़ी है अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बात तो अब साबित हो गई है कि एलजी वहां पे गए थे और एलजी ने आदेश दिए थे अब जितने भी अधिकारी

उनके साथ गए थे चाहे वो एनवायरनमेंट के प्रिंसिपल सैक्रेट्री हों, चाहे वो चीफ सैक्रेट्री हों वो अपना अपना हलफनामा दे के बताएं कि क्या उन्होंने एलजी को बताया था कि ये पेड़ काटने गैर कानूनी हैं या नहीं बताया था? अब अध्यक्ष जी इसके अंदर दो ही ऑप्शन हैं अगर आपने एलजी को नहीं बताया कि ये पेड़ काटने गैर कानूनी हैं तो इन सब तो अफसरों को पता ही था कि पेड़ काटने गैर कानूनी हैं इनके पास इसकी परमिशन नहीं हैं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की परमिशन चाहिये होती है तो सबको मालूम था, अगर इन अफसरों ने नहीं बताया तो इन अफसरों के उपर criminal prosecution launch होना चाहिये, इनके उपर कार्रवाई होनी चाहिये और अगर ये अफसर कहते हैं कि हमने एलजी को बताया था उसके बावजूद पेड़ काट दिए गए तो एलजी के उपर criminal prosecution होना चाहिये। इन दोनों के अलावा कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है, ना एलजी के पास ना दिल्ली की top bureaucracy के पास। तो अध्यक्ष जी जो हलफनामा देने के लिए कहा था उसमें मैं दो हलफनामे पढ़ के बात खत्म करूंगा दो मिनट में, उससे आपको दिल्ली के अंदर क्या चल रहा है उसका पता चल जाएगा। मुख्य सचिव क्या कहते हैं, सुनिए। मुख्य सचिव के बयान की जो एफेडेविट है उसके अंदर मात्र एक पैराग्राफ ही काम का है बाकी सब उन्होंने कहानियां लिखी हैं। उन्होंने लिखा It is not clear from the affidavit अच्छा इसको छोड़ देते हैं as Delhi Government and DDA are before us... to the best of ये असल में ना पूरा पढ़ देता हूं आपको पूरा पढ़ देता हूं मुझे अंग्रेजी में कोई दिक्कत कोई ना है, सुनो। 'As Delhi

Government and DDA are before us, if any officers who, during the visit of Hon'ble LG, had brought to the notice of Hon'ble LG that the orders passed by this court and the requirement of obtaining permission of the Tree Officer, those officers are free to file their affidavits indicating whether they had informed the Hon'ble LG or not? अब सुनिए क्या लिखा है उस दिन सीएस ने to the best of the knowledge of the undersigned, none of the officers and the officials present at site brought to the notice of Hon'ble LG the orders passed by this Hon'ble court or the requirement of obtaining permission of the Tree Officer. It is submitted that the directions of the higher authorities during such visits to expedite completion of the projects cannot be considered as directions to overlook or by-pass the statutory provisions for expediting the works.' ये मजाक, सोचिए, मुख्य सचिव सुप्रीम कोर्ट को हलफनामे में कह रहे हैं कि ये किसी अफसर ने एलजी को नहीं बताया कि पेड़ काटने के लिए सुप्रीम कोर्ट की या ट्री ऑफिसर की जरूरत होती है।

...व्यवधान...

माननीय मंत्री (श्री सौरभ भारद्वाज): ये क्या, ये तो सबको मालूम है। ये तो बच्चे बच्चे को मालूम है, ये तो छोटे छोटे फोरेस्ट रेंजर को भी मालूम है। मगर अध्यक्ष जी मजे की बात ये है।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: विजेंद्र जी माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं कोई विधायक नहीं बोल रहा।

माननीय मंत्री (श्री सौरभ भारद्वाज): अध्यक्ष जी, मगर मजे की बात ये है चीफ सैक्रेट्री के, अध्यक्ष जी सुनिए। मगर मजे की बात क्या है चीफ सैक्रेट्री के झूठ की पोल Pr. Conservator of Forest के affidavit ने खोल दी। Pr. Conservator of Forest क्या कहता है, सुनिए। वो पूरा एफिडेविट के अंदर बता रहा है 'During the visit, following directions were given to the Forest Department. It was pointed out that mandatory permissions from the Forest Department under Delhi Preservation of Tree Act and Forest Conservation Act, 1980 were pending. The Forest Department was advised to expedite the process in this regard. उन्होंने बोल दिया कि एलजी की विजिट के दौरान Pr. Conservator of Forest ने उनको बताया था कि ये परमिशंस पैंडिंग हैं यानि कि एलजी के संज्ञान में था कि ये परमिशंस नहीं आईं हैं और सबसे खतरनाक बात ये है अध्यक्ष जी आज दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी इतनी डरी हुई है एलजी से, केन्द्र सरकार से इनके हाथ में ईडी और सीबीआई जैसी ऐजेंसिज़ से कि जब सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करते हुए भी एलजी अगर ये आर्डर देते हैं कि इन पेड़ों की परमिशन नहीं है, आपके पास सुप्रीम कोर्ट की परमिशन नहीं है, तब भी आप पेड़ काट दो तो किसी अफसर की, बड़े बड़े आईएएस अफसर, इसमें top bureaucracy थी एलजी के साथ, सीएस थे, Pr. Secretary (PWD)

थे, सीईओ थे forest के, Environment Forest Secretary थे, प्रिंसिपल सैक्रेट्री थे, एमसीडी कमिशनर थे सब थे, उसके बावजूद किसी अफसर की इतनी हिम्मत नहीं, उसकी रीढ़ की हड्डी में इतना दम नहीं कि वो एलजी साहब को ये कह दे कि एलजी साहब इसकी परमिशन नहीं है, ऐसे कैसे काट दें और पकड़े गए तो उसके बाद किसी अफसर के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर हलफनामा दे के कह दें कि हां हमने एलजी को बताया था कि इसकी परमिशन नहीं है, ये गलत काम कर रहे हैं ये हालत आज दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी की हो गई है। मुझे उनके साथ पूरी सदभावना है क्योंकि मैं मानता हूं कि उनमें से अधिकांश अफसर आज डराये गए हैं और इतने डरे हुए हैं कि एलजी के कहने पे गैर कानूनी काम करते हुए भी जो है उनको ऐसा लगता है कि अगर हम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, हमें फंसा देगें किसी ना किसी मामले के अंदर जो कि अपने आप में एक बहुत ज्यादा जो है संवेदनशील बात है, सीरियस बात है दिल्ली को ले के और अब इनके सामने ये बात है किस तरीके से एलजी ने किया है और दिल्ली में जहां पे दिल्ली की सरकार रोज पेड़ लगाने का काम कर रही है, दिल्ली के लोग रोज पेड़ लगाने का काम कर रहे हैं। अब देखिये इससे पहले इतना पॉल्यूशन कभी दिल्ली में नहीं होता था। इस बार सितम्बर के अंदर पॉल्यूशन बढ़ गया है। इस बार दिल्ली के अंदर टेम्परेचर 53 डिग्री पहुंच गया है। ये तो एक ऐसी जगह है जहां पे चोरी पकड़ी गयी है। पता नहीं कितनी जगह पेड़ कटवा रहे हैं और आखिरी बात मैं कह दूंगा एक मिनट में, ये किसी हास्पिटल के लिये रोड़ चौड़ी नहीं

की गयी इस गलतफहमी में न रहें, मैं इस गलतफहमी में नहीं हूं। ये एलजी जब आये थे इनसे एक महीने पहले यूटीपैक की मीटिंग में जो सड़क को broaden करने का नक्शा पास हुआ था उसमें वो सड़क उलटे हाथ में चौड़ी करनी थी, जहां पे बड़े बड़े करोड़पति और अरबपतियों के फार्महाउसिस थे, मगर ये एलजी जब आये इन्होंने यूटीपैक के नक्शे के खिलाफ, जो ये नहीं कर सकते थे, इन्होंने उन करोड़पतियों के फार्महाउसिस को बचाने के लिये जंगल के पेड़ काटे ये ऑन रिकार्ड है। ये किसी अस्पताल के लिये नहीं हुआ है, ये बड़े बड़े करोड़पतियों से पता नहीं क्या क्या ले के जो है इन लोगों ने किया है, वहां बहुत शोर है अगर आप वहां पे जायेंगे, सतबड़ी में लोग बता रहे हैं कितना पैसा इकट्ठा हुआ है पर फार्महाउस कितना पैसा इकट्ठा हुआ है और वो पैसा किसके पास गया है वहां का बच्चा बच्चा बता देगा। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः अब माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी।

श्री अरविंद केजरीवालः माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं भगवान की कृपा से दिल्ली के और देश के करोड़ों लोगों के आशीर्वाद से आप लोगों के बीच में जेल से छूट के आया हूं। उन सब लोगों का मैं तहेदिल से शुक्रिया अदा करता हूं, भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं हमेशा कहता हूं, मैं जानता हूं मेरे विपक्ष के साथी मुझे यहां देख के मनीष सिसोदिया को देख के दुखी तो हो रहे होंगे। तो मैं हमेशा

कहता हूं मोदी जी बहुत ताकतवर हैं, बहुत ताकतवर हैं और अथाह पैसा है उनके पास, अथाह रिसोर्सिज हैं, पर मोदी भगवान नहीं हैं। और भगवान तो है इस दुनिया में, कोई तो शक्ति है कोई उसे भगवान कहता है, कोई उसे अल्लाह कहता है, कोई कुछ कहता है कोई तो शक्ति है, वो हमारे साथ है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आज हमारे देश के अंदर न्याय व्यवस्था तो है। अध्यक्ष महोदय, आज मैं मुख्य मंत्री जी के साथ सुबह एक रोड़ का इंस्पेक्शन करने गया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में सड़कें बहुत शानदार हुआ करती थीं। मेरे पास जेल से छूटने के बाद कुछ लोग आए उन्होंने बताया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की सड़कें खराब हो गई हैं। मैं आज रोड़ इंस्पेक्शन करने गया था और बहुत बुरा हाल था सड़कों का तो मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा कि इनको तुरंत ठीक करवाया जाए, उन्होंने आदेश दिए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि उस सड़क को जल्द ठीक करवाया जाएगा।

...व्यवधान...

श्री अरविंद केजरीवालः मैं तीन चार दिन पहले एक भाजपा के बड़े नेता से मिला। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा मुझे गिरफ्तार करके क्या मिला आपको कुछ फायदा हुआ, बोले आपके पीछे से हमने पूरी दिल्ली सरकार डीरेल कर दी, हमने आपके पीछे से दिल्ली ठप्प कर दी। बड़ा खुश हो रहा था। मुझे सुनकर बड़ा दुख हुआ, आक्रोश भी हुआ और मैं स्तब्ध रह गया। देश की राजधानी के दो करोड़ लोगों की जिंदगी खराब करके उनको खुशी हो रही है। ऐसी कैसी पार्टी हो सकती है,

ऐसे कैसे नेता हो सकते हैं जो दिल्ली ठप्प करके, दिल्ली के दो करोड़ लोगों की जिंदगी खराब करके, परेशान करके और वो खुश हो रहे हैं, क्या राजनीति इस स्तर पे गिर सकती है कि वोट लेने के लिए उनका मकसद क्या है? उनका मकसद था कि हमारे को बदनाम करना, आम आदमी पार्टी की सरकार को बदनाम करना ताकि उनको वोट मिल जाएं। नॉर्मल वो देख चुके तीन चुनाव से लगातार तीन क्या ये तो 25-27 साल से, 1997 से बाहर हैं तो 23 और 4 सत्ताइस साल से वनवास है। सत्ताइस साल से इनको दिल्ली की जनता वोट नहीं दे रही। अब ये दिल्ली की जनता को परेशान करके वोट लेना चाहते हैं। अरे आपके पास तो केन्द्र सरकार है यार, केन्द्र सरकार के पास अथाह पैसा है। केजरीवाल 500 मौहल्ला क्लीनिक बनाता है आप 5 हजार मौहल्ला क्लीनिक बनाओ ना दिल्ली में कौन मना कर रहा है। ये मनीष सिसोदिया ने 700 स्कूल बनाए हैं आप सात हजार स्कूल बनाओ ना दिल्ली में कोई हमको पूछेगा ही नहीं। आज.

...व्यवधान...

श्री अरविंद केजरीवालः 500 मौहल्ला क्लीनिक अगर मैंने बनाए आप उन 500 मौहल्ला क्लिनिक की दवाइयां बंद करके केजरीवाल को बदनाम करके वोट लेना चाहते हो ये गलत बात है। ये जनता भी देख रही है। सब साफ हो जाता है जनता के सामने, आपको लगता है आप ही होशियार हो, जनता बड़ी सयानी है, जनता देखती है, जनता चुप

रहती है। वोट वाले दिन जब बटन दबाने जाती है तब जनता अपना गुस्सा जाहिर।

...व्यवधान...

श्री अरविंद केजरीवाल: एक मिनट भाई साहब, मैंने बीच में नहीं बोला जब आप लोग बोल रहे थे अब आप भी जरा सुन लीजिए फिर उसके बाद आप बोल लेना।

...व्यवधान...

श्री अरविंद केजरीवाल: तो काम रोकने से, काम खराब करने से जनता वोट नहीं देगी।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: उचित नहीं है।

श्री अरविंद केजरीवाल: काम करने से, अच्छा काम करने से जनता वोट देगी। अच्छा काम करो, आपने मेरी गैर मौजूदगी में दिल्ली में सड़कों की रिपेयर बंद करा दी। मेरी गैर मौजूदगी में आप दिल्ली की सारी सड़कें बनवा देते, कहते केजरीवाल जेल में बैठा है हम बनवा रहे हैं सड़क। देखो आप जीत ना जाते तो। बाहर निकल के मैं किस बात पे वोट मांगता, आज मैं वोट मागूंगा, केजरीवाल आ गया अब तुम्हारी सड़कें रिपेयर कराऊंगा मैं। ले आते 5 हजार करोड़ रूपये मोदी जी से, केंद्र सरकार से, सारा पैसा तो आपके पास है। पांच हजार

करोड़ रूपये में नयी नयी सड़कें बनवा देते सारी एमसीडी की सड़कें रिपेयर करा देते, सारी दिल्ली सरकार की रिपेयर करा देते, हमारे पास कुछ काम ही नहीं बचता, आप ही आप होते। लेकिन आपकी तो पूरी की पूरी मेंटैलिटी ही नेगेटिव है, इसके काम रोको, इसको ईडी भेज दो, इसको सीबीआई भेज दो, इसको जेल भेज दो, अरे कभी कभी थोड़ा भगवान के सामने बैठ के, हाथ जोड़ के शांति से भी सोचा करो। इन्होंने बस मार्शल हटा दिये मेरे पीछे से, बताओ। कोई अच्छा काम करा ? वो बस मार्शल आते हैं बेचारे, गरीब परिवारों से आते हैं। बस मार्शल की नौकरी कौन करता है, कोई अमीर आदमी, आपके बच्चे तो करते नहीं बस मार्शल की नौकरी। वो तो बेचारे गांव के हमारे दिल्ली देहात के बच्चे जो हैं, गरीबों के बच्चे हैं वही करते हैं बस मार्शल की नौकरी और बसों में जाके देखो महिलायें जो इतने गुनगाण किया करती थी कि अब हमारे को सुरक्षा महसूस होती है, अब वो फिर से उसी हालत में हो गयी महिलायें। बुजुर्गों की पेंशन बंद कर दी, उनके दिल से उनकी आत्मा से आपके लिये क्या निकलेगा, बद्दुआ ही निकलेगी, बद्दुआ ही निकलेगी। अब केजरीवाल जब उनकी पेंशन चालू करायेगा हमारे लिये आशीर्वाद निकलेगा। तीर्थयात्रा बंद कर दी बताओ, तीर्थ यात्रा बंद कर दी। हम बुजुर्गों को रामेश्वरम ले जाते थे, पुरी ले जाते थे, शिरड़ी बाबा ले जाते थे, हरिद्वार, ऋषिकेश ले जाते थे, वैष्णो देवी ले जाते थे, कितनी जगह ले जाते थे, उनकी तीर्थयात्रा बंद कर दी आप लोगों ने। आप खुद भी होकर आओ थोड़ा तीर्थयात्रा, थोड़ी मन को शांति, मेरी अध्यक्ष महोदय से निवेदन है विपक्ष के साथियों के लिए

तीर्थयात्रा का आयोजन करें। अभी जैसे सौरभ बता रहा था पेड़ काट दिए हमारे पीछे से, मैं जब जेल गया इन्होंने पीछे से पेड़ काट दिए बताओ दिल्ली के। तो दिल्ली की जनता के मन में दो चीजें हैं, दो बातें हैं, एक केजरीवाल कटट्र ईमानदार है, केजरीवाल कुछ भी हो सकता है बेईमान नहीं हो सकता और दूसरा केजरीवाल काम करता है, जनता के लिए काम करता है, ये दो बातें दिल्ली की जनता के मन में हैं। ये उन दोनों बातों पर चोट करना चाहते थे। ये केजरीवाल को बेईमान साबित करना चाहते थे और ये दिखाना चाहते थे भई केजरीवाल के सारे काम ठप्प हो गए, उन दोनों बातों पर चोट किया। ृर्जी केस कर दिया मेरे ऊपर। केस करके मनीष को जेल में डाल दिया, सत्येन्द्र जैन को जेल में डाल दिया, मेरे को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, विभव को जेल में डाल दिया, विजय नायर को जेल में डाल दिया, ये सबको जेल में डाल दिया। मैं आज चैलेंज करता हूं पांच सबसे बड़े नेताओं को जेल में डालने के बाद भी आज हमारी पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है। मैं चैलेंज करता हूं, तुम्हारी पार्टी के दो लोगों को जेल में डाल दो तुम्हारी पार्टी न टूट जाए। और इन्होंने ऐसा कानून लगाया मेरे ऊपर जिसमें बेल में भी नहीं मिलती, ऐसा कानून, इतना सख्त कानून लगाया बेल भी नहीं, उसके बावजूद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मुझे बेल दे दी। मनीष सिसोदिया जी को बेल दे दी और आज हम यहां बैठे हैं। जब मैं जेल से निकला, मैंने इस्तीफा दे दिया, किसी ने मांगा नहीं था, मैंने खुद-ब-खुद इस्तीफा दे दिया और मैंने दिल्ली की जनता को बोला है अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है तो मेरे को वोट देना वर्ना वोट मत देना। मैं दिल्ली में घूम

रहा हूं अध्यक्ष महोदय, एक बच्चा, एक आदमी, इनके कटट्र बीजेपी वाले, आरएसएस वाले भी ये नहीं कहते कि केजरीवाल बेईमान है, कोई नहीं कहता। तो इनके सारे हथकंडे फेल हो गए केजरीवाल को बेईमान साबित करने के लिए।

दूसरा ये ये साबित करना चाहते थे केजरीवाल के काम ठप्प हो गए। मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं आपका बेटा आ गया, आपका भाई आ गया। इन्होंने जितने काम ठप्प करे हैं सारे काम दुबारा शुरू कराऊंगा, एक-एक काम शुरू कराऊंगा, जो करना पड़ेगा वो करूंगा, जैसे करना पड़ेगा करूंगा, दिल्ली की जनता को परेशान नहीं होने दूंगा मैं काम ठप्प नहीं होने दूंगा।

लोग कहते हैं जेल जाने से नुकसान हुआ, जरूर हुआ, मैं मानता हूं जेल जाने से बहुत नुकसान हुआ है पर केजरीवाल का नुकसान नहीं हुआ, मनीष सिसोदिया का नुकसान नहीं हुआ, दिल्ली के दो करोड़ लोगों का नुकसान हुआ। आज जब घर से निकलते हैं अपनी गाड़ी लेकर या कैसे भी, वो टूटी हुई सड़कों के ऊपर उनकी गाड़ी ऊपर नीचे होती है, प्रदूषण होता है उसकी वजह से। आज जगह-जगह सीवर ओवरफ्लो कर रहे हैं। बस मार्शल हटा दिए इन लोगों ने। दवाइयां मैं बात कर रहा था, टेस्ट बंद कर दिए, बताओं अस्पतालों में टेस्ट बंद कर दिए, यार तुम लोगों ने दवाइयां बंद कर दी अस्पतालों के अंदर, ये सब ठीक नहीं है, ये सब ठीक नहीं है, अच्छी बात नहीं है। थोड़ा भगवान से डरो। अभिमान.. रावण का भी अभिमान नहीं टिका था। मैंने

अंदर गीता और रामायण बहुत पढ़ी और उसी का, मैं आपसे हाथ जोड़कर पूरी विनम्रता से कह रहा हूं अभिमान मत करो, अहंकार मत करो, अहंकार टिकता नहीं है, किसी का नहीं टिकता, इतिहास में किसी का अहंकार नहीं टिका, आप भी थोड़ा भगवान से डरो।

अब चुनाव में जनता जवाब देगी कि केजरीवाल चोर है या केजरीवाल को जेल में भेजने वाले चोर हैं। जनता जवाब देगी कि जनता को काम रोकने वाले पसंद हैं कि काम करने वाला पसंद है। और अध्यक्ष महोदय जब इतिहास लिखा जाएगा तब ये लिखा जाएगा कि एक मनीष सिसोदिया था जिसने दिल्ली के स्कूल चालू करे और स्कूल अच्छे करे उसको जेल में डाल दिया। एक सत्येन्द्र जैन था जिसने दिल्लीवालों की बिजली मुफ्त करी, दिल्लीवालों के लिए मोहल्ला क्लिनिक बनाए, दवाइयां मुफ्त करी उसको जेल में डाल दिया, उसके काम रोक दिए। और एक बीजेपी थी जिन्होंने सारे काम रोक दिए। जब इतिहास लिखा जाएगा तो बीजेपी के भी कारनामे लिखे जाएंगे, मनीष सिसोदिया के भी, अरविंद केजरीवाल के भी और सत्येन्द्र जैन के भी।

अध्यक्ष जी, जेल से निकलने के बाद मैंने इस्तीफा दे दिया। मुझे इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं थी, किसी ने, इन्होंने भी नहीं मांगा था मेरा इस्तीफा। इन्होंने तो पोस्टर लगाए थे इस्तीफा दो, मैंने जब दे दिया तो इनको ये समझ नहीं आया उन पोस्टरों का क्या करें अब।..

...व्यवधान...

मैंने इस्तीफा दे दिया। मेरी जिन्दगी में तीन बार ऐसे मौके आए हैं जब बड़े-बड़े पदों से मैंने इस्तीफा दिया है अपनी जिन्दगी में वालन्टेरेली, स्वेच्छिक, अपनी मर्जी से, किसी ने मांगा नहीं था। मैं इन्कम टैक्स में काम किया करता था जॉइंट कमिश्नर की पोस्ट पर था, मन में ये था कि देश के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है तो मुझे ये लगा कि जो मैं नौकरी कर रहा हूं ये नौकरी तो और कई लोग कर लेंगे, मेरे जैसे और बहुत इन्कम टैक्स में जॉइंट कमिश्नर हैं, कमिश्नर हैं, वो लोग कर लेंगे। मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जो हर आदमी नहीं करता। मैंने जॉइंट कमिश्नर की नौकरी से त्यागपत्र देकर और 10 साल दिल्ली की झुग्गियों के अंदर काम किया। जॉइंट कमिश्नर की नौकरी से मैंने इस्तीफा दिया था, किसी ने इस्तीफा मांगा नहीं था। और जब मैंने इस्तीफा दिया था, 2006 में इस्तीफा दिया था, वैसे तो मैं छुट्टी लेकर 2000 से ही निकल गया था, उस वक्त कोई पार्टी नहीं थी, कोई आंदोलन नहीं था और दिल्ली की झुग्गियों में जाकर मैं रहने लगा था। तब ये नहीं था कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा या चुनाव लड़ूंगा, चुनाव लड़ने की कोई इच्छा नहीं थी। फिर 2013 में हमारी सरकार बनी और 49 दिन की सरकार के बाद अपने उसूलों पर मैंने इस्तीफा दिया था, 49 दिन के बाद, किसी ने मांगा नहीं था इस्तीफा, 49 दिन के बाद इस्तीफा दिया था। और अब तीसरी बार अब जेल से निकलने के बाद मैंने इस्तीफा दिया है। मैं सत्ता के लिए नहीं आया। मेरे को सत्ता की जरा सी भी भूख नहीं है, मेरे को सत्ता का, पैसे का जरा सा भी

लालच नहीं है। देश के लिए आए हैं, देश के लिए कुछ करने के लिए आए हैं।

और दूसरी तरफ ये लोग बेचारे परेशान हो गए हैं कह-कहकर भई 75 साल का रूल आपने ही बनाया था। मेरे को कल एक आरएसएस के बहुत सीनीयर नेता मिले, उन्होंने बताया, बोले जी आरएसएस ने अल्टीमेटम दे दिया है कि भई 75 साल का रूल तो लागू होगा लेकिन वो मान नहीं रहें कह रहे है सत्ता छोड़नी बहुत मुश्किल है, सत्ता, कुर्सी छोड़नी बहुत मुश्किल है।

...व्यवधान...

श्री अरविंद केजरीवाल: एक मिनट, वो बोलने के लिए ललचा रहे हैं, मेरे बाद बोल लेना। सत्ता छोड़नी अध्यक्ष महोदय बहुत मुश्किल है। सत्ता का लालच छोड़ना बहुत मुश्किल है। खुद ही रूल बनाया, उस रूल के तहत सबसे पहले आडवाणी जी का इस्तीफा लिया, मुरली मनोहर जोशी जी का इस्तीफा लिया, सुमित्रा महाजन जी का इस्तीफा लिया, बी.सी. खंडूरी जी का इस्तीफा लिया, कालराज मिश्र का इस्तीफा लिया, आनंदीबेन पटेल का इस्तीफा लिया, शांता कुमार जी का इस्तीफा लिया, करिया मुंडा जी का इस्तीफा, हुकुमदेव नारायण जी का इस्तीफा लिया, नजमा हेपतुल्ला जी का इस्तीफा लिया, भगत सिंह कोश्यारी जी का इस्तीफा, और भी बहुत हैं, मेरे पास तो थोड़े ही नाम हैं। उन सबका इस्तीफा लेने के बाद जब अपना नम्बर आया तो कहते हैं ये

कानून मेरे पर लागू नहीं होगा, ये तो ठीक नहीं है। सबके लिए बराबर कानून होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मैं ये सोच रहा था कल को कोई असफर 60 साल की उम्र होने के बाद कहे मैं तो नहीं रिटायर होता जी, कल को कोई सुप्रीम कोर्ट का जज 65 साल की उम्र होने के बाद कहे जी मैं तो रिटायर नहीं होता, व्यवस्था ही खराब हो जाएगी, ऐसे व्यवस्था कैसे चलेगी। अगर आपने अपने अंदर एक रूल बनाया, कानून बनाया भई 75 साल में सारे रिटायर होंगे तो सारे रिटायर होंगे उसमें सारे आते हैं। उसमें, तो सत्ता का लालच जो है, कुर्सी से चिपके रहने का, जो कहते थे परिवार नहीं है, किसके लिए, पता नहीं किसके लिए इतना लालच है। तो आज आरएसएस के कार्यकर्ता घर-घर में जब जाते हैं तो लोग उनसे पूछते है कि भई 75 साल का रूल उनके ऊपर क्यूं नहीं लागू होगा जब सबके ऊपर लागू हो रहा है। तो मुझे ये लगता है कि जब आदमी किसी बड़े पद पर बैठे तो उसे निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करनी चाहिए, पद रहे, न रहे इसकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए।

अंत में अध्यक्ष महोदय मैं फिर से ये ही कहना चाहूंगा हमारी दिल्ली बहुत खूबसूरत है, हमारे दिल्लीवाले दिलवाले हैं। हमें सबको, दो-ढाई करोड़ लोगों को मिलकर दिल्ली बनानी है, इसमें हर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको मिलकर दिल्ली बनानी है, इसमें ब्राह्मण, यादव, जाटव, दलित, बनिये सबको मिलकर बनानी है। इसमें बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले, आम आदमी पार्टी हम सबको मिलकर बनानी है।

इसमें ये काम रोकना, काम बंद करना ये अच्छी बात नहीं है। मैं अपने सभी विपक्ष के साथियों से भी निवेदन करता हूं कि चुनाव के टाइम में चुनाव लड़ेंगे, चुनाव के बाद हमें सबको मिलकर काम करना है। थैंक यू अध्यक्ष महोदय।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद। माननीय पर्यावरण मंत्री–गोपाल राय जी चर्चा का उत्तर देंगे।

माननीय पर्यावरण मंत्री (श्री गोपाल राय): माननीय अध्यक्ष जी, दिल्ली के अंदर अवैध तरीके से 1100 पेड़ जिस तरह से कटवाए गये उसको लेकर के सदन काफी देर से चर्चा कर रहा है। चर्चा के दौरान माननीय स्वास्थ्य मंत्री- सौरभ भारद्वाज जी ने भी कई कागज और कई स्टेटमेंट डीडीए के इंजीनियर्स से लेकरके, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों से लेकरके और सुप्रीम कोर्ट तक का सारा तथ्य सदन के सामने रखा।

श्री विजेंद्र गुप्ता (माननीय नेता-प्रतिपक्ष): कागज तो हमने भी दिखाये कोर्ट में..

माननीय पर्यावरण मंत्रीः माननीय नेता-प्रतिपक्ष अभी फाइलों की कुछ कॉपियां दिखा रहे थे जो उनको एल.जी. हाउस से दिए गए कि यही बोलना। माननीय अध्यक्ष जी, मैं चैलेंज देकर कहना चाहता हूं..

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः अब सुन लीजिए।

माननीय पर्यावरण मंत्रीः माननीय नेता-प्रतिपक्ष को भी, माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी, डीडीए के सभी अधिकारियों को भी और पूरी भारतीय जनता पार्टी को भी पेड़ों के काटने का परमिशन डीडीए के पास अगर है तो कोई भी सामने लाकरके दिखा दो। न केंद्र सरकार ने परमिशन दिया, न राज्य सरकार का परमिशन है, न सुप्रीम कोर्ट का परमिशन है और एल.जी. की मनमर्जी से सरेआम पेड़ काट करके गिरा दिए गए, उसके बाद कागज दिखा रहे हो आप। और अभी आपको पता नहीं है..

...व्यवधान...

श्री विजेंद्र गुप्ताः उस पर आपके हस्ताक्षर है।

माननीय पर्यावरण मंत्रीः हमारे हस्ताक्षर जो है पेड़ काटने के नहीं है, सुप्रीम कोर्ट और ट्री कानून के हिसाब से एक भी..

...व्यवधान...

माननीय पर्यावरण मंत्रीः सुन लीजिए।

माननीय अध्यक्षः भई विजेन्द्र जी आप,

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः नहीं, विजेन्द्र जी बैठिये आप।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी, ये कोई तरीका नहीं है।

...व्यवधान...

माननीय पर्यावरण मंत्रीः देखो मेरी आवाज दबा नहीं पाओगे। न आप दबा सकते हों, न एल.जी. दबा सकते हैं, न भाजपा दबा सकती है।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी, बैठिये आप।

...व्यवधान...

माननीय पर्यावरण मंत्रीः एक बार पढ़ लेना फाइल।

...व्यवधान...

माननीय पर्यावरण मंत्रीः सुनो आप, ये जो परमिशन जो होती है, ये जो परमिशन है, सुन लो, ये परमिशन सरकार से परमिशन लेने के बाद इसके आगे की कार्रवाई होती है। पावर है ट्री ऑफिसर को। इस सारे के बाद कितना पेड़ कहां लगेगा डिपार्टमेंट सब्मिट करता है। डिपार्टमेंट के सब्मिट करने के बाद..

...व्यवधान...

श्री विजेंद्र गुप्ताः सब है।

माननीय पर्यावरण मंत्रीः ट्री, नहीं आए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः है।

माननीय पर्यावरण मंत्रीः मैं पर्यावरण मंत्री हूं, नहीं आए। सुनो आप,

...व्यवधान...

माननीय पर्यावरण मंत्रीः सुन लो, नहीं आए।

...व्यवधान...

माननीय पर्यावरण मंत्रीः अगर कोई भी, मैं यही बात फिर दोहरा रहा हूं डीडीए के पास अगर पेड़ काटने का ट्री ऑफिसर का परमिशन है, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं..

...व्यवधान...

माननीय पर्यावरण मंत्रीः सुनो, कल सदन के सामने रख देना।

माननीय अध्यक्षः भई विजेन्द्र जी ये तो बात ठीक नहीं अब।

...व्यवधान...

माननीय पर्यावरण मंत्रीः कल आप सदन के सामने रख देना।

माननीय अध्यक्षः आप टोके जा रहे हों।

माननीय पर्यावरण मंत्री: डीडीए के पास अगर परमिशन है, चाहे जेई के पास हो, एई के पास हो, एक्सईएन के पास हो, डीडीए के वाईस चेयरमैन के पास हो, जहां एल.जी. चेयरमैन हैं डीडीए के, किसी के पास भी ट्री ऑफिसर का परमिशन है कल सदन के अंदर लाकर रख देना वर्ना कल सदन में आना मत, कल लाकर रख देना सदन पर, परमिशन लाकर रख देना।

...व्यवधान...

माननीय पर्यावरण मंत्री: वो परमिशन नहीं है, पेड़ काटने का परमिशन नहीं है वो।

...व्यवधान...

माननीय पर्यावरण मंत्री: साइन हमने किए है, साइन मुख्यमंत्री जी ने किए थे, साइन एल.जी. ने किए थे, पेड़ काटने के परमिशन नहीं थे डीडीए के पास। भाई, आप सुनो, मैं क्या कह रहा हूं आप समझो।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी आप अपनी बात बोलिए, उलझिये नहीं। भई अब ये, ये ठीक नहीं है तरीका। प्लीज।

माननीय पर्यावरण मंत्री: नहीं-नहीं, अध्यक्ष जी, उनकी मुंहजोरी का जवाब देना मैं जानता हूं। मैं कह रहा हूं आपके सदन में माननीय मेम्बर वो भी हैं, माननीय मेम्बर मैं भी हूं,

...व्यवधान...

माननीय पर्यावरण मंत्रीः एक सेकेण्ड पेड़ कटता है Tree Officer के साइन से। ना, आप सदन पे कल लाके रख दो। अगर, सुनो सब, फाइल लेके मत घूमो।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी अगर आपको इस ढंग से डिस्टर्ब किया जायेगा ना, नहीं आप बैठिए आप। वो आपने जो बोला है उसका जवाब नहीं देंगे, आपने जो सदन में बोला है उसका जवाब देंगे, नहीं देंगे?

श्री कुलदीप कुमारः अध्यक्ष जी जो कागज दिखा रहे हैं ना इस मामले को Privilege Committee को भेज दीजिए इस मामले को।

माननीय पर्यावरण मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ और दोहरा देता हूँ। सदन कल भी चलेगा। कल मैं भी आऊंगा सदन में। माननीय नेता, प्रतिपक्ष भी आयेंगे। इनको आधी जानकारी दी गई। वो उसके आधार पे बोल रहे हैं। माननीय नेता, प्रतिपक्ष एलजी साहब तो अभी विदेश में हैं, यहां हैं नहीं। लेकिन टेलिफोन पर आज कल रोजाना एक आदेश जारी होता है। जब तक दिल्ली में थे आदेश नहीं होता था। जब से वो विदेश गए हैं रोजाना एक आदेश जारी होता है। ये हो रहा है, वो हो रहा है। उनसे भी पूछ

लेना आप। डीडीए के वाइस चेयरमैन से भी पूछ लेना, अपनी वकीलों से भी पूछ लेना ट्री ऑफिसर ने पेड़ काटने का परमिशन डीडीए को नहीं दिया था, एक। दूसरा, रिज क्षेत्र में ये जो जिस फाइल की आप बात कर रहे हो ये रिज क्षेत्र के बाहर का है। 1100 पेड़ काटे गए हैं ये 422 फाइल की बात आप कर रहे हो। 1100 पेड़ में बाकी रिज के अंदर आते हैं और रिज का परमिशन दिल्ली सरकार दे भी नहीं सकती है। रिज के परमिशन के लिए सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है। आपके डीडीए के लोग गए केन्द्र सरकार के पास, केंद्रीय वन विभाग के पास, वहां से वो गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने भी परमिशन नहीं दिया। बिना परमिशन के ना तो ट्री ऑफिसर दिल्ली का परमिशन दिया, ना सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दिया और मौखिक तरह से आदेश देकर के पेड़ काट दिये गए। अध्यक्ष महोदय, ये दर्दनाक है। ये दिल्ली के लोगों के साथ एक तरफ अध्यक्ष जी माननीय प्रतिपक्ष के कई मेंबर कह रहे थे 10 साल में क्या हुआ। जब से दिल्ली में अरविन्द केजरीवाल जी की सरकार बनी दिन रात काम किया है और ये तब किया है ये आंकड़ा लेके रख लेना। ये आंकड़ा है। ये आंकड़ा है दिल्ली में एक्यूआई का। 34.6 परसेंट 2016 के बाद 2023 तक दिल्ली का प्रदूषण कम हुआ है। ये आंकड़ा है पीएम 10 और पीएम 2.5 का, ये अरविन्द केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय ये केवल आंकड़े नहीं हैं। काम किया है तब प्रदूषण कम हुआ है। दिल्ली के अंदर पिछले ही चुनाव में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से वादा किया था, 10 गारण्टी दी थी।

उन्होंने कहा था कि अगले पांच साल में दिल्ली में दो करोड़ पेड़ पौधे लगाये जायेंगे। मैं सदन को भी बताना चाहता हूँ पांच साल में जो काम का गारंटी दिया था अरविन्द केजरीवाल जी ने 4 साल में दिल्ली में हमने 2 करोड़ पेड़–पौधे लगाकर के कम्पलीट किये हैं। 4 साल में। वो कह रहे थे कोई दो करोड़ बता रहा है कोई 64 लाख बता रहा है, दो करोड़ का हमने लक्ष्य पूरा किया 4 साल में। इस साल एक्सट्रा 64 लाख पौधे लगाने का अभियान दिल्ली के अंदर चल रहा है अध्यक्ष महोदय। अरविन्द केजरीवाल जी की सरकार बनी 20 परसेंट ग्रीनबेल्ट था दिल्ली का, ये हमने नहीं सेंट्रल गवर्मेंट ने सर्वे किया है। 20 परसेंट ग्रीनबेल्ट था आज 23.06 परसेंट ग्रीनबेल्ट हुआ है जिसकी वजह से पोल्यूशन कम हो रहा है। अभी माननीय विधायक जी कह रहे थे केंद्र सरकार की वजह से दिल्ली में इलैक्ट्रिक बसें आ गई। हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, हमारे शर्मा जी कह रहे थे आनन्द विहार, आनन्द विहार, आनन्द विहार अरे केंद्र सरकार की वजह से दिल्ली में दो हजार बस आ गईं और यूपी, हरियाणा में दो भी नहीं आ पाईं, वहां भी पैसा दे देते, वहां भी आ जातीं। सारी आनन्द विहार में, शर्मा जी आपके विधान सभा में आती है एक बार जाना डीपो में सारी डीजल की बसें, बीएस–3, बीएस–4 आ करके पूरा आनन्द विहार को धुंआ–धुंआ करके बैठी हैं। वहां भी इलैक्ट्रिक बस मंगवा दो भाई, आपकी केंद्र में डबल इंजन की सरकार है।

श्री ओम प्रकाश शर्मा: दिल्ली की सरकार भी कुछ करेगी नहीं करेगी?

श्री गोपाल राय: हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं 2000 पूरे देश में अकेली दिल्ली की सरकार है जहां 2000 बसें सड़कों पर चलती हैं। दिल्ली की सरकार ने इलैक्ट्रिक वाहन पॉलिसी बनाई है। तीन लाख से ज्यादा प्राइवेट गाड़ियां दिल्ली की सड़कों पर चलती हैं देश में एक भी राज्य नहीं है जहां पर इतनी गाड़ियां चलती हों। दिल्ली के अंदर सारी पुट पोल्यूटेड इंडस्ट्रीको हमने पीएनजी में चेंज कर दिया। दिल्ली के अंदर थर्मल पावर प्लांट हमने बंद कर दिया। दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली देते हैं जिससे सारा जनरेटर का धुंआ बंद हुआ है, इसलिए पॉल्यूशन कम हो रहा है। अध्यक्ष महोदय मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये 1100 पेड़ जो काटने का अपराध एलजी साहब ने किया है उसको छुपाने के लिए चाहे जितना मर्जी कोशिश कर ले कोई, वो छुपने वाला नहीं है। हमारे माननीय विधायक जी ने कहा कि वाटर तो छिड़क नहीं पा रहे हैं, हैलिकॉप्टर से वर्षा करना चाह रहे हैं। गुनाह कर रहे हैं क्या भई? गुनाह तो नहीं कर रहे। अगर हेलिकोपटर से वर्षा होने से पॉल्यूशन कम हो सकता है तो आप भी मदद करो क्या दिक्कत है। हमने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को एक चिट्ठी लिख दी। पिछली बार आईआईटी कानपुर के लोग आए मुख्यमंत्री जी से मिले। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी देश में ये टेक्नॉलोजी आ गई है। खासतौर से नबम्वर में जब लेयर पैदा हो जाती है तो दुनिया के बहुत सारे देशों

में जो है कृत्रिम वर्षा हुई और उससे वो पॉल्यूशन कम हो गया। मुख्यमंत्री जी ने कहा भाई इसको चैक करो। हमने बुलाया आइटी कानपुर के लोगों ने पूरा प्रजेंटेशन दिया उसके बाद हमने काम शुरू किया, लेकिन अध्यक्ष महोदय उसके लिए केन्द्र सरकार का परमिशन चाहिए। हम तो मिल के काम करना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय। हमने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी को अगस्त में ही चिट्ठी लिखी कि आप क्योंकि पिछले बार हमने मीटिंग बुला ली तो कई लोग नाराज हो गए थे। हमने कहा केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से आप एक मीटिंग बुला लीजिए मैं भी आ जाऊंगा, आईआईटी कानपुर के साइंटिस्ट को भी बुला लेते हैं और जितने डिपार्टमेंट का परमिशन चाहिए उनको बुला लेते हैं। अगर समय से परमिशन हो जायेगा तो इमरजेंसी सिच्युएशन में उसका उपयोग करेंगे। भाजपा के नेता सारे नाराज हो गए। कह रहे हैं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को चिट्ठी क्यों लिख रहे हो। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को चिट्ठी क्यों लिख रहे हो। अरे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को अगर दिल्ली का पर्यावरण मंत्री चिट्ठी नहीं लिख सकता है तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री बना किस लिए है, बना किस लिए है भाई? अगर राज्य का पर्यावरण मंत्री केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को चिट्ठी नहीं लिखेगा तो किसको लिखेगा और किस लिए लिखा था मैंने, मदद मांगने के लिए लिखा था। अभी उन्होंने कहा कि हमने ईस्टर्नल वेस्टर्नल पेरिफेरियल बनाया उससे पोल्यूशन कम हुआ, हम सम्मान के साथ उसको स्वीकार करते हैं। हर जगह कहते हैं कि दिल्ली का जो पोल्यूशन कम हुआ है उसमें जो बेवजह गाड़ियां दिल्ली में आती थीं उसको कम करने में केंद्र सरकार ने एक

बड़ा काम किया, जिसकी वजह से दिल्ली को मदद मिली। लेकिन इससे बाकी जिम्मेदारी खत्म तो नहीं हो जाती। हम तो सहयोग ही मांग रहे हैं, दिल्ली के लिए मांग रहे हैं। आप कह रहे हो, अरे हमने इस बार जिस दिन हमने चिट्ठी लिखी अध्यक्ष महोदय भाजपा के अध्यक्ष बोले कैसे चिट्ठी लिख सकते हो। कांग्रेस के भी बोले। मैंने एक चिट्ठी लिखी हम विन्टर एक्शन प्लान बना रहे हैं आपके पास जो भी सुझाव है दिल्ली सरकार करेगी, अपना सुझाव दे दो। सदन को बताना चाहता हूँ ये भाजपा, कांग्रेस के नेता जो हैं बयान बहुत करते हैं। कल विंटर एक्शन प्लान लाँच भी हो गया, भाजपा कांग्रेस के नेताओं के पास एक भी सुझाव नहीं था जो मेरे पास भेज दें। एक भी जवाब नहीं आया। एक भी जवाब नहीं आया कि ये काम कर दे सरकार। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आखिर में केवल इतनी बात कहना चाहता हूँ दिल्ली के लोगों ने प्रचंड बहुमत से दिल्ली में अरविन्द केजरीवाल जी की सरकार बनाई और अरविन्द केजरीवाल जी ने भी प्रचंड तरीके से दिल्ली में वो काम किये जो हिन्दुस्तान के इतिहास में आज तक कोई हुकुमत नहीं कर पाई। वही काम भाजपा के पेट में दर्द पैदा किया। उस काम को रोकने के लिए पहले एलजी साहब को लगाये, काम नहीं रूका। उसके बाद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सतेन्द्र जैन को उठाकर के जेल में डाल दिया सोचे डर जायेंगे, काम रूक जायेगा, काम नहीं रूका। उसके बाद मनीष सिसोदिया जी को उठा के जेल में डाल दिया सोचा काम रूक जायेगा, काम नहीं रूका। उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री को उठाके जेल में डाल दिया। सोचा न रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। यही जड़

है सारे काम का, काम नहीं रूका अध्यक्ष महोदय। ये एक सपना और देख रहे थे कि जैसे महाराष्ट्र के अंदर इन्होंने शिव सेना को तोड़ लिया, ईडी, सीबीआई के दम पर, शरद पवार जी की पार्टी को तोड़ लिया और अपनी सरकार बना दी। ये सोचते थे दिल्ली में भी सारे नेता जेल में जायेंगे, विधायक डर जायेंगे, सरकार गिर जायेगी, पार्टी टूट जायेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के पास ईडी की ताकत है ये सच है, भारतीय जनता पार्टी के पास सीबीआई की ताकत है ये सच है, भाजपा के पास पैसे की ताकत है ये सच है, भाजपा के पास नफरत की ताकत है ये सच है। लेकिन अरविन्द केजरीवाल के साथ दिल्ली के लाखों लोगों की दुआओं की ताकत है, आशीर्वाद की ताकत है। किसी भी कीमत पर ना कल ये आम आदमी पार्टी का बाल बांका कर पाये, ना आगे कर पायेंगे। कल भी हमने काम किया था, आज भी हम काम कर रहे हैं और कल भी हम काम करेंगे। हमें इस बात का अफसोस है दिल्ली का कोई भी एमएलए, कोई भी कार्यकर्ता, दिल्ली का कोई भी नागरिक नहीं चाहता था जेल से आने के बाद अरविन्द केजरीवाल इस्तीफा दें। लेकिन अरविन्द केजरीवाल, अरविन्द केजरीवाल हैं। देश का पहला नेता नहीं दुनिया का पहला नेता है, जब जेल में थे सारा चक्रव्यूह किया था, इस्तीफा दो तो नहीं दिया, देश में पहली बार नहीं दुनिया में जेल से सरकार चलाई और जब जेल से बाहर आ गया तो अपनी मर्जी से सीएम की कुर्सी ठुकराई, अकेला नेता है ये, अकेला नेता। भाजपा के सारे शड़यंत्र भी दिल्ली के लोग देख रहे हैं और अरविन्द केजरीवाल

का त्याग भी दिल्ली के लोग देख रहे हैं। ज्यादा दिन की बात नहीं है। हम तो कह रहे हैं जल्दी चुनाव कराओ। पिछली बार से ज्यादा प्रचंड बहुमत से अरविन्द केजरीवाल दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे ये ही दिल्ली के लोगों की चाहत है। आप सबका बहुत–बहुत शुक्रिया, बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री प्रलाद सिंह साहनी: निगम बोध के अंदर आज भी पीपल के पेड़ जलाकर मुर्दे जलाये जा रहे हैं। मुर्दे जलाये जा रहे हैं पीपल के पेड़ काटकर। निगम बोध के अंदर एक भी पीपल का पेड़ नहीं मिलेगा आने वाले दिनों के अंदर। ये बीजेपी के लोग मिलकर गैरकानून से बीजेपी के लोग..

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: बैठिए साहनी जी, बैठिए प्लीज साहनी जी। साहनी जी बैठिए। विधेयक का पुर:स्थापन अब श्रीमती आतिशी जी, माननीया मुख्यमंत्री दिल्ली माल एवं सेवा कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2024 (वर्ष 2024 का विधेयक संख्या 3) को सदन में introduce करने की परमिशन मांगेंगी।

माननीया मुख्यमंत्री (श्रीमती आतिशी): Hon'ble Speaker Sir I seek the permission of the House to introduce the 'Delhi Goods and Services Tax (Third Amendment) Bill, 2024' (Bill No.03 of 2024) in the House.

माननीय अध्यक्ष: यह प्रस्ताव सदन के सामने है:

जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं वे न कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता,

प्रस्ताव पारित हुआ।

अब माननीया मुख्यमंत्री विधेयकको सदन में introduce करेंगी।

माननीया मुख्यमंत्री: Hon'ble Speaker Sir I introduce the 'Delhi Goods and Services Tax (Third Amendment) Bill, 2024' (Bill No.03 of 2024) in the House.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण आप सबको सूचित किया जाता है कि कल दिनांक 27 सितंबर, 2024 को प्रात: 10:30 बजे केंद्रीय विधान सभा के प्रथम निर्वाचित भारतीय अध्यक्ष श्री विट्ठल भाई पटेल जी की 151 जयंती तथा शहीद भगत सिंह जी की 117 वीं जयंती के अवसर पर विधान सभा परिसर में पुष्पांजली अर्पण कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा। अत: आप सबसे प्रार्थना है 10:30 बजे अवश्य पहुंचे। अब सदन की कार्यवाही शुक्रवार दिनांक 27 सितंबर, 2024 को पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(सदन की कार्यवाही शुक्रवार दिनांक 27 सितंबर, 2024 को पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

© दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 18 (2) के उपबंधों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 281 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकाशित तथा ग्राफिक प्रिंटर्स, 2965 /41, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-110 005 द्वारा मुद्रित।